राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 201

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 29 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रविशंकर बोले– वोटबैंक की राजनीति में उलझा है विपक्ष

>> 4

संडे बॉक्स

'दादा' की अंगुली पकड़ धमाल मचाएगा क्रिकेट का 'वंडर किड'

कोलकाता : विराट कोहली से लेकर केविन पीटरसन तक, बड़े-बड़े क्रिकेटर तीन साल के जिस उस्ताद क्रिकेटर शेख शाहिद की बल्लेबाजी के मुरीद हैं, अब दादा सौरभ गांगुली की क्रिकेट अकादमी उसे विधिवत प्रशिक्षण देकर निखारेगी। (पेज-15)

रविवार विशेष

'कैप्स्यूल गिल' के कारनामे को फिर सलाम करेगी दुनिया...

धनबाद : 1989 में प. बंगाल स्थित कोयला खदान में 220 मजदूर 350 फीट नीचे काम कर रहे थे। अचानक खदान में पानी भर गया। तब आइआइटी आइएसएम के छात्र जेएस गिल ने कैप्स्यूलनुमा लिफ्ट बना 65 मजदूरों को बाहर निकाला। (पेज-15)

आम बजट से लोगों की उम्मीदों पर केंद्रित विशेष सामग्री पेज 7

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

संसद और मुंबई हमले के बाद भी एयरस्ट्राइक को तैयार थी वायुसेना

नई दिल्ली : पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने शनिवार को कहा कि 2001 में संसद पर और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हवाई हमला करने के लिए वायुसेना तैयार थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसकी अनुमति नहीं दी। वह मुंबई में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

कर्मनाशा नदी का पुल क्षतिग्रस्त उप्र का कई राज्यों से संपर्क टूटा

चंदौली : उप्र-बिहार सीमा पर स्थित कर्मनाशा नदी पर 450 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-2 पर बना पुल शुक्रवार देर रात ओवरलोड वाहनों के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के पूर्वी छोर के शुरुआती चार पिलर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे सड़क का ऊपरी हिस्सा धंस गया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सोमालिया में बम धमाके से 90 लोगों की मौत

मोगादिशू : सोमालिया की राजधानी मोगादिशू शनिवार को भीषण बम धमाके से दहल गई। एक व्यस्त सुरक्षा जांच चौकी के पास विस्फोटकों से लदी कार से किए गए धमाके में तुर्की के दो नागरिकों समेत 90 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए।

सर्दी ने ढाया सितम, पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में, कई जगह टूटे रिकॉर्ड

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, घरों में दुबके लोग
- राजस्थान के पांच शहरों में जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा तापमान
- कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित

राजस्थान के सीकर में को तापमान शून्य से नीचे होने पर कार के ऊपर जमी बर्फ। प्रेट्र

शनिवार की सुबह सर्दी का सितम लेकर आई और पूरा उत्तर भारत ठिठुरने लगा। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। इसका जनजीवन पर व्यापक असर दिखा। लोगों ने देर से बिस्तर छोड़ी। सड़कों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलते दिखते। दफ्तरों में लोग विलंब से पहुंचे। पार्क सूने दिखे और स्कूल-कालेजों में उपस्थिति बेहद कम रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। लोकल बसों में यात्री कम दिखे। ठंड से कांपते हुए पहुंचे लोगों को बंद मेट्रो में थोड़ी राहत मिली।

मैदानी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड व राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिसार में छह वर्ष में दूसरी बार न्यूनतम तापमान शून्य से भी नीचे चला गया। राजस्थान के पांच शहरों फतेहपुर, माउंट आबू, जोबनेर, सीकर और चुरू में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे आ गया। फतेहपुर में माइनस चार डिग्री दर्ज किया गया। माउंट आबू में बर्फ की परत जमी हुई है। ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में भी ठंड की स्थिति बनी रही।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने बेहाल कर रखा है। श्रीनगर में तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते डल झील समेत अधिकांश जलस्रोत जम गए हैं। उत्तराखंड के छह शहरों में पारा दो डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, मनाली, सोलन, भुंतर, सुंदरनगर समेत कई जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है।

दिल्ली में टूट सकता है 118 साल का रिकॉर्ड

राजधानी में 118 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 1919, 1929, 1961 और 1997 में ही दिसंबर माह का औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। इस साल 28 दिसंबर तक दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 19 .18 डिग्री सेल्सियस है। दिसंबर 1901 में यह 17 .3 डिग्री सेल्सियस रहा था।

शहर और न्यूनतम तापमान

द्रास	-28.6
कश्मीर	-5.8
जोशीमठ	-1.0
दिल्ली	2.4
रेवाड़ी	1
पंचमढ़ी	1
हिसार	.2
मुजफ्फरनगर	1.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

यह है पूर्वानुमान : मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान महज 2 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह घना कोहरा होगा और दिन में भी जबरदस्त शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। 31 दिसंबर से तापमान में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन साल का अंत और नए साल के प्रारंभ हल्की बारिश से हो सकता है। 1 व 2 जनवरी को ओलावृष्टि की संभावना है।

यह है ठंड बढ़ने की वजह : दिल्ली में कड़ाके की सर्दी की बड़ी वजह बादल बताए जा रहे हैं। बादलों के कारण सूरज की किरणें धरती तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही हैं, जिससे ठंडक कम हो। हालांकि मौसम विभाग इसे जलवायु परिवर्तन के असर से जोड़कर देखने के पक्ष में नहीं है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि ठंड कम या अधिक रहने के पीछे पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता बड़ी वजह है। इस बार हिमालय क्षेत्र में जो भी पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, सभी मजबूत रहे हैं। जनवरी माह में भी इस बार अच्छी खासी ठंड पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है।

कोहरे ने रोका यातायात : कोहरे के चलते दृश्यता बहुत कम होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हैं। 24 ट्रेनें खराब दृश्यता के कारण 2-5 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में दिक्कत आई। दो उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि छह को डायवर्ट कर अन्य एयरपोर्ट पर उतारा गया। 200 से ज्यादा उड़ानों का संचालन देरी से हुआ। कोहरे के कारण हुए हादसों में उप्र में चार, राजस्थान और हरियाणा में दो-दो लोगों की मौत हो गई।

पूस के रात-दिन इसलिए हुए बहुत सर्द पेज>>6

केरल के राज्यपाल से अभद्रता

बदसुलूकी ▶ भारतीय इतिहास कांग्रेस में इरफान हबीब ने आरिफ को बोलने से जबरन रोका

राज्यपाल से चिल्लाकर कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नहीं गोडसे का हवाला दीजिए

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के साथ कन्नूर विश्वविद्यालय में शनिवार को अभद्रता की गई। इसकी जानकारी खुद राज्यपाल ने ट्वीट कर दी। राज्यपाल ने कहा कि जाने-माने इतिहासकार इरफान हबीब ने उन्हें भारतीय इतिहास कांग्रेस (आइएचसी) में बोलने से रोकने की कोशिश की। राज्यपाल ने विरोधी विचार के खिलाफ हबीब के इस 'असहिष्णु' कृत्य को अलोकतांत्रिक बताया। बाद में राज्यपाल ने कार्यक्रम के सीसीटीवी फुटेज के साथ कुलपति गोपीनाथ रविंद्रन को गेस्ट हाउस में तलब किया।

कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के फोटो के साथ एक के बाद एक किए ट्वीट में आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि आइएचसी के दौरान मंच पर और सामने बैठे लोगों की तरफ से उनके भाषण में बार-बार बाधा डाली गई। मुस्लिम समुदाय का उदारवादी चेहरा माने जाने वाले आरिफ मुहम्मद खान ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'इरफान हबीब तो मंच से उठकर उन्हें रोकने के लिए उनके पास तक चले आए, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का हवाला दिया तो हबीब ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें गोडसे का हवाला देना चाहिए।'

राज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि महामहिम के एडीसी और सुरक्षा अधिकारी ने जब हबीब को रोकना चाहा तो उन्होंने उन्हें भी धक्का दे दिया। आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि उनसे पहले अपने संबोधन में इरफान हबीब ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। उनका यह कर्तव्य था कि वह संविधान की रक्षा और सुरक्षा करें। ऐसे में वह सिर्फ इरफान हबीब और पूर्व के वक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मंच पर बैठे हबीब उठकर उनके पास चले आए और उन्हें जबरन चुप कराने की कोशिश की। कार्यक्रम के वीडियो में हबीब की यह हरकत साफ नजर आ रही है। रोक-टोक और शोर-शराबे के बीच राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा, 'आपको विरोध करने का पूरा हक है। लेकिन आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते।'

कन्नूर विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान (बाएं) को बोलने से रोकने की कोशिश करते इतिहासकार इरफान हबीब (दाएं से दूसरे)। ट्विटर

ट्विटर पर यूजर्स ने इरफान हबीब की खबर ली

कोच्चि, आइएएनएस : राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के साथ अभद्रता करने पर ट्विटर पर लोगों ने इतिहासकार इरफान हबीब की जमकर खबर ली। राज्यपाल की तरफ से ट्विटर पर इस संबंध में फोटो और डाला गया तो यूजर हबीब की आलोचना करने लगे। राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट को 2 .7 हजार बार रीट्वीट किया गया, जबकि 3 .5 हजार लाइक मिले। हबीब के बारे में एक यूजर ने लिखा, 'इस व्यक्ति ने अपने चाटुकारों के साथ मिलकर झूठ फैलाने के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़ कर रख दिया और झूठ के आधार पर एक धारणा स्थापित की।' एक यूजर ने लिखा, 'सहिष्णुता की वाम-उदार शैली। ये तब तक उदार हैं जब तक आप उनकी हां में हां मिलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए।'

उपद्रवी सुधरें, वरना कराई जाएगी 'मनचाही यात्रा' : योगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, आगजनी की है, उनसे भरपाई कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। समाज में ऐसे चेहरों को चिह्नित किया जा रहा है जो नकारात्मक तत्व हैं। वे सुधरेंगे तो अच्छी बात है, वरना स्वाभाविक रूप से उन्हें 'मनचाही यात्रा' कराई जाएगी। उन्होंने यह अपील भी की कि जो लोग विदेशी जूठन पर पल कर देश के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके बहकावे में कभी न आएं।

वह शनिवार को गोरखपुर स्थित राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के मैदान में 185 करोड़ की लागत वाली विकास की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नकारात्मक तत्वों के बहकावे में आकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को केवल डिग्री बांटने का केंद्र न बनकर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने का केंद्र बनना चाहिए। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जहां देश की जनता के टैक्स के बल पर कुछ लोग पलते हैं और देश के विरोध में ही नारेबाजी करते हैं, देशहित में बनने वाले कानूनों का विरोध करते हैं।

योगी ने कहा कि सरकार जनसहयोग से विकास कार्य में लगी रहती है। स्कूल, कॉलेज बनवाए जाते हैं, अस्पताल बनवाए जाते हैं, यातायात के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इन पर खर्च होने वाला धन किसी की जेब से नहीं आता बल्कि जनता का होता है। किसी के बहकावे में आकर कोई इन्हें क्षति पहुंचाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चिदंबरम बोले, अपने काम से मतलब रखें जनरल रावत पेज>>4

उत्तर प्रदेश में हालात हुए सामान्य, इंटरनेट सेवा बहाल पेज>>5

राहुल गांधी ने कहा-असम को नागपुर और आरएसएस वाले नहीं चलाएंगे

गुवाहाटी, प्रेट्र : कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को देशभर में 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' रैली निकाली। असम में इस रैली की कमान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली। इस दौरान राहुल जमकर केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को नागपुर में बैठकर असम के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गुवाहाटी में राहुल ने कहा, 'हम भाजपा, आरएसएस वालों को असम की संस्कृति, भाषा एवं पहचान पर हमला नहीं करने देंगे। आरएसएस और नागपुर असम को संचालित नहीं कर सकते और न ही हमला कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे पूर्वोत्तर की भाषा व पहचान को कुचल देंगे, तब उन्होंने अब तक आपको पहचाना ही नहीं।' कांग्रेस नेता बोले, 'मुझे डर है कि भाजपा की नीतियों के कारण राज्य फिर हिंसा की राह पर लौट सकता है। असम में कड़े संघर्ष के बाद शांति आई है। असम समझौता इस शांति की नींव है। इसलिए असम समझौते की मूलभावना खत्म नहीं होनी चाहिए।'

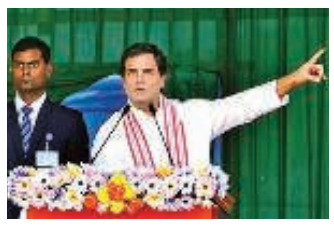

असम के गुवाहाटी में शनिवार को रैली को संबोधित करते राहुल गांधी। एएनआइ

पुलिस ने की मुझसे मारपीट, गला दबाया : प्रियंका

लखनऊ : प्रियंका वाड्रा ने शनिवार को लखनऊ में बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि पुलिस ने उनसे मारपीट की और गला दबाया। दरअसल, पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद कार्यालय से गुपचुप निकल कर कुछ पदाधिकारियों के साथ वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गिरफ्तार किए गए रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने लगीं। पुलिस ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोक दी। इससे बिफरीं प्रियंका पैदल ही चल पड़ीं। (विस्तृत खबर पेज-5 पर)

असम से सीखा भाईचारा पेज>>5

बैंकों के सही फैसलों को संरक्षण देगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री ने कहा - कंपनियों को तीन 'सी' से डरने की जरूरत नहीं
- सीबीआइ भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नोटिस भेजेगी

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों को गलतियों की चिंता से मुक्त होकर खुलकर निर्णय लेने का संदेश दिया था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में इसी संदेश को दोहराया है। वित्त मंत्री ने शनिवार को बैठक में कहा कि ईमानदार बैंक अधिकारियों के सही वाणिज्यिक निर्णयों को सरकार संरक्षण देगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि तीन 'सी' यानी सीबीआइ, सीवीसी और सीएजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।

वित्त मंत्री ने इस बात का भरोसा भी दिया कि सरकार ने यह निर्णय बैंक अधिकारियों को जांच एजेंसियों की तरफ से होने वाली परेशानी से बचाने की दिशा में लिया है। बैठक में सीबीआइ निदेशक भी शामिल थे। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलत हुआ निर्णय वाणिज्यिक तौर पर सही था या जान-बूझकर ऐसा किया गया। सीतारमण ने कहा कि बैंक वर्तमान में चिंता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। जांच एजेंसियों की तरफ से होने वाली संभावित परेशानी की चिंता में बैंक सही निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं।

आमतौर पर बैंकों में सीबीआइ, सीएजी और सीवीसी को 3-सी के नाम से जाना जाता है। बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि बैंक अधिकारियों की इस चिंता को देखते हुए ही सीबीआइ निदेशक की उपस्थिति में पूरी चर्चा की गई। अब सीबीआइ बैंक अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित कर वार्ता को आगे बढ़ाएगी। ऐसे आयोजनों में बैंकों के विजिलेंस अधिकारी, सीनियर मैनेजर से लेकर जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सीबीआइ निदेशक ने बैंक अधिकारियों की कुछ शंकाओं और भ्रम का निराकरण भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आगे चलकर अन्य जांच एजेंसियों मसलन ईडी, डीआरआइ और कस्टम्स अधिकारियों के साथ बैंक अफसरों की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे विजिलेंस संबंधी लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें। उन्होंने बैंकों को महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पैनल गठित करने को भी कहा जो ऐसे मामलों में फैसला कर सकें। बैठक में यह भी तय हुआ कि सीबीआइ भी इनकम टैक्स विभाग की भांति ऐसी व्यवस्था कायम करेगी जिसमें किसी अधिकारी को भेजे जाने वाले नोटिस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो। गौरतलब है कि अब आयकर विभाग की तरफ से किसी भी करदाता को कोई ऐसा नोटिस नहीं भेजा जा सकता जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो।

मुकाबला

ओलंपिक क्वालीफायर खेलने के लिए कराए गए ट्रायल में 9-1 से जीती मेरी कॉम, जीत के बाद जरीन से मेरी कॉम ने नहीं मिलाया हाथ

ट्रायल की लड़ाई जीतीं सुपर मॉम, टूटा निखत का ख्वाब

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम (51 किग्रा) ने शनिवार को यहां निखत जरीन को 9-1 से हराकर चीन में अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई। इस मुकाबले में 36 साल की मेरी कॉम ने बहुत दमदार मुक्के जमाकर स्पष्ट अंक हासिल किए और टीम में जगह सुनिश्चित की, लेकिन बॉक्सिंग हॉल के अंदर माहौल तनावपूर्ण रहा। मैच के दौरान निखत के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन हुआ तो मैच के बाद मेरी कॉम अपनी विपक्षी मुक्केबाज से हाथ मिलाए बिना रिंग से उतर गईं।

मुकाबले के दौरान और रिंग के बाहर दोनों मुक्केबाजों के बीच बहस भी हुई। जब नतीजा घोषित किया गया तो निखत के घरेलू राज्य तेलंगाना मुक्केबाजी संघ के कुछ प्रतिनिधि इसका विरोध करने लगे। मेरी कॉम ने मुकाबले के बाद कहा, 'मैं थोड़ी नाराज थी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सब कुछ हो गया है। मैं आगे बढ़ गई हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बोलने से पहले प्रदर्शन करो, उससे पहले नहीं बोलो। आप रिंग में जो करते हो, उसे हर कोई देख सकता है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी आहत होती हूं। क्या मैं तब गुस्सा भी नहीं हो सकती, जब मेरे कौशल पर सवाल उठाया जाए। यह पहली बार नहीं हुआ है। सच्चाई यही है कि मैं उस स्तर की मुक्केबाज हूं जिस स्तर पर कोई अन्य मुक्केबाज नहीं पहुंच सका है।' ओलंपिक क्वालीफायर चीन में तीन से 14 फरवरी तक कराए जाएंगे।

मुकाबले के बाद मेरी कॉम ने खेल भावना नहीं दिखाई और निखत से हाथ भी नहीं मिलाया। इसके साथ जब निखत के गले लगाने की कोशिश की तो मेरी कॉम ने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में पूछने पर मेरी कॉम ने कहा, 'हमारे खेल में इसे पकड़ना बोला जाता है। मैंने यह विवाद खड़ा नहीं किया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं ट्रायल के लिए नहीं आऊंगी। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जब कोई आरोप लगाएगा कि यह मेरी गलती थी। यह मेरी गलती नहीं थी और मेरा नाम इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए।'

मैच के दौरान महिला मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम (बाएं) और निखत जरीन। प्रेट्र

आहत हुईं निखत पेज>>6

यह थी विवाद की असल जड़

रूस में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में मेरी कॉम ने 51 किग्रा में कांस्य जीता था। इस जीत के बाद अजय सिंह ने मेरी कॉम को ओलंपिक क्वालीफायर में सीधे भेजने की बात कही थी जो बाई के नियमों के उलट थी। बाई के नियमों के मुताबिक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण या रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को ही ओलंपिक क्वालीफायर के लिए सीधे प्रवेश मिलेगा और जिस भारवर्ग में भारत की मुक्केबाज फाइनल में नहीं पहुंची हैं उस भारवर्ग में ट्रायल होगा। निखत ने इसका विरोध किया और कहा कि ट्रायल के आधार ही क्वालीफायर के लिए चयन होना चाहिए। निखत की मेहनत रंग लाई और बाई अपने पुराने नियमों पर लौट ट्रायल्स आयोजित कराने पर राजी हो गया।

हाई कोर्ट के कर्मचारियों से 104 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हाई कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन सहित तीन के खिलाफ 104 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट के लिए कंपनी ने इन लोगों से रुपये तो ले लिए, लेकिन आठ साल बाद निर्माण कार्य भी यहां शुरू नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी फ्लैट के निर्माण के लिए दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनियों से संपर्क कर रहे थे। इसी बीच इन लोगों से ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी अंतरिक्ष इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राकेश यादव, एमडी दीपांशु राव और मैनेजर बिशन गुलाटी ने संपर्क किया। इन लोगों ने उन्हें ग्रेटर नोएडा सेक्टर-1 में अंतरिक्ष गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट देने का वादा किया था। इसके तहत आठ टावर बनाए जाने का दावा कंपनी ने किया। इसके लिए दिसंबर 2011 में कंपनी ने लिखित समझौता किया कि रुपये के भुगतान के बाद अधिकतम 36 महीने फ्लैट सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इस पर हाई कोर्ट के कर्मियों ने 86 फ्लैट के लिए 16 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा करा दिए। वहीं, इस कंपनी के अन्य प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट के लिए कर्मियों के परिवार, एनटीपीसी सहित अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने भी 104 करोड़ की लागत के फ्लैट बुक करा दिए। लेकिन, कंपनी का काम कछुआ की गति से शुरू हुआ। स्थिति यह है कि वर्तमान में हाई कोर्ट के कर्मियों के लिए तय छह टावर का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है।

40 फीसद अपराध में कमी आई है दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के बाद। यह दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। कहा, बसों में 13 हजार मार्शल तैनात करने के बाद महिलाएं सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हुई हैं।

'10 फीसद वादे भी पूरा नहीं कर पाए केजरीवाल'

वार ▶ भाजपा ने दिल्ली सरकार के पांच साल के कार्यकाल पर जारी किया 'जनता का आरोप पत्र'

डॉ. हर्षवर्धन बोले, झूठ और विश्वासघात के पर्याय बन गए हैं मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के द्वारा गत चुनाव में किए गए वादों पर विफल बताते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'जनता का आरोपपत्र' जारी किया। इस दौरान 'उसने 70 किए थे वादे-पूरे न हुए आधे' का नारा भी लांच किया। साथ ही कहा कि केजरीवाल सरकार अपने पांच साल के रिपोर्ट कार्ड में 10 फीसद भी काम नहीं कर पाई। मनोज तिवारी के साथ मौजूद भाजपा सांसदों ने यह आरोप पत्र जारी किया। पार्टी इसे हर विधानसभा क्षेत्र में घर-घर ले जाएगी।

मनोज तिवारी ने कहा कि पांच साल में केजरीवाल के 70 वादों की बात करें तो आम आदमी कहेगा कि उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इनकी पूरी पड़ताल करेंगे तो देखेंगे कि जहां इन्होंने कहा था कि ये हर घर दीया जलाएंगे, तो सच्चाई ये है कि हर घर में आग लगाएंगे। अब तो दिल्ली एक ही बात कह रही है 70 किए वादे पूरे हुए न आधे, आप तो 10 फीसद से भी नहीं हो

कनांट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में दिल्ली भाजपा की ओर से आयोजित दिल्ली सरकार पर जनता का आरोप पत्र जारी करते (बाएं से) सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल और सांसद रमेश बिधूड़ी। संजय

सके पास, किया दिल्ली के साथ 91 फीसद विश्वासघात।

केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए बनी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ और विश्वासघात के पर्याय बन गए हैं। लोकपाल आंदोलन करने वाले ने अपनी पार्टी से आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटा दिया। इतना ही नहीं, जनलोकपाल विधेयक और स्वराज के तहत मोहल्ला सभाओं को मजबूत करने की बात कही थी वह आज कहां है किसी को नहीं पता।

राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने गंदे पानी और वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया तो सांसद रमेश बिधूड़ी व प्रवेश वर्मा ने गांव-देहात की समस्याओं को पूरा न करने आरोप लगाया। मीनाक्षी लेखी ने वादे न पूरा करने पर वेबसाइट से चंदे और घोषणा पत्र हटाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जब भी देश की बात हुई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी अक्सर अराजक शक्तियों के साथ खड़ी दिखाई दी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरी तो कन्हैया कुमार और उमर खालिद को बचाने के लिए अभी तक एनओसी नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनपर गरीबों को मकान न देने का आरोप लगाया।

आरोप पत्र में किस मुद्दे पर क्या लगाए आरोप

- **पानी** : वादा था कि पांच साल में हर घर को नल से पानी मिलेगा, लेकिन पांच साल बाद सच यह है कि देश के 21 शहरों से भी गंदा पानी दिल्ली वालों को मिलता है।
- हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां गंदे पानी की वजह से बच्चों को बीमार कर रही हैं।
- गंदे पानी की 1.65 लाख शिकायतें आई हैं, छह लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए हैं।
- आरटीआइ के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल के जल बोर्ड का कार्यभार संभालने पर जल बोर्ड 800 करोड़ के घाटे में चला गया है।
- **अनधिकृत कॉलोनी** : वादा था अनधिकृत कालोनियों को पक्का किया जाएगा। पांच साल में एक भी नक्शा पास नहीं किया।
- केंद्र सरकार ने इसका बिल संसद से पास किया और लोगों को मालिकाना हक दिया।
- गरीबों को सस्ते मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया
- 52 हजार फ्लैट गरीबों के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनका आवंटन अभी तक नहीं किया, बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए।
- **शिक्षा** : तमाशा और घोषणाएं तो बहुत हुए हैं, लेकिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम से लेकर शिक्षकों की भर्ती में स्थिति पहले से खराब हुई है। 20 नए कॉलेज बनाने की बात थी। एक भी नया कॉलेज नहीं बना।
- 500 स्कूल बनाने की बात थी। एक भी नया स्कूल नहीं बना।
- अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा, एक भी शिक्षक स्थायी नहीं हुआ।
- **स्वास्थ्य** : अस्पतालों में 30 हजार बिस्तर बढ़ाने की बात थी और चार हजार प्रसूति वार्डों में बिस्तर बढ़ाने की बात थी, लेकिन 200 बिस्तर कम हो गए।
- गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की।
- 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का वादा किया था, दिखावे के लिए थोड़े खोले और वे भी खराब स्थिति में हैं।
- एक भी नया अस्पताल नहीं खोला।
- **प्रदूषण** : प्रदूषण न रोकने से एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगाया।
- इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात थी और एयर प्यूरिफायर लगाने के सपने दिखाए गए, लेकिन वे कहा गए?
- स्वच्छता की जिम्मेदारी निगमों की है, पर निगमों का दस हजार करोड़ का फंड रोक लिया।
- परिवहन व्यवस्था चरमराई है, पर्याप्त बसें नहीं आईं।

कंपकंपाती ठंड में सियासत को आंच देगी कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▶ अनधिकृत कॉलोनियों और विकास के तमाम मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे भूख हड़ताल

▶ नववर्ष की पूर्वसंध्या पर होगा सांकेतिक विरोध, नारा होगा-दिल्ली का हाल ऐसा तो जश्न कैसा?

विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जल्द ही होने की संभावना के बीच दिल्ली में सियासी सरगर्मियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। भाजपा एवं आप तो एक दूसरे पर लगातार हमलावर चल ही रही हैं, अब कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबले का आधार बनाने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आप के रिपोर्ट कार्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के बाद अब पार्टी दिल्ली के सभी मुद्दों को लेकर कंपकंपाती ठंड में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है।

प्रदेश इकाई इस मुद्दे को हर विधानसभा क्षेत्र तक लेकर जाना चाहती है कि बीते पांच साल में दिल्ली का विकास ठहर गया है। किसी भी क्षेत्र में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। इसे लेकर पूरा अभियान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पार्टी के प्रचार रथ भी हर विधानसभा क्षेत्र में घूमते नजर आएंगे। इनके माध्यम से दिल्लीवासियों को बताया जाएगा कि शीला दीक्षित सरकार के 15 साल में दिल्ली का कितना विकास हुआ और अब आप सरकार के कार्यकाल में किस तरह केवल दावे किए गए हैं जबकि हकीकत जीरो है।

सूत्र बताते हैं कि पार्टी पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली की बदहाली को मुद्दा बनाते हुए ही हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड के बीच सड़क पर उतरने की रणनीति भी बनाई गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता नववर्ष के जश्न पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए सड़क पर भूख हड़ताल करेंगे। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के आसपास कहीं यह भूख हड़ताल नए साल की पूर्व संध्या पर करने की योजना है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता रात भर सड़क पर बैठेंगे और सवाल उठाएंगे कि अनधिकृत कॉलोनियों एवं विकास के मुददे पर कोरी राजनीति क्यों? आखिर कब तक राजधानी की जनता को गुमराह किया जाता रहेगा?

> दिल्ली में पिछले पांच साल से आप सरकार राज कर रही है। लेकिन इस सरकार की एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे राजधानी को गति मिली हो। किसी भी योजना का बजट तक पूरा खर्च नहीं किया जा सका। केवल मुफ्तखोरी की घोषणाएं कर दोबारा सत्ता हासिल करने की तैयारी चल रही है। इसीलिए हमें दिल्ली की जनता से सहानुभूति है और हम दिल्ली की बदहाली को लेकर चिंतित भी हैं। हमारी यह भूख हड़ताल इसी स्थिति का प्रतीकात्मक विरोध होगा।
>
> **-सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस**

न्यूज गैलरी

पुलिस ने सपना चौधरी को भेजा नोटिस

गुरुग्राम : गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के नजदीक 25 दिसंबर की रात हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को नोटिस जारी किया है। कार सपना के नाम पर है। सदर थाना प्रभारी बसंत कुमार ने बताया कि रात 12 बजे सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक की तरफ एक कैंटर जा रहा था। पीछे से फॉर्च्यूनर कार अचानक आगे निकली। कुछ ही दूरी पर कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे कैंटर उसमें टकरा गया। हादसे की वजह से कार एवं कैंटर को दोनों को नुकसान हुआ। कार में दो युवक थे। 27 दिसंबर की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में बिहार के भागलपुर निवासी कैंटर चालक अमर ने हादसे की सूचना दी। जानकारी मिली है कि हादसे को लेकर कार चालक की तरफ से कैंटर चालक को दोषी ठहराया जा रहा है। इसे देखते हुए दोनों पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। (जासं)

चुनाव से पहले कन्हैया की फाइल साइन करें सीएम : सिंह

नई दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राष्ट्रहित में जेएनयू मामले में आरोपित कन्हैया कुमार की फाइल साइन करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि सीएम के साइन के बाद ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर पाएगी। दिल्ली के लोगों ने अन्ना हजारे की राष्ट्रवादी छवि के चलते केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे में सीएम को चाहिए कि राष्ट्रहित के विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर देखें। उन्होंने कहा कि सीएम चाहें तो नागरिकता संशोधन कानून पर राजनीति कर लें, लेकिन देश हित में टुकड़े-टुकड़े गैंग की फाइल रोककर बहुत अहित करेंगे। (जासं)

चुनावी मौसम में किए जा रहे फर्जी शिलान्यास : यादव

नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एवं बादली से पूर्व विधायक देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार को फर्जीवाल सरकार की संज्ञा दी है। शनिवार को जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने बादली में एक ऐसे अस्पताल का शिलान्यास करने का एलान किया है, जिसका न नक्शा पास हुआ है, न टेंडर किसी कंपनी को अलॉट हुआ है, न ही किसी महकमे से कोई एनओसी जारी हुई है। (जासं)

राजधानी में जल्द खत्म होंगे 2,768 डॉर्क स्पॉट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

महिला सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माने जाने वाले 2,768 डार्क स्पॉट अब जल्द ही खत्म होंगे। योजना के तहत संबंधित कंपनी को काम दिया भी जा चुका है। इस पर काम इसी सप्ताह शुरू होने जा रहा है।

राजधानी में कितने डार्क स्पॉट हैं, सेफ्टी पिन ने इसकी पहचान 2016 में भी की थी। उस समय 7,438 डार्क स्पॉट की रिपोर्ट सेफ्टी पिन ने सरकार को दी थी। उस समय 7,438 डार्क स्पॉट को समाप्त कर दिया गया था। अब नए सिरे से कराए गए सर्वे में 2,768 नए डार्क स्पॉट की पहचान की गई है। ये डार्क स्पॉट अलीपुर-नरेला रोड, जीटी कैनाल रोड, कंझावला रोड, निजामपुर रोड, बीएल भारद्वाज चैरिटेबल हॉस्पिटल रोड, पीवीसी मार्केट रोड टिकरी कलां, संत नगर मार्ग, मेन मंडोली मार्ग, पुस्ता रोड, नाला रोड, खादर कालिंदी कुंज रोड, जैतपुर कालिंदी कुंज रोड, मेन रोड आली गांव, शूटिंग रेंज रोड, बाबू जगजीवन रोड, सीआरबी मार्ग, डेरा गांव रोड, बक्करवाला रोड, नजफगढ़-बहादुरगढ़ रोड, फिरनी रोड आदि में शामिल हैं।

महिला सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली भर में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2 लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना है। इसी योजना के तहत 2,768 डॉर्क स्पॉट भी रोशन किए जाएंगे। सेफ्टी पिन ने वर्ष 2018 से 2019 के बीच नए सिरे से डार्क स्पॉट की पहचान करने का काम शुरू किया था। इसके तहत गलियों, सड़कों, ट्रांसपोर्ट हब, बाजारों, सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक पार्कों एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर डार्क स्पॉट की पहचान करने के लिए सर्वे का काम किया गया। लाइटों को लगाने की जिम्मेदारी तीनों बिजली कंपनियों को दी गई है। प्रत्येक डिस्कॉम 70 हजार स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

'भाजपा ने निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगर निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। यदि भवन विभाग को निगमों से अलग कर दिया जाए तो भाजपा के आधे से ज्यादा निगम पार्षद चुनाव लड़ने से इन्कार कर देंगे। इतना ही नहीं भाजपा के पार्षद और उनके लोग रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली तक करते हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारी सड़कें और नालियां ऐसी हैं जो भाजपा शासित निगमों के अधीन आती हैं। परंतु पिछले कई वर्षों से भाजपा ने एक भी सड़क या नाली बनवाने का काम नहीं किया है। दिल्ली सरकार ने निगमों की सड़कों और नालियों को विधायक कोष और मुख्यमंत्री कोष द्वारा बनवाने का काम किया है। दिल्ली के बाजारों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी निगमों की थी, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी ने पैसा खाकर बाजारों को अव्यवस्थित ढंग से चलने दिया और आज सभी व्यापारियों की गर्दन पर नगर निगमों ने सीलिंग की तलवार लटका रखी है। भाजपा ने स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया।

उन्होंने कहा कि आप सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो अपने पांच साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर घर-घर जा रही है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि वह भी अपने 12 साल का निगम के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करे और जनता के बीच लेकर जाए। यदि भाजपा ने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया तो उसमें केवल पैसा वसूली और भ्रष्टाचार सामने आएगा।

उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि नगर निगमों के स्कूलों से जो बच्चे पांचवीं पास कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा छह में आते हैं, वे फिर से कक्षा दो की किताब से पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वे दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं। भाजपा दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा शासित निगमों के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों का हाल खराब है। सफाई जो उनका मुख्य काम है, उसका भी बुरा हाल है। भाजपा के सभी लोग केवल और केवल पैसा उगाही के काम में लगे हुए हैं।

भाजपा नेता विजय गोयल के एनआरसी और सीएए को लेकर भड़की हिंसा पर आप को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के पास न कोई मुद्दा है, न कोई नेता है इसलिए वह इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस द्वारा आप की सरकार से भी सस्ती बिजली दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर सिसोदिया ने कहा कि दोनों पार्टियों की दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वहां पहली सस्ती करा लें, फिर दिल्ली की बात करें।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

भाजपा के आरोप पर केजरीवाल ने कहा, निंदक नियरे राखिए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा के आरोपपत्र पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयमित तरीके से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सिखाती है कि निंदा करने वालों को अपने आसपास ही रखिए। भाजपा ने आरोपपत्र में जो आरोप हमारी सरकार पर लगाए हैं, हम उस आरोप पत्र को पढ़ेंगे। जो भी अच्छे सुझाव हैं, उन्हें अगले पांच साल में लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे काम की कड़ी समीक्षा करें और हमारी कमियां निकालें। सुझाव दें ताकि हम और अच्छा काम कर सकें।

केजरीवाल बोले, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला देश करता है तरक्की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ वजीरपुर में मुख्यमंत्री ने किया वृद्धाश्रम का शुभारंभ

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वजीरपुर गांव स्थित समाज कल्याण विभाग की ओर से निर्मित ज्योतिबा फूले स्मारक वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में अगर हम माता-पिता को साथ नहीं रख सकते हैं, तो हम से बुरा इंसान कोई नहीं है। मां-बाप हमें पालने में बड़ा कष्ट उठाते हैं। वे पेट काटकर हमें रोटी देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं और हम हैं कि बुढ़ापे में उन्हें छोड़े देते हैं। जो देश और समाज बुजुर्गों का सम्मान करता है, वही तरक्की करता है। यही हमारे देश की संस्कृति भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली सरकार है, जिसने बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम किया। आज यहां वृद्धाश्रम की शुरुआत हो रही है। यहां 36 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है। उनके मनोरंजन, खाने और रहने की सभी सुविधाएं हैं। आज इसे शुरू करते हुए खुशी भी है और दुख भी। बुजुर्ग अपने बच्चे व परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं या उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार और वृद्धाश्रम खोलने जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमें माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें साथ रखना चाहिए। मैं अपने माता-पिता के साथ रहता हूं। शाम में जब उनके साथ कुछ समय बिताता हूं तो दिन भर की थकान मिट जाती है। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा रही है। बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ देने की परंपरा अमेरिका जैसे देशों की रही है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वह समय निकालकर वृद्धाश्रम में आएं और बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम ऐसी योजना तैयार करेंगे, जिससे लोग बुजुर्गों से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, जिसमें हम उन्हें 12 तीर्थ स्थानों पर लेकर जाते हैं। इस योजना का अब तक 40 हजार बुजुर्ग लाभ ले चुके हैं।

अभी सात जगहों पर और बनाये जा रहे वृद्धाश्रम : समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जिनके घर में मां-बाप खुश रहते हैं, वहां वृद्धि होती है। गांधी नगर और कांति नगर में वृद्धा आश्रम बनकर तैयार हैं। सात स्थानों पर वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम यह सब काम कर रहे हैं।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है वृद्धाश्रम : कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के सचिव मधुप व्यास ने बताया कि यह वृद्धाश्रम करीब 600 वर्ग मीटर में चार मंजिला बना हुआ है। इसमें 36 वरिष्ठ नागरिकों के रहने की जगह है। यहां पर आधुनिक सुविधाएं होंगी। मेडिकल की सुविधा, डाइनिंग, किचन आदि हैं। वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन की भी सुविधा है। सुविधाएं मुफ्त हैं। चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार, गीता कॉलोनी, छतरपुर, जनकपुरी, सरिता विहार और वसंत कुंज में भी वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं।

एम्स में अगले माह तैयार हो जाएगा सर्जिकल ब्लॉक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स में नवनिर्मित सर्जिकल ब्लॉक में अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर (ओटी) बनाने का काम अगले माह पूरा हो जाएगा। इसके बाद सर्जिकल ब्लॉक संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही अगले माह नए ओपीडी ब्लॉक को भी शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद अगले कुछ माह में सर्जिकल ब्लॉक में भी इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे एम्स में सर्जरी के लिए महीनों इंतजार करने वाले मरीजों को राहत मिलेगी।

एम्स में प्रतिदिन करीब 13 हजार लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से संस्थान में मरीजों का भारी दबाव है। मरीजों को सर्जरी के लिए लंबी तारीख दी जाती हैं। किडनी खराब होने की बीमारी से पीड़ित मरीजों को एक साल तक प्रत्यारोपण के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके मद्देनजर एम्स के विस्तार की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले फरवरी 2014 में एम्स में सर्जिकल ब्लॉक और मातृ-शिशु ब्लॉक का निर्माण शुरू किया गया था। सर्जिकल ब्लॉक की क्षमता 200 बेड की होगी। इसमें वर्ष 2016 में चिकित्सा सुविधा शुरू करने का लक्ष्य था। लंबे समय से इसका भवन बनकर तैयार भी है, फिर भी इसे शुरू नहीं किया जा सका है। इस ब्लॉक में 12 ओटी की सुविधा होगी। पहले इसमें साधारण ओटी बनाया गया था। इसमें कई और खामियां पाई गई थीं, जिससे डॉक्टर खुश नहीं थे। इसके बाद एम्स ने मॉड्यूलर ओटी बनाने का फैसला किया। इसमें देरी के कारण सर्जिकल ब्लॉक को अब तक शुरू नहीं किया जा सका। परियोजना से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि 26 जनवरी तक मॉड्यूलर ओटी तैयार हो जाएंगे। इस ब्लॉक के लिए चिकित्सा उपकरण भी खरीदे जा चुके हैं। इसलिए जनवरी के बाद सर्जिकल ब्लॉक शुरू होने की उम्मीद है।

सर्जिकल ब्लॉक के नजदीक ही ओपीडी ब्लॉक का निर्माण किया गया है। इसे अगस्त में ही शुरू करने का लक्ष्य था, लेकिन तकनीकी कारणों से उस वक्त इसमें इलाज शुरू नहीं हो सका। इस ब्लॉक के अंदरूनी हिस्से में कुछ बदलाव किया जा रहा है। यह काम भी अगले माह पूरा हो जाएगा। फायर विभाग व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) से इस ब्लॉक को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल चुका है।

रिपोर्ट कार्ड को हथियार बना कर आप जा रही जनता के द्वार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) पांच साल में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर ही अपनी जमीन मजबूत कर रही है। पार्टी की रणनीति है कि इस रिपोर्ट कार्ड को हर घर तक पहुंचाया जाए। यदि किसी का कोई सुझाव या शिकायत भी होगी तो उसे भी कार्यकर्ता सुनेंगे उसे नोट करेंगे। उस सुझाव व शिकायत को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे।

इसके लिए 26 दिसंबर से डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान दिल्ली भर में चल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से 10 उपलब्धियों को शामिल किया गया है। कार्यकर्ता पार्टी द्वारा जारी किया गया स्टीकर भी लगा रहे हैं। जिस पर लिखा है अच्छे बीते पांच साल और लगे रहो केजरीवाल। मगर पार्टी की ओर से यह स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि जिस किसी के द्वार पर स्टीकर लगाएं तो उनसे अनुमति जरूर लें। सूत्रों का कहना है कि अभियान को काफी सराहना मिल रही है। लोग खास कर बिजली बिल मुफ्त योजना पर बात कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाने पर तमाम लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनका बिजली का बिल नहीं आया है। दिल्ली भर में ऐसे परिवारों की संख्या 32 लाख बताई जा रही है।

अध्ययन

सफर की नई शोध रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों से 41 फीसद प्रदूषण होता है जबकि बाइक से 14 और स्कूटर से 10 फीसद तक फैलता है हवा में जहर

दिल्ली में 24 फीसद प्रदूषण की वजह बाइक और स्कूटर

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अध्ययनों में यह तो पहले ही साबित हो चुका है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक 41 फीसद तक योगदान वाहनों के धुएं का है। इसमें भी व्यावसायिक वाहनों और ट्रकों के धुएं को इसकी बड़ी वजह बताया जाता रहा है। इसी बीच अब नई रिपोर्ट यह है कि 41 में से 24 फीसद प्रदूषण दोपहिया वाहनों का है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफर इंडिया की शोध रिपोर्ट के मुताबिक ट्रकों का प्रवेश 85 फीसद घट जाने के बाद अब दिल्ली में एक-चौथाई प्रदूषण की वजह बाइक और स्कूटर सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 24 फीसद प्रदूषण की वजह दोपहिया वाहन ही हैं। इसमें भी बाइक की वजह से 14 फीसद और स्कूटरों की वजह से 10 फीसद प्रदूषण होता है। ट्रक और बसों की हिस्सेदारी इस प्रदूषण में 20-20 फीसद रह गई है। ऑटो और कारें भी राजधानी को काफी प्रदूषित कर रही हैं। सफर के निदेशक डॉ. गुफरान बेग के अनुसार, दिल्ली में स्कूटर और बाइक से ज्यादा प्रदूषण होने का कारण उनका ठीक से रखरखाव नहीं किया जाना है। बेग का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं, वैसा ही कुछ निर्णय दोपहिया वाहनों के मामले में भी किया जाना जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा कि बाइक-स्कूटर पेट्रोल से दौड़ते हैं इसीलिए इनसे कम प्रदूषण होता है जबकि व्यावसायिक वाहन डीजल से चलते हैं और अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन नई शोध रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2015 के बाद से राजधानी में वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 में लगातार कमी हो रही है। हालांकि अब भी यह तय मानकों से काफी अधिक है। 2010 में पीएम 2.5 का औसत स्तर 111 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा था, जो 2018 में घटकर 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है। नवंबर 2019 में यह और घट कर 92 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया है। हालांकि इसे 40 तक होना चाहिए। इस हिसाब से यह अभी भी लगभग दोगुना है।

आरएफआइडी टैग और एक्सप्रेस-वे से कम हुआ ट्रकों का प्रवेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या में 85 फीसद तक कमी आ गई है। इससे राजधानी में रात के समय होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिली है। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के मुताबिक पहले हर रोज औसतन 35 हजार ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते थे। ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और आरएफआइडी टैग लागू होने के बाद उनकी संख्या प्रति दिन महज चार हजार रह गई है। पिछले सालों में सर्दियों की शुरुआत में दिन में धूप निकलने पर प्रदूषण कुछ कम हो जाता था। लेकिन रात में ठंड बढ़ने और भारी वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता था। वहीं इस साल रात के समय होने वाले प्रदूषण से काफी हद तक कमी देखी गई है। इसकी वजह राजधानी में वाहनों का कम प्रवेश मानी जा रही है। इस साल अगस्त में ईस्टर्न व वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे के चालू होने और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के 13 प्रवेश मार्गों पर आरएफआइडी टैग अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वहीं ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें यहीं पर सामान पहुंचाना है।

यूनिटेक को ब्याज के साथ लौटाने होंगे उपभोक्ता के 49 लाख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यूनिटेक बिल्डर को आदेश दिया है कि उपभोक्ता के 49 लाख 20 हजार रुपये 10 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें। साथ ही केस खर्च के 25 हजार रुपये भी अदा करें। उपभोक्ता ने 2006 में ग्रेटर नोएडा में बनने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा कर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया।

नई दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी नीरू ढल्ल ने ग्रेटर नोएडा में बनने वाले यूनिटेक होरिजन में मई 2006 में फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कीमत 51.37 लाख रुपये तय हुई और सितंबर 2008 तक 49.20 लाख अदा कर दिए गए थे। बकाया रकम नवंबर 2008 में फ्लैट का कब्जा मिलने के समय देना तय हुआ, लेकिन समय गुजरता गया और निर्माण अधर में ही लटका रहा। नीरू ढल्ल ने उपभोक्ता आयोग में दायर शिकायत में कहा कि यूनिटेक ने दिल्ली साकेत स्थित दफ्तर के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं आयोग की तरफ से जारी नोटिस पर यूनिटेक ने जवाब दिया कि रियल एस्टेट में अचानक आई मंदी के कारण उनके प्रोजेक्ट लटक गए। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन किसानों की जमीन सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी, उन्होंने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिए। इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो सका। यूनिटेक की इन दलीलों को आयोग ने मानने से इन्कार कर दिया। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भी लंबित कई मामलों में भी यूनिटेक ने यही दलीलें दीं, जो स्वीकार नहीं की गईं। ऐसे में उपभोक्ता को इंतजार नहीं कराया जा सकता।

144 खंभे बनाए गए हैं संसद की पहली मंजिल पर। इस भवन की गोलाकर संरचना निरंतरता की प्रतीक है, यह संरचना यह दर्शाती है यह सत्ता बनी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी।

संसद और मुंबई हमले के बाद भी एयरस्ट्राइक को तैयार थी वायुसेना

नई दिल्ली, एजेंसियां : पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने शनिवार को कहा कि 2001 में संसद पर और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हवाई हमला करने के लिए वायु सेना तैयार थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसकी अनुमति नहीं दी। वह वीजेटीआई के वार्षिक समारोह 'टेक्नोवंजा' को संबोधित कर रहे थे।

धनोआ ने कहा कि दिसंबर, 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने की योजना तैयार की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। दिसंबर, 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद भी तत्कालीन वायुसेना प्रमुख गुलाम कश्मीर में मौजूद आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। उस समय तकनीकी रूप से वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना से मजबूत स्थिति में

- पूर्व वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा, तत्कालीन सरकारों ने नहीं दी अनुमति
- पुलवामा के बाद सरकार ने फैसला किया, हमने बालाकोट को अंजाम दिया

बीएस धनोआ। फाइल

भी थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पुलवामा में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमला करने में इसलिए सफल रही क्योंकि सरकार ने इसका फैसला किया। उन्होंने कहा, 'इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया और हमने उसे अंजाम दिया।' धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि इससे उसे कई लाभ मिलते हैं। पाकिस्तान झूठ फैलाने में लगा है और वह कश्मीर में हमले जारी रखेगा।

बता दें कि धनोआ 31 दिसंबर, 2016 से 30 सितंबर, 2019 तक वायुसेना प्रमुख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के पास जमीन, आकाश और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पड़ोस में दो परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान और चीन मौजूद हैं। चीन ने अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक बना लिया है। उसने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वायुसेना की तैनाती भी की है। वह दक्षिण चीन सागर में भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, उसने ऐसे युद्धपोत बनाए हैं जो डूब नहीं सकते।

सोशल मीडिया पर ज्ञान साझा करेंगे केंद्रीय विवि

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज : दुनिया में ज्ञान और सूचनाओं को आपस में साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए सोशल मीडिया भी एक बेहतर प्लेटफार्म हो सकता है। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस दिशा में अहम निर्णय लिया है कि देशभर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अब सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। इसमें सभी तकनीकी संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

दरअसल, मंत्रालय ने लंबे समय से यह नई योजना बनाई थी। उसे मूर्त रूप देने के लिए इस मसले पर शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के करीब 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। कार्यशाला में बताया गया कि वर्तमान में यह जरूरी हो गया है कि अपने ज्ञान और सूचनाओं को आपस में साझा किया जाए, ताकि सभी छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हर संस्थान विभिन्न मीडिया मंचों के माध्यम से अपने अच्छे कार्यों का प्रचार करे।

आज हेमंत लेंगे झारखंड के सीएम पद की शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची

- कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी लेंगे शपथ
- खरमास के बाद विस्तार में जोड़े जाएंगे अन्य मंत्रियों के नाम

झारखंड के ग्यारहवें मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी शपथ लेंगे। अन्य नामों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अनुमान है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें सभी नामों पर फैसला होगा। फिलहाल कांग्रेस से पांच, झामुमो से छह और राजद से एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के फॉर्मूले पर सहमति है। झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायकों और अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन इस सरकार को अलग से है।

मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का यह दूसरा कार्यकाल होगा। उनके अलावा बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और रघुवर दास भी एक-एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ने तीन-तीन बार सत्ता की बागडोर संभाली है।

फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर संशय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि झामुमो से भी एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की तैयारी है, लेकिन शनिवार देर रात तक नाम पर फैसला नहीं हो सका था।

मुझे सिर्फ अपनी जानकारी, दूसरों की नहीं : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है। फैसला आलाकमान को लेना है। यहां से अनुशंसा की बात भी नहीं है। उनका दो टूक जवाब था-प्रदेश प्रभारी ने फोन पर तैयार होने की सूचना दी और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं।

देश भर से जुटेंगे विपक्षी नेता : शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, शरद पवार के साथ बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, बसपा अध्यक्ष मायावती, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सीपीआइ नेता कन्हैया कुमार, सांसद टीआर बालू आदि शामिल होंगे।

भगवा की जगह हरा रंग

मोरहाबादी मैदान में पूर्व के सरकारी समारोह में दिखने वाला भगवा रंग इस बार नहीं दिखेगा। अब चलन में हरा रंग है और इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर हुआ है। मैदान की घेराबंदी में सफेद और हरे रंग के कपड़े का उपयोग किया गया है।

'भ्रष्टाचार मिटाएंगे, स्थानीयता और नियोजन नीति में करेंगे बदलाव'

साक्षात्कार

अपने आवास में महागठबंधन के विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन। जागरण

झारखंड में सत्तासीन रही भाजपा को बेदखल कर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हेमंत सोरेन को यह पद आसानी से नहीं मिला है। उन्होंने राज्य की जरूरतों, समस्याओं और लोगों की उम्मीदों को करीब से समझा है। चुनावी रणनीति बनाने से लेकर प्रत्याशियों का चयन करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी। वे अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ कांग्रेस और राजद के भी स्टार प्रचारक थे। सधे हुए कदमों से बिना थके उन्होंने पूरे अभियान को नेतृत्व दिया और जब परिणाम सामने आया तो उस गठबंधन को बहुमत से ज्यादा विधायक मिले, जिसकी कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है। हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत के तौर पर मिली, लेकिन खुद को साबित करने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा है। झारखंड के लिए उनका एजेंडा स्पष्ट है जिसे वे अपने कार्यकाल के दौरान मुकाम तक पहुंचाने को उत्सुक हैं। इस बाबत **हेमंत सोरेन** से **दैनिक जागरण** के राज्य ब्यूरो प्रभारी **प्रदीप सिंह** ने विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश :

आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको इसकी बधाई और शुभकामनाएं। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी?

राज्य के लिए जो आकांक्षाएं आम लोगों की है, वह हमारी भी है। इसके लिए परिणाम आने तक लगातार काम करना होगा, गतिशील रहना होगा। जहां तक आपने प्राथमिकताओं की बात की तो यह बड़ा व्यापक है। इसके लिए बड़ी सोच भी रखनी होगी। विजन के साथ काम को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। आप देखेंगे कि हम आमलोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने में कामयाब होंगे। सभी लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विजन का लाभ पहुंचेगा। जो तबका उपेक्षित रहा है, उनकी चिंता सरकार करेगी। भ्रष्टाचार के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं होगी। हम लोगों का काम सबको दिखेगा। हम होर्डिंग और बैनर में चेहरा चमकाने की बजाय धरातल पर काम करके दिखाएंगे।

आपको पूर्व में भी राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला है। तब आपका कार्यकाल काफी कम समय का था। इस बार जनादेश पांच वर्षों के लिए मिला है। कैसा लग रहा है?

हंसते हुए....आपने सही कहा, इस बार जनता ने ठोस जनादेश दिया है। अगले पांच साल इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम देश में झारखंड की अलग पहचान कायम करेंगे। झारखंड तेजी से आगे बढ़ेगा।

आपने भाजपा सरकार के दौरान लागू की गई स्थानीयता नीति और नियोजन नीति का विरोध किया था। क्या इसे बदलने की दिशा में कार्रवाई करेंगे?

निश्चित तौर पर स्थानीयता नीति और नियोजन नीति में बदलाव करेंगे। इन नीतियों की त्रुटियों को खत्म करेंगे। सबके साथ मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और राज्य के हित में फैसले लेंगे।

झारखंड में भाजपा की शिकस्त की अनुगूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। भविष्य में आप अपनी भूमिका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी पाते हैं?

बेशक राजनीति का दायरा सीमित नहीं किया जा सकता। आज यह काफी व्यापक है। यह जहां तक जाएगा उसी के मुताबिक कार्य करेंगे। फिलहाल झारखंड पर ही पूरा ध्यान केंद्रित है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ढेर सारे चुनावी वादे किए हैं। क्या सारे वादे धरातल पर उतरेंगे?

बिल्कुल...हमने जो भी वादा किया है, उसे हर हाल में निभाएंगे। इसके अलावा अन्य कार्य भी हम करेंगे जो पद पर बैठने के पश्चात मेरे ध्यानार्थ लाए जाएंगे। हम अपने वादे निभाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है। आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब कोई हमारे झारखंड में भूख से नहीं मरेगा, कोई बच्चा भात-भात चिल्लाते हुए नहीं मरेगा।

बोले वेंकैया नायडू ▶ हमें संवैधानिक तरीकों से समस्याएं हल करना सीखना होगा

'विचार-विमर्श से सुलझाएं जटिल मुद्दे'

उपराष्ट्रपति ने जेटली पर लिखी किताब का ओम बिरला के साथ किया विमोचन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर लिखी गई पुस्तक 'दि रेनैसांस मैन : दि मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली' का विमोचन करते उपराष्ट्रपति एम वैंकया नायडू (बीच में)। साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (बाएं) और अरुण जेटली की पत्नी संगीता। पीआइबी

वर्तमान हालात में ज्वलंत मुद्दों को संविधान के दायरे में रहते हुए बौद्धिक विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाए जाने की जरूरत है। इसके लिए अरुण जेटली जैसा चरित्र, प्रतिभा और क्षमता चाहिए, जिनमें सबको साथ लेकर जटिल विषयों को भी आसानी से सुलझा लेने की अद्भुत क्षमता थी। यह बात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्गीय जेटली पर लिखी पुस्तक 'दि रेनेसां मैन : दि मेनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली' का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ विमोचन करते हुए कही।

सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं का जिक्र किए बगैर नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ज्वलंत मुद्दों को संसद, विधानसभाओं तथा जनता के बीच चर्चाओं के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। जटिल विषयों पर आपस में चर्चा करें, जनता के बीच जाकर बहस करें और फिर निर्णय जनता पर छोड़ दें। यही वक्त का तकाजा है। जाति, धर्म को हावी होने देने के बजाय हमें संवैधानिक तरीके से समस्याओं को सुलझाने की आदत डालनी चाहिए। यही अरुण जेटली को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जेटली की जयंती पर उनकी खूबियों को याद करते हुए वेंकैया ने कहा कि संसद में जब-जब जटिल मुद्दे आएंगे, तब हमें अरुण जेटली की याद आएगी। वे कठिन से कठिन मुद्दों पर भी इतने प्यार भरे तरीके से अपनी बात रखते थे कि सभी को सहमत होना पड़ता था। संसद के सेंट्रल हॉल में बड़ा जमावड़ा होता था, तो सभी समझ जाते थे कि जेटलीजी बैठे हैं। पत्रकार भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वे खबरों के स्रोत थे।

नायडू ने कहा कि वे असाधारण प्रतिभा के धनी ऐसे राजनेता थे, जो सभी के लिए सहज सुलभ थे और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे। पहली बार मिलने वाला भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। छोटा, बड़ा जो उनके पास गया उन्होंने हमेशा सबकी मदद की। उनमें कुशल वक्ता, असाधारण संवादकर्ता तथा आदर्श सांसद के सभी गुण मौजूद थे। वे देश से प्यार करने वाले ईमानदार नेता थे और भ्रष्टाचार से उन्हें सख्त नफरत थी। नई पीढ़ी को जेटली से सीखने की जरूरत है।

नायडू ने जेटली से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि हम दोनों छात्र यूनियन लीडर थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात जेपी आंदोलन के समय में हुई थी, जो बाद में अटल और फिर मोदी सरकार में मंत्री और राज्यसभा में सभापति बनने पर भी जारी रही। लगभग रोजाना ही विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा होती थी। वे खाने-खिलाने के बेहद शौकीन थे और ऐसी जगहों पर बैठकें आयोजित कराना पसंद करते थे, जहां बढ़िया रेस्तरां हो, ताकि मीटिंग और ईटिंग साथ-साथ हो सके। अरुण जेटली के व्यक्तित्व से मेरे बेटे हर्षवर्द्धन और बेटी दीपा वेंकट भी अछूते नहीं रहे और इसी का नतीजा है कि दोनों ने उनकी यादों को इस पुस्तक के रूप में संजोया है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जेटली के साथ अपने अनुभवों को साझा किया।

न्यूज गैलरी

महाराष्ट्र सीएम के बंगले में ठाकरे के खिलाफ भद्दी टिप्पणी

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले 'वर्षा' में एक दीवार पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरोध और भाजपा के समर्थन में कुछ शब्द लिखे मिलने पर विवाद पैदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इसे खाली कर दिया था और नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी इस घर में आए नहीं हैं। स्थानीय समाचार चैनलों में जो लिखावट दिखाई जा रही है उसके मुताबिक बंगले की एक दीवार अंग्रेजी में लिखा है-'यूटी इज मीन', 'बीजेपी रॉक्स'। फड़नवीस ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है।

चौटाला पिता-पुत्र को 14 दिन का फरलो

नई दिल्ली : जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 14 दिन की फरलो मिली है। पिता-पुत्र शनिवार को तिहाड़ जेल से निकलकर घर के लिए रवाना हो गए। जेल प्रशासन ने शुक्रवार को ही इस संबंध में आदेश जारी किया था। (जासं)

उप्र में हिंदू परित्यक्त महिलाओं को पेंशन के लिए एफआइआर जरूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने तीन तलाक पीड़िताओं व हिंदू परित्यक्त महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना पेंशन देने की घोषणा 25 सितंबर को की थी। इस योजना को दो विभागों अल्पसंख्यक कल्याण व समाज कल्याण विभाग को मिलकर चलानी है। दोनों विभागों ने पेंशन की नियमावली का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री के सामने प्रजेंटेशन होना है। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद हर जिले से पीड़िताओं के आवेदन-पत्र लेकर उन्हें पेंशन दी जाएगी।

उप्र में हिंदू परित्यक्त महिलाओं को पेंशन पाने के लिए थाने में एफआइआर दर्ज कराना जरूरी होगा। एफआइआर न होने पर थाने में दी गई तहरीर को भी पेंशन के लिए मान्य किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन नियमावली का खाका तैयार कर लिया है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक पीड़िताओं व हिंदू परित्यक्त महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना पेंशन देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर रहा है। इसके लिए दोनों विभाग मिलकर नियमावली तैयार कर रहे हैं। तीन तलाक पीड़िताओं को आर्थिक सहायता के साथ ही कानूनी मदद भी दी जानी है।

हिंदू परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देने के लिए उनकी पहचान किस तरह की जाए, यह पेंच फंसा हुआ था। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने नियमावली के ड्राफ्ट में हिंदू परित्यक्त महिलाओं की ओर से एफआइआर दर्ज कराये जाने या फिर थाने में लिखित शिकायत करने का प्रावधान जरूरी कर दिया है।

तीन तलाक पीड़िताओं के साथ नहीं है दिक्कत : तीन तलाक पीड़िताओं की पहचान में कोई संकट इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिमों में निकाह एक तरह का करारनामा है, जबकि हिंदुओं में शादी एक पवित्र बंधन माना गया है।

अहमदाबाद-मुंबई के बीच 17 को चलेगी तेजस

नई दिल्ली, प्रेट्र : लखनऊ-दिल्ली रूट के बाद अब देश की निजी यानी कॉरपोरेट ट्रेन तेजस अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच भी शुरू होने जा रही है। इस मार्ग पर 17 जनवरी को तेजस ट्रेन लांच होगी और 19 जनवरी से इसका व्यावसायिक परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे की खानपान एवं पर्यटन शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) इस ट्रेन का संचालन कर रही है। अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। पहली तेजस की तरह ही देरी से चलने पर यात्रियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। रेलवे में एयरलाइंस जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के तहत इस ट्रेन में यात्रियों को एयरलाइंस जैसी सुविधा दी जा रही है। उच्च गुणवत्ता के भोजन और पेय पदार्थ ट्रेन में सवार यात्रियों को परोसे जाएंगे और इसकी कीमत टिकट में शामिल होगी। हर कोच में बोतल बंद पानी के साथ ही आरओ भी लगा रहेगा। यात्रियों को ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराकर रेल मंत्रालय यात्रा को सुखद बनाने में जुटा है।

सूत्रों के अनुसार, एक घंटा से अधिक की देरी होने पर आइआरसीटीसी प्रति यात्री 100 रुपये और दो घंटे से अधिक की देरी होने पर 250 रुपये क्षतिपूर्ति देगी। इसके अलावा ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को आइआरसीटीसी की ओर से 25 लाख रुपये तक का मुफ्त रेल यात्रा बीमा मुहैया कराया जाएगा। इसमें यात्रा के दौरान डकैती आदि की स्थिति में एक लाख रुपये तक का कवरेज भी शामिल होगा।

तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होगा। केवल जेनरल कोटा और विदेशी पर्यटक कोटा होगा। विदेशी पर्यटक कोटे की छह सीटें एग्जिक्यूटिव क्लास में और 12 चेयर कार में होंगी।

अब रेलवे प्लेटफार्म पर चढ़ने और उतरने का देना होगा शुल्क

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

रेलवे में अब मुफ्त की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। यहां तक कि प्लेटफार्म पर उतरने व चढ़ने तक का शुल्क वसूला जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल इसे देहरादून व चंडीगढ़ में लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह शुल्क कितना होगा, यह अभी तय नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने रेलवे की आर्थिक स्थिति को लेकर रिपोर्ट में कहा है कि 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे 98.44 रुपये खर्च करता है। सुझाव दिया कि आंतरिक स्रोत से आय (इंटरनल रेवेन्यू) बढ़ाएं। साथ ही मुफ्त सेवा पर रोक लगाने व सभी यात्री सुविधाओं पर शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। इसके बाद रेलवे बोर्ड व रेल मंत्रालय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के साथ कुछ नई सुविधाएं भी शुरू होंगी। यही नहीं आप जिस स्टेशन के लिए टिकट ले रहे हैं वहां प्लेटफार्म पर उतरने और चढ़ने का शुल्क वसूलने की भी तैयारी है। यानी टिकट के साथ ही शुल्क वसूल किए जाएंगे। इससे सामान्य टिकट के साथ प्लेटफार्म टिकट की भी कीमत बढ़ जाएगी। किराया क्या होगा, अभी यह तय नहीं किया गया है।

हार्दिक पटेल को कांग्रेस देगी बड़ी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात कांग्रेस अपने जंबो संगठन व निष्क्रिय नेताओं को हटाकर 80 सक्रिय सदस्यों को प्रदेश संगठन में शामिल करेगी। अध्यक्ष पद पर अमित चावडा बने रहेंगे और युवा नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के पाटीदार वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस हार्दिक का कार्ड खेल सकती है ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव तक मजबूत युवा टीम तैयार की जा सके। नए संगठन में निष्क्रिय नेताओं को दरकिनार कर 80 सक्रिय सदस्यों का ही संगठन बनाया जाएगा। छह सीटों पर कराए गए उपचुनाव में चावडा के नेतृत्व में तीन सीट जीतने के बाद पार्टी में उत्साह दिखाई दे रहा है।

शनिवार को कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव, अध्यक्ष अमित चावडा ने नेता विपक्ष परेश धनाणी, पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांधी आश्रम पर ध्वज लहराया और उसके बाद संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाते हुए वहां से कूच किया। सातव ने भाजपा पर किसान, युवा व महिलाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के 25 साल के कार्यकाल में 11 बार प्रतियोगिता परीक्षाएं रद करनी पड़ी।

कम हुई तल्खी

बंगाल सरकार व राज्यपाल के तल्ख रिश्ते में दिखी थोड़ी नरमी, धनखड़ ने कहा-लोकतंत्र में एकजुटता से बढ़ना होगा आगे, विश्वविद्यालयों पर चर्चा को लेकर पत्र लिख सीएम से मांगा था समय

ममता ने 24 घंटे में दिया जवाब तो खुश हुए धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल सरकार व राज्यपाल के तल्ख रिश्ते में शनिवार को तब थोड़ी नरमी देखने को मिली, जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए लिखे गए पत्र का जवाब 24 घंटे के भीतर मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। राज्यपाल ने कहा- 'लोकतंत्र में एकजुटता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री से राजकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चर्चा को लेकर मुलाकात के लिए लिखे पत्र का जवाब मिलना दर्शाता है कि शिक्षा के परिदृश्य में सुधार के प्रति मेरे प्रयासों का असर दिखने लगा है।'

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राज्यपाल मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर पत्र लिख चुके हैं, जिसका कोई जवाब नहीं आया था। गत 25 दिसंबर को राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों पर चर्चा के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात करने की इच्छा जताई थी। इसका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से 26 दिसंबर को ही राजभवन भेज दिया गया, जिसमें कहा गया है कि चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग के अंतर्गत पड़ता है इसलिए शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को मामला अग्रसारित किया गया है ताकि वे समयानुसार आपसे (राज्यपाल) मुलाकात करें।

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

गौरतलब है कि गत 24 दिसंबर को राज्यपाल जब जादवपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे थे तो कुछ छात्रों ने उनका रास्ता रोक दिया था और 'गो बैक' के नारे लगाए थे। राज्यपाल ने सीएमओ से प्राप्त पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा है,-मैंने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसका जवाब उन्होंने 26 दिसंबर को देते हुए कहा कि चूंकि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का मामला मेरे अधीन नहीं पड़ता, इसलिए इस बाबत शिक्षा मंत्री आप से सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि मैं मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हमें एकजुटता से आगे बढ़ना होगा।'

पहले जमा होगी रिपोर्ट, फिर होगी मुलाकात : पार्थ : शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने शनिवार को इस मामले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहले उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्यपाल के सवाल का जवाब दिया जाएगा, फिर वे उनसे सोमवार अथवा मंगलवार को मुलाकात कर सकते हैं, जो कि सहूलियत के हिसाब से तय होगी। पार्थ ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की चिट्ठी को ट्वीटर पर साझा करने पर सवाल करते हुए कहा कि गोपनीय चिट्ठी सार्वजनिक पटल पर नहीं आनी चाहिए थी।

मप्र में राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस में बवाल, बाबरिया बिफरे

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया बिफर गए हैं। वह खुलकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन के लिए लंबे समय से सक्रिय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि एआइसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) के पदाधिकारियों का काम संगठन में समन्वय का होता है। मुख्यमंत्री किसी के सुझाव या अपने विवेक पर किसी भी अशासकीय सदस्य को नियुक्ति दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अब तक करीब दस अशासकीय सदस्यों की सहकारिता क्षेत्र में राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। इनमें ग्वालियर के कांग्रेस नेता अशोक सिंह की मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक के रूप में अशासकीय नियुक्ति सबसे अहम है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

125 वोट नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में पड़े थे राज्यसभा में, जबकि विरोध में 99 वोट पड़े थे। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 29 दिसंबर 2019

साक्षात्कार

वोटबैंक की राजनीति में उलझा विपक्ष : रविशंकर

सीएए और एनपीआर को लेकर हो रहे हिंसात्मक विरोध को कांग्रेस जैसे बड़े राष्ट्रीय दल के समर्थन को केंद्रीय कानून मंत्री **रविशंकर प्रसाद** दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख **नितिन प्रधान** से बातचीत में प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब एनआरसी कानून लागू हुआ और 2010 में संसद में जनगणना पर बहस हुई तो लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह और तमाम वामपंथी दल इसके समर्थन में थे। वही लोग अब विरोध कर रहे हैं। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश

● आखिर नागरिकता संशोधन कानून का देशव्यापी विरोध क्यों हो रहा है?

-देखिए, मैं इस संबंध में सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह कानून किसी भी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता, मुस्लिम सहित। यह किसी की नागरिकता भी नहीं लेता। इसका सीमित उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का है, जिन्हें उनके घर से भगा दिया गया। यह पहली बार तो नहीं हो रहा है। साठ के दशक में युगांडा से हिंदुओं को ईदी अमीन ने निकाला तो उनको नागरिकता दी गई या नहीं? 1971 में बहुत सारे लोग भागकर आए तब इंदिराजी ने दी। राजीव गांधी ने श्रीलंका के पीड़ित तमिलों को दिया, तब भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, तरुण गोगोई ने कहा तो विरोध नहीं हुआ। यानी मोदी और अमित शाह कुछ करें तो गलत है। आप करें तो सही। यह कौन सा लॉजिक है? भारत की विरासत रही है कि आस्था के कारण जो लोग पीड़ित होते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। इसीलिए हमने ईरान से आने वाले पारसी भाइयों को सम्मान दिया।

● जब पहले ऐसा हुआ तो क्या बिना कानून में संशोधन किए ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती थी?

-पहले ग्रुप में दी जा रही थी। हम जिनकी बात कर रहे हैं, वे पीड़ित होकर वर्षों से यहां रह रहे थे। देश में कहीं भी ऐसे लोगों को जाकर देखा जा सकता है। किस तरह वो जिल्लत में रह रहे थे। हमारा तो काउंटर चार्ज है कि संप्रग और कांग्रेस सरकार ने उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी? अफगानिस्तान में सिख और पाकिस्तान में हिंदू गिनती में बचे हैं।

● तब इतना हिंसक आंदोलन क्यों हो रहा है?

- बिलकुल, मैं यहां सवाल पूछना चाहता हूं कि जब स्थिति इतनी स्पष्ट थी तो इतनी हायतौबा क्यों मचाई गई? वो कौन सी ताकते थीं, जो हिंसा को उकसा रही थीं। और कांग्रेस ऐसी जिम्मेदार पार्टी जो देश पर 55 साल राज कर चुकी है, उसने ऐसा क्यों किया। (नागरिकता कानून दिखाते हुए) यह कानून तो 1955 का है।

● कांग्रेस कहती है कि एनपीआर एनआरसी की शुरुआत है?

-इसके जवाब की शुरुआत मैं एक उदाहरण से देता हूं। सात मई, 2010 को लोकसभा में 2011 की जनगणना पर चर्चा हुई। चिदंबरम साहब ने विस्तार से जवाब दिया और पूरे एनपीआर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि रजिस्टर ऑफ सिटीजन पॉपुलेशन रजिस्टर का सबसेट है। उस वक्त इस बहस में लालू प्रसाद, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ने हिस्सा लिया। संप्रग के स्टैंड के साथ सभी खड़े थे। पर आज वे विरोध कर रहे हैं। भाकपा और माकपा भी उनके साथ थे। यह कौन सा दोहरा मानदंड और चरित्र है? यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। विरोध करने और सवाल पूछने का सबको अधिकार है। नरेंद्र मोदी सहित पूरी सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है। लेकिन हिंसा का तांडव और टुकड़े टुकड़े गैंग के षड्यंत्र को सफल होने नहीं दिया जाएगा। इतनी स्पष्टता के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि इतनी हिंसा हुई?

● इस हिंसा के पीछे किसे देखते हैं आप?

-दरअसल इस वोट बैंक की राजनीति में उत्तेजक और अतिवादी ताकतें सक्रिय हैं। इनमें पीएफआइ भी है। एमक्यूएम का नजरिया भी अलग है। ये लोग जान-बूझकर उत्तेजना और अतिवाद के सहारे अपने षड्यंत्र और राजनीति को सफल करते हैं। मुझे पीड़ा होती है कि कांग्रेस इनके साथ कैसे खड़ी होती है? क्या वोटबैंक के लिए ये दल यहां तक जाएंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

● फिर एनपीआर क्यों जरूरी है?

-देखिए हर 10 वर्ष पर देश में जनगणना होती है। इसके लिए बाकायदा एक कानून है। इसका संवैधानिक पहलू है। समाज के तमाम वर्गों को सहूलियतें देने और अनुसूचित जातियों, जनजातियों समेत अन्य सभी आरक्षण का आधार पिछली जनसंख्या के आंकड़े होते हैं। जनगणना के निजी आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह काम पॉपुलेशन रजिस्टर से होता है। नीति निर्धारण, सेवाओं की बहाली और जनकल्याणकारी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए यह बहुत जरूरी है। देश के कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोगों के पास मकान हैं, सभी आंकड़े इससे प्राप्त होते हैं। इसलिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का केंद्र भी इस्तेमाल करता है और प्रदेश की सरकारें भी।

● लेकिन, कहा जा रहा है कि इस बार कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी जा रही हैं।

-आप ही बताइए, देश में वोट कौन दे सकता है, जो देश का नागरिक हो। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास वोटर आइ कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट सभी में आपके मां-बाप का नाम होता है और ये सभी जानकारी सार्वजनिक होती है। तब आप विरोध नहीं करते? तब ये बात कहां से उठ रही है, क्यों उठ रही है? भ्रामक तथ्यों के आधार पर उकसाने की ये कार्रवाई क्यों हो रही है? हमारा आरोप है कि अलगाववादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग ये काम कर रहा है।

● एनआरसी को लेकर भी सरकार आरोपों के घेरे में है?

-इसे भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। नेशनल सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 14-ए में कहा गया है कि केंद्र सरकार अनिवार्य तौर पर देश के सभी नागरिकों का पंजीकरण करेगी और उसे एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी। साथ ही केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगी और इसके लिए एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह कब लागू हुआ? यह लागू हुआ तीन दिसंबर, 2004 को। किसकी सरकार थी? अगर कांग्रेस में हिम्मत थी तो इसे लागू करने से इन्कार कर देती। उस सरकार के पीछे भी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, भाकपा, माकपा सब खड़े थे। एनआरसी की कल्पना जिस कानून से आई उसे लागू तो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। आप करें तो ठीक, हम करें तो आपको आपत्ति है। लेकिन एनआरसी की एक प्रक्रिया है। रूल 4 के मुताबिक एक तिथि तय होगी, वह तारीख गजट में घोषित होगी, फिर इसमें नाम चढ़ाए जाएंगे। उसका वेरिफिकेशन होगा, उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, आपत्तियों का निराकरण होगा, फिर अपील का प्रावधान है। अभी तो कुछ नहीं हुआ। कोई राजनीतिक निर्णय भी नहीं हुआ। एनआरसी जब भी होगा इन नियमों के अनुसार होगा। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि अभी इस पर बातचीत भी नहीं हुई।

● तो क्या सरकार इसे लागू नहीं करेगी?

-यहां मैं आपको केवल लोकतांत्रिक देशों का हवाला देकर एक बात कहना चाहता हूं। आप अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस किसी देश में ऐसे ही घुस सकते हैं क्या? जब तक आप वहां के नागरिक न हो या वैधानिक अनुमति न हो। क्या भारत को हम धर्मशाला बनाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। हम भारत को बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। जहां समावेशी सरकार हो और सुरक्षित जनता। जनता की सुरक्षा आतंकवादियों, टुकड़े-टुकड़े गैंग और माओवादियों के कुप्रभाव से हो। क्या सरकार ने शासन में कोई विभेद किया? क्या उज्ज्वला में मुस्लिम गांव को छोड़ दिया, क्या आयुष्मान भारत में अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया, डिजिटल इंडिया में सीएससी में मुस्लिम वीएलई काम नहीं कर रहे। सच तो यह है कि हम किसी चीज को वोटबैंक के चश्मे से नहीं देखते, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। इस देश को बनाने, बढ़ाने में मुस्लिमों ने बहुत काम किया है। इस बगिया में सबको खिलने का अधिकार है। लेकिन, कोई इसे नुकसान पहुंचाएगा तो हम सख्ती करेंगे। हम बातचीत करने को भी तैयार हैं, अगर कोई करना चाहता है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सारा कुछ नियमानुसार और भारतीयों के विकास और रक्षा की आवश्यकता के लिए हो रहा है।

न्यूज गैलरी

'सत्ता में रहते कांग्रेस को क्यों नहीं याद आता संविधान'

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के स्थापना दिवस को 'भारत बचाओ, संविधान बचाओ' के रूप में मनाए जाने पर तीखा हमला किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने उप्र में विपक्षी दलों के डर जाने की बात कही, उन्होंने ट्वीट कर पलटवार किया। मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया कि 'कांग्रेस आज अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को भारत बचाओ, संविधान बचाओ के रूप में मना रही है। इस मौके पर दूसरों की चिंता व्यक्त करने के बजाय कांग्रेस स्वयं अपनी स्थिति पर आत्मचिंतन करती तो यह बेहतर होता, जिससे निकलने के लिए उसे अब किस्म-किस्म की नाटकबाजी करनी पड़ रही है।' मायावती यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि 'भारत बचाओ, संविधान बचाओ' की याद कांग्रेस को तब क्यों नहीं आई जब वह सत्ता में रहकर जनहित की घोर अनदेखी कर रही थी। जिसमें दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों को भी उनका संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा था।' (राब्यू)

मायावती फाइल

'जबलपुर में तोड़फोड़ करने वाले भाजपा के पदाधिकारी'

भोपाल : मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सीएए और एनआरसी को लेकर जबलपुर में कुछ दिन पहले हुई तोड़फोड़ की घटना में भाजपा के पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुस्लिम पदाधिकारी के भड़काने पर तोड़फोड़ हुई और उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को भी जवाबी पथराव करना पड़ा। यही वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। दिग्विजय ने कांग्रेस शासित राज्यों के प्रशासन को हिदायत दी है कि गड़बड़ी करने वाले शरारती तत्वों को देखें कि वे भाजपा से जुड़े हैं या औवैसी समर्थक थे। उधर, विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के वायरल वीडियो पर भाजपा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में खुफिया तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। (नईदुनिया)

दिग्विजय सिंह फाइल

आंबेडकर के सपने को साकार कर रहा नागरिकता संशोधन कानून : जे नंदकुमार

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- **आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक ने अपनी नई पुस्तक में आंबेडकर की प्रशंसा की**
- **सच साबित हुई आंबेडकर की चेतावनी कि पाकिस्तान में विलुप्त हो जाएंगे हिंदू दलित**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर मचे विवाद के बीच आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक जे नंदकुमार ने दावा किया है कि सीएए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के सपने को पूरा करता है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान लग रहे हिंदुत्व विरोधी नारों के बीच प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंदकुमार ने अपनी नई पुस्तक 'हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स' में बाबा साहब आंबेडकर पर विस्तार से लिखा है। नंदकुमार के अनुसार, पुस्तक में सीधे तौर पर सीएए का जिक्र नहीं है क्योंकि इस पर काम काफी पहले पूरा हो गया था।

अपनी पुस्तक में नंदकुमार ने बाबा साहब आंबेडकर के पत्रकार के रूप में व्यक्त विचारों को विस्तार से रखा है। उनके अनुसार, जो बात जनसंघ के लोग नहीं बोल सके थे, उसे आंबेडकर ने डंके की चोट पर कह दिया था। नंदकुमार के अनुसार, आंबेडकर ने कहा था कि वहां (पाकिस्तान में) दलित हिंदू पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब की यह चेतावनी आजादी के कुछ ही साल बाद ही सच साबित हुई और पाकिस्तान के पहले दलित मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल को आना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यदि आज बाबा साहब जिंदा होते तो निश्चित रूप से सीएए का स्वागत करते।

नंदकुमार ने मौजूदा वक्त में हिंदुत्व को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी का 'इज्म' जोड़कर हिंदुत्व को हिंदुइज्म के रूप में पेश कर रहे हैं। जबकि हिंदुत्व कोई सीमित दायरे में बंधा हुआ विचार नहीं है। बल्कि यह एक सतत प्रवाह है जो बदलते समय के साथ खुद को बदलता भी है और सबको समाहित भी करता है।

पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस तरह आजादी के बाद वामपंथियों के सहयोग से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई। नंदकुमार के अनुसार, संविधान में संशोधन कर धर्मनिरपेक्ष शब्द इसी साजिश के तहत जोड़ा गया, जबकि संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हुई थी और उसके बाद फैसला हुआ था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू हमेशा से सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है।

नंदकुमार के अनुसार, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के बाद हिंदुओं से जुड़े महापुरुषों को बदनाम करने का काम शुरू हुआ। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण वीर सावरकर हैं। आपातकाल लागू होने के पहले तक वामपंथी नेता नंबूदरीपाद से लेकर इंदिरा गांधी तक सावरकर के प्रति सम्मान भाव प्रकट करते थे, लेकिन फिर उनके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। इसी तरह हिंदू एकता को तोड़ने के लिए जातीय राजनीति को बढ़ावा दिया जाने लगा। यही कारण है कि बाद के समय में सभी राज्यों में अलग-अलग जातियों के नेताओं का उदय हुआ।

सीएए को समर्थन...

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को विदेश में रह रहे भारतीयों का अपार समर्थन मिल रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतवंशियों ने सीएए के लिए आवाज बुलंद की। इस मौके पर वहां भारतीय दूतावास के बाहर जुटे भारतीय समुदाय ने लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अवगत कराते हुए जागरूक किया। एएनआइ

नागरिकता कानून पर उप्र में छह रैलियां करेगी भाजपा

जागरण संवाददाता, मेरठ

सीएए को लेकर देशभर में मचे घमासान के बीच संघ ने भाजपा को नया होमवर्क दिया है। संघ ने मेरठ के माधवकुंज स्थित कार्यालय में शनिवार को पश्चिमी उप्र के सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों व विधायकों के अलावा संगठन के साथ बैठक की। सीएए को लेकर अल्पसंख्यक समाज में व्याप्त भय को दूर किया जाएगा। प्रदेशभर में छह रैलियां होंगी। पश्चिमी उप्र की रैली मेरठ में 15 से 26 जनवरी के बीच होगी। इससे पहले मुख्यालयों तक पदयात्रा के बहाने जागरूकता बढ़ाने की योजना है।

माधवकुंज में शनिवार सुबह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, डॉ. संजीव बालियान, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, चौ. भूपेंद्र सिंह, चेतन चौहान, राज्यमंत्री गुलाबो देवी, डॉ. धर्मवीर सिंह सैनी समेत आधा दर्जन मंत्री पहुंच गए। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर, कांता कर्दम, सुरेंद्र नागर समेत पश्चिमी उप्र के सभी विधायक भी पहुंच गए। संघ की प्रांतीय एवं विभागीय टीम के अलावा सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। संघ के प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्रीय संघचालक ने दो सत्र में भाजपाइयों से संवाद किया। संघ पदाधिकारियों ने भाजपाइयों से एक पत्रक साझा किया, जिसमें सीएए और एनआरसी के बीच फर्क और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है।

संघ पदाधिकारियों ने भाजपाइयों एवं अनुषांगिक संगठनों से कहा कि वे समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंचकर सीएए और एनआरसी को लेकर उभरे भ्रम को दूर करें। इस दौरान पार्टी एक जनवरी से 15 तक संपर्क अभियान चलाएगी।

'मदनी की भी जांच जरूरी'

मुजफ्फरनगर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने मौलाना महमूद मदनी पर हमला बोला। कहा कि सीने पर गोलियां खाने की बात कहने वाले मदनी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हिंसा और बवाल करने वालों का चरित्र उग्रवादियों की तरह रहा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि मुस्लिमों के लिए कई इस्लामिक देश हैं। किंतु हिंदू समेत अन्य धर्मों के लोगों का आश्रय सिर्फ भारत हो सकता है।

साल की सबसे बड़ी जोकर है राजग सरकार : अधीर रंजन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीएए व एनआरसी पर बढ़ते विवाद के बीच राजनीतिक पारा भी तेजी से चढ़ रहा है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को राजग सरकार को साल की सबसे बड़ी जोकर करार दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को 2019 का सबसे बड़ा झूठा कहा था।

अपने बयान में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति तेजी से नीचे जा रही है, जल्द ही केंद्र में राजग सरकार की जगह एनपीए सरकार होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर को वाद-विवाद की चुनौती देते हुए कहा कि एक बार हमारे साथ चर्चा कर लें, फिर पता चल जाएगा कि झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि गुरुवार को राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर पूरा भाजपा खेमा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमलावर था। प्रकाश जावड़ेकर ने बकायदा संवाददाता सम्मेलन कर राहुल को 2019 का सबसे बड़ा झूठा बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता उनका परिवार है, कांग्रेस उसके बाद है। राहुल गांधी को हर चीज में टैक्स नजर आता है। असल में यही कांग्रेस की संस्कृति है। जावड़ेकर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस देश में घुसपैठियों को संरक्षण देती है, यही उसका असली चरित्र है।

चिदंबरम बोले, अपने काम से मतलब रखें जनरल रावत

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को हिंसा के लिए भड़काने वाले नेता नहीं हैं। शनिवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजभवन के सामने आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने सेना प्रमुख से अपने काम से मतलब रखने को कहा। महारैली का आयोजन नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में किया गया था।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सेनाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से सरकार का समर्थन करने के लिए कहा गया है। यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अब सेना प्रमुख को बोलने के लिए कहा गया है। क्या यह उनका काम है? मैं जनरल रावत से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सेना की अगुआई करते हैं। आप अपने काम से मतलब रखिए। नेताओं को जो करना है, नेता करेंगे। नेताओं को उनका काम बताना सेना की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह लड़ाई कैसे जीती जाती है, सेना को यह बताना हमारा काम नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए जनरल रावत ने कहा था कि लोगों को हिंसा और आगजनी के लिए भड़काने वाले नेता नहीं हैं। नेता उनको नहीं कहेंगे, जो लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र हिंसा और आगजनी के लिए भड़काए जा रहे हैं।

येचुरी ने रावत के बयान को घरेलू राजनीति में दखल बताया

हैदराबाद, प्रेट्र : जनरल रावत के बयान को घरेलू राजनीति में दखल बताते हुए माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि यदि सैन्य बलों का राजनीतीकरण जारी रहा तो हालात और खराब होंगे। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए माकपा नेता ने कहा कि सरकार आरोप लगा रही है कि प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा और सेना प्रमुख ने भी कहा। लेकिन, वे अंदरूनी राजनीति से चिंतित नहीं हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सेना प्रमुख ने घरेलू राजनीति पर अपना विचार प्रकट किया है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यदि यह जारी रही, तो जैसा कि पाकिस्तान में सेना की भूमिका है, हमारे यहां भी वैसी ही हो जाएगी।

झूठ के झाड़ से ढका जा रहा सच का पहाड़ : नकवी

मुंबई, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सच के पहाड़ को झूठ की झाड़ियों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा, 'कुछ लोग क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर समाज के एक तबके में भ्रम फैला रहे हैं। सीएए, एनआरसी या किसी भी कानून से भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि सीएए को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक है, जबकि भारत स्वर्ग है। विभाजनकारी ताकतों को यह सच स्वीकार्य नहीं है और वे देश को कमजोर करने निकल पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम भारत में किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता के कारण रहते हैं।

मुख्तार अब्बास नकवी फाइल

चर्चा में

दबंग थ्री की रिलीज के दिन इंटरनेट पर सलमान से चार गुना ज्यादा किया गया सर्च, 16 दिसंबर से लगातार ट्रेंड कर रहा है नागरिकता संशोधन कानून

गूगल ट्रेंड में सलमान से ज्यादा 'दबंग' निकला सीएए

श्रीनारायण मिश्र, कानपुर

फिल्म स्टार सलमान खान की कोई फिल्म रिलीज हो तो वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। यदि वह फिल्म सुपरहिट दबंग सीरीज की अगली कड़ी 'दबंग थ्री' हो तो फिर उसका इंटरनेट सेंसेशन (सनसनी) बनना तय है। हुआ भी ऐसा ही, 20 दिसंबर को सलमान खान ने गूगल पर खूब ट्रेंड किया, फिर भी वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से पिछड़ गए। उस दिन सीएए को सलमान खान के मुकाबले तकरीबन चार गुना अधिक सर्च किया गया।

नागरिकता संशोधन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया। गूगल ट्रेंड के मुताबिक उसी दिन से लोगों में सीएए के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। 16 दिसंबर तक गूगल पर सीएए की लोकप्रियता ने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसी फिल्मी शख्सियतों के साथ ही सलमान को भी पीछे छोड़ दिया। 20 दिसंबर को दबंग थ्री की रिलीज डेट पर सलमान फिर ट्रेंड में आए। हालांकि सीएए के मुकाबले बहुत पीछे रहे। उस दिन 24 घंटे में सलमान के मुकाबले सीएए को चार गुना अधिक सर्च किया गया। इसके बाद माहौल शांत हुआ, भ्रांतियां कम होने लगीं। ऐसे में 25 दिसंबर को सलमान सीएए से आगे निकले। अपने जन्मदिन यानी 27 दिसंबर को भी वह गूगल ट्रेंड पर छाए रहे।

हालांकि सीएए की लोकप्रियता कम नहीं हुई। 20 से 24 दिसंबर के बीच एक बारगी तो गूगल ट्रेंड के मामले में सीएए ने देश की सर्वाधिक प्रसिद्ध शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी सीएए ने लगातार ट्रेंड किया। हैशटैग के साथ ट्विटर पर भी अव्वल रहा। 24 दिसंबर के बाद इसे सर्च करने वालों की संख्या में कमी आई। जाहिर है अब लोग इस कानून को काफी हद तक जान चुके हैं और उनकी जिज्ञासा कम हो रही है।

20 से 24 दिसंबर तक रही बादशाहत, सोशल मीडिया पर भी छाया

- **शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसी फिल्मी शख्सियतों को भी पीछे छोड़ा**

गूगल पर दबंग फिल्म से ज्यादा लोगों ने सीएए को सर्च किया। प्रतीकात्मक

पीएम को एक करोड़ संदेश भेज सीएए के लिए धन्यवाद देगी बंगाल भाजपा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- **पोस्टकार्ड व ईमेल के जरिये मोदी को भेजे जाएंगे संदेश**
- **बंगाल में रह रहे करीब एक करोड़ शरणार्थियों की ओर से जताया जाएगा आभार**

भाजपा की बंगाल इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में रह रहे शरणार्थियों की ओर से एक करोड़ मैसेज भेजकर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लिए धन्यवाद देगी। पोस्टकार्ड की कमी के चलते बड़ी संख्या में ईमेल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये भी पीएम को धन्यवाद संदेश भेजे जाएंगे।

प्रदेश भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने बताया कि संदेश भेजने को लेकर कुछ दिनों में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राज्य में रह रहे लगभग एक करोड़ शरणार्थी इस कानून को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई व धन्यवाद देंगे। बसु ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया जाएगा। इसके जरिये यह बताने की कोशिश भी की जाएगी कि पार्टी शरणार्थियों के साथ थी और वे पत्र के माध्यम से इस बात को स्वीकार करेंगे।

2021 के चुनाव पर है नजर : बताया जाता है कि भाजपा बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर लुभाकर 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को पटखनी देकर राज्य की सत्ता पर काबिज होने का उम्मीद कर रही है।

बड़ी संख्या में हैं मतुआ संप्रदाय से जुड़े लोग

बंगाल में बड़ी संख्या में मतुआ संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, जो हिंदू शरणार्थी के तौर पर 1947 में विभाजन एवं 1971 में मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश से आए थे। उन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली थी। सीएए के बाद उन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बंगाल में चुनावी सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें नागरिकता देने का वादा किया था। गौरतलब है कि बंगाल के कई जिलों में मतुआ संप्रदाय का काफी प्रभाव है। दर्जनों विधानसभा सीटों व तीन-चार लोकसभा सीटों पर हार-जीत तय करने में उनकी अहम भूमिका है।

350 कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में सीएए के खिलाफ गिरफ्तारियां दीं। ये सभी जमीयत उलमा-ए-हिंद (महमूद मदनी गुट) से संबद्ध थे। इन्हें मौके पर ही रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर, अन्य जिलों में स्थिति सामान्य होने के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने चौकसी बरती।

सरकार से आर-पार को तैयार कांग्रेस

हल्ला बोल ▶ स्थापना दिवस पर संविधान मार्च निकाल पार्टी ने साफ किया कि नहीं थमेगा विरोध

सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ पार्टी दिग्गज ही नहीं कांग्रेसी राज्यों के सीएम भी उतरे मैदान में

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस ने अपने 135वें स्थापना दिवस के मौके पर देशभर में 'संविधान बचाओ-भारत बचाओ' मार्च निकालकर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ अपने विरोध को नई धार दी है। दिल्ली से मुंबई, असम से केरल और गुजरात से लेकर बिहार तक पार्टी ने इस मार्च के साथ संविधान की मूल प्रस्तावना का पाठ कर एनडीए सरकार को साफ संदेश दिया कि कांग्रेस का सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन अभी थमेगा नहीं। देश में सीएए-एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर-पार की सियासी जंग की तैयारी करती साफ दिख रही है।

सीएए-एनआरसी पर राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस के सियासी तेवर इसी से जाहिर हैं कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, असम में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और लखनऊ में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद इस विरोध का नेतृत्व किया। पी. चिदंबरम और गुलाम नबी आजाद से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ही नहीं कांग्रेस शासित पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टी के इस बड़े विरोध मार्च में शामिल होकर सीएए-एनआरसी की जंग को सियासी आर-पार की लड़ाई बनाने के पार्टी के इरादे में किसी गुंजाइश को खत्म कर दिया।

दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24, अकबर रोड पर शनिवार सुबह सोनिया गांधी ने पार्टी का झंडा लहराकर स्थापना दिवस समारोह का आगाज किया। इस दौरान राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके बाद राहुल सीएए-एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस के मार्च और रैली को संबोधित करने असम रवाना हो गए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में करीब तीन किलोमीटर लंबा मार्च राजघाट तक निकाला गया।

लखनऊ में प्रियंका ने संभाली कमान: लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में सीएए-एनआरसी पर पार्टी के मुखर विरोध को आगे बढ़ाते हुए पार्टीजनों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। उत्तर प्रदेश में पूरे सूबे में लगी धारा 144 के कारण प्रियंका की अगुआई में कांग्रेस के मार्च को निकालने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। हालांकि प्रियंका ने पार्टी दफ्तर में ही अपने संबोधन के दौरान सीएए-एनआरसी के जरिये देश को बांटने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला। सीएए-एनआरसी के विरोध के लिए देश में स्वतंत्रता संग्राम जैसी दूसरी लड़ाई लड़ने की बात कह प्रियंका ने साफ कर दिया कि इसका विरोध करने के लिए निकल चुके कांग्रेस के कदम अब वापस नहीं होंगे।

नई दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के 135वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बच्चे को मिठाई भेंट करने के बाद उसे दुलारतीं पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (पगड़ी में) भी मौजूद रहे। प्रेट्र

भाजपा-आरएसएस के विचार से नहीं चलेगा देश : राहुल

एनआरसी पर भाजपा सरकार को बैकफुट पर धकेलने के कांग्रेस के इरादों को राहुल गांधी ने भी गुवाहाटी में खुलकर जाहिर किया और कहा कि भाजपा-आरएसएस के विचार से असम या देश को संचालित करने के प्रयासों के खिलाफ पार्टी की लड़ाई थमेगी नहीं। हालांकि सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा से आंदोलन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंकाओं को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व काफी सजग दिखा। इसीलिए राहुल ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन में हिंसा नहीं करने की बात कही तो प्रियंका ने भी लखनऊ में गांधी के अहिंसक विरोध के रास्ते पर चलकर संविधान के साथ छेड़छाड़ के सत्ता के प्रयासों को चुनौती देने की घोषणा की।

कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी कसी कमर

कांग्रेस शासित राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और पुडुचेरी में सीएम नारायणसामी ने कांग्रेस का संविधान मार्च निकाला। वहीं महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के मंत्रियों और सभी प्रदेशों में राज्य कांग्रेस प्रमुख की अगुआई में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया।

पुलिस ने की मारपीट, गला दबाया : प्रियंका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्रियंका वाड्रा ने शनिवार को लखनऊ में बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि पुलिस ने उनसे मारपीट की और गला दबाया। दरअसल, पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद कार्यालय से गुपचुप निकल कर कुछ पदाधिकारियों के साथ वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गिरफ्तार किए गए रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने लगीं। पुलिस ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोक दी। इससे बिफरीं प्रियंका पैदल ही चल पड़ीं। पुलिस धकियाती-जूझती रही, लेकिन वह रुकी नहीं और जुटते गए कार्यकर्ताओं के साथ करीब छह किलोमीटर का मार्च निकाल मंजिल तक पहुंचीं। यहां प्रियंका ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे मारपीट की और उनका गला दबाया।

कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रियंका कुछ वरिष्ठ कांग्रेसजन के साथ रिटायर्ड आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी के इंदिरानगर स्थित आवास जाने के लिए रवाना हो गईं। भनक लगते ही पुलिस ने उनकी गाड़ी गोमतीनगर में फन मॉल के सामने रोक ली। प्रियंका कार से उतरीं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साथ स्कूटी पर बैठकर पॉलीटेक्निक चौराहा पहुंच गईं। फिर उतरकर पैदल चलने लगीं। करीब छह किलोमीटर का सफर पैदल तय कर इंदिरा नगर स्थित दारापुरी के आवास पहुंच गईं। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे मारपीट की, पकड़कर धक्का दिया और गला भी दबाया।

प्रियंका कर रहीं नौटंकी : सिद्धार्थनाथ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की लखनऊ में पुलिस से हुई हुज्जत को राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नौटंकी करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि 'यह परिवार झूठ पर ही पनप रहा है। थूको और भागो की थ्योरी उन्हें तात्कालिक प्रचार तो दिला सकती है, लेकिन वोट नहीं। प्रियंका गांधी की नौटंकी की निंदा की जानी चाहिए।'

पुलिस की गलती नहीं : एडीजी

प्रियंका वाड्रा के आरोपों पर एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री ने कहा कि उन्हें विशिष्ट श्रेणी की सुरक्षा हासिल है। जिला पुलिस के अधिकारियों ने प्रियंका वाड्रा से उनके कार्यक्रम में हुए बदलाव के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही थी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं प्रतीत होती है।

लखनऊ में शनिवार को रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने के दौरान पुलिस द्वारा कार रोके पर कार्यकर्ता के साथ स्कूटी से जातीं प्रियंका गांधी वाड्रा (स्कूटी पर पीछे)। जागरण

प्रियंका का सीआरपीएफ के आइजी को पत्र

नई दिल्ली, एजेंसियां : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी (सीओ) के खिलाफ उनके सुरक्षाकर्मियों और उनके कार्यक्रम को रोकने की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रियंका के दफ्तर ने सीआरपीएफ के वीआइपी सुरक्षा के प्रभारी को लिखे पत्र में सीओ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं, कांग्रेस ने योगी सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दूसरी ओर, लखनऊ पुलिस ने प्रियंका के साथ धक्का-मुक्की के आरोपों को गलत बताया है।

वीआइपी सुरक्षा के प्रभारी और सीआरपीएफ के आइजी प्रदीप कुमार सिंह को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा के दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि हजरतगंज के सीओ अभय मिश्र ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वह दर्जन भर पुलिसकर्मियों के साथ बिना अनुमति उस परिसर में घुस आए जहां कांग्रेस महासचिव ठहरी हुई थीं। प्रियंका की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के कमांडों ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उनसे भिड़ गए। सीओ प्रियंका के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांग रहे थे, जो पहले ही पुलिस को उपलब्ध करा दी गई थी।

न्यूज गैलरी

मप्र की बसपा विधायक ने किया सीएए का समर्थन

दमोह: एक तरफ कांग्रेस जहां नागरिका संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहीं बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार ने इसका खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह कानून देश के हित में है। पथरिया नगर पंचायत के एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नागरिकता संशोधन कानून बनाया है, वह बहुत ही अच्छा है और देश हित में है। इस कानून से उन्हें फायदा होगा, जो पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित होकर यहां शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। (नईदुनिया)

राहुल चाहें तो इटली ले जाकर दिला दें नागरिकता : गिरिराज

रांची : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर कांग्रेस को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के लिए देश में जगह नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अगर चाहें तो कुछ लोगों को ले जाकर इटली की नागरिकता दिला लें। गिरिराज झारखंड में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि भारत घुसपैठियों के लिए धर्मशाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। (राब्यू)

मेरठ के एसपी सिटी का वीडियो वायरल होने के बाद मचा सियासी घमासान

जागरण संवाददाता, मेरठ

- वीडियो में पड़ोसी मुल्क के पक्ष में खड़े उपद्रवियों को वहीं जाने की नसीहत देते दिख रहे एसपी सिटी
- उमा भारती और प्रियंका वाड्रा ने पक्ष-विपक्ष में किया ट्वीट

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान मेरठ पुलिस उपद्रवियों के निशाने पर थी। पथराव और गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात संभालने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। भारी उपद्रव के बीच शहर की एक गली में पथराव हुआ तो एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां उपद्रवियों ने उन्हें देखकर भारत विरोधी व पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर एसपी सिटी ने इस तरह की नारेबाजी करने वालों को वहीं जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यह नहीं चलेगा कि खाएं यहां का और गाएं वहां का। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल होते ही सियासी घमासान मच गया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और भाजपा नेता उमा भारती ने ट्वीट किया है। हालांकि एसपी सिटी का कहना है कि उनका यह बयान किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि उन शरारती तत्वों के लिए था, जो काली पट्टी बांधकर पड़ोसी मुल्क के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने उनसे कहा था कि अगर तुमको यह (देश) नहीं पसंद है, तो वहीं चले जाओ। वीडियो में एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह हिंसा के दौरान शरारती तत्वों से कड़ाई से बात कर रहे हैं। उनके साथ एडीएम सिटी अजय तिवारी भी मौजूद हैं। वह कह रहे हैं, 'इस गली के शरारती युवकों को ठीक कर दूंगा मैं, एक-एक घर के एक-एक आदमी को जेल में बंद करूंगा। खाते यहां का हो और गाते कहीं और का हो'।

सटीक शब्द का चयन सामान्य हालात में होता है, असामान्य हालात में नहीं : एडीजी

मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि उस वक्त वहां पर पत्थरबाजी की गई थी। भारत विरोधी और पड़ोसी मुल्क के समर्थन में नारे लगाए गए थे। वहां हालात बहुत खराब थे। अगर हालात सामान्य होते तो यकीनन बेहतर शब्द का चयन हो सकता था, लेकिन उस वक्त हालात काफी खराब थे। हमारे अधिकारियों ने बहुत संयम दिखाया। पुलिस द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई।

संविधान इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता : प्रियंका : कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता है। भाजपा ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कद्र ही नहीं है।

यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया : उमा भारती : भाजपा नेता उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि, एसपी सिटी मेरठ का पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे, पुलिस को गालियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे, आगजनी कर रहे दंगाइयों से यह कहना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते समय यह मानवीय पक्ष भूल रहे हैं कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं। देशभक्ति का जज्बा उनमें काफी प्रबल होता है। ऐसे में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना इन दोनों भाई-बहनों की घिनौनी साजिश है।

भाजपा प्रवक्ता ने ट्वीट कर एसपी सिटी को सैल्यूट किया

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर मेरठ के एसपी सिटी को सैल्यूट किया। शलभ ने ट्विटर पर लिखा, सैल्यूट है मेरठ के सिटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह को, पड़ोसी मुल्क के समर्थन में और भारत के खिलाफ नारे लगा रहे उपद्रवियों को करारा जवाब देने के लिए। अब कुछ तथाकथित प्रबुद्धों को अफसोस है कि भारत के विरोध और पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले गद्दारों को पाकिस्तान जाने को क्यों कहा।

उप्र में हालात हुए सामान्य, इंटरनेट सेवा बहाल

जेएनन, लखनऊ

- जमीयत ने दिया धरना-प्रदर्शन, 350 ने दी गिरफ्तारी
- मेरठ में शनिवार को हालात सामान्य रहे, मुकदमों की संख्या बढ़कर 25 पहुंची

सीएए को लेकर उप्र में विरोध के स्वर अब भी जारी हैं। शनिवार को सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलमा-ए-हिंद (महमूद मदनी गुट) द्वारा धरना दिया गया। 350 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, जिन्हें मौके पर रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर, अन्य जिलों में स्थिति सामान्य होने के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने चौकसी बरती। कई जिलों में खुराफातियों पर कार्रवाई की गई है। फ्लैग मार्च निकाला गया। इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। 20 दिसंबर को हिंसा-बवाल करने वालों की तलाश जारी है।

सहारनपुर में जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा गत मंगलवार को ईदगाह मैदान में धरना और गिरफ्तारी का कार्यक्रम था। डीएम आलोक कुमार ने आयोजन को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। शनिवार को जमीयत ने ईदगाह मैदान में फिर धरना दिया।

इस दौरान सीएए और एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी हुई। मेरठ में शनिवार को हालात सामान्य रहे। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है। मुकदमों की संख्या बढ़कर 25 पर पहुंच गई है। मेरठ में हुई हिंसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की अहम भूमिका रही। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि उक्त संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।

तृणमूल का बंगाल में धरना

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीएए और एनआरसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को राज्य के सभी 294 विधानसभा (विस) क्षेत्रों में धरना दिया। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल के धरना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेता सीएए के खिलाफ मार्च कर रहे थे। लगता है कि वे थक गए हैं, इसलिए अब धरना का सहारा लिया है।

बिजनौर में हुए बवाल के मामले में पुलिस की ओर से 33 लोगों के खिलाफ जनता को भड़काकर बवाल कराने के आरोप में राजद्रोह के नोटिस के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई है।

पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

बिजनौर के नहटौर कस्बे में 20 दिसंबर को हुए बवाल में मारे गए सुलेमान के भाई शुएब ने शनिवार को तत्कालीन कोतवाल सहित छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।

असम से सीखा भाईचारा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

राहुल ने कहा कि उन्होंने असम से प्रेम एवं भाईचारा सीखा है और हर जगह इसका जिक्र करते हैं। कांग्रेस नेता बोले, 'पहले यहां हिंसा थी। फिर सब एक हुए और राज्य में अहिंसा, शांति एवं विकास ने कदम रखा। मुझे दुख है कि हालिया विरोध प्रदर्शनों में पांच युवाओं की मौत हुई है।' उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर गोली चलाने को लेकर सवाल किया।

जहां भाजपा, वहां हिंसा : राहुल ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा जाती है, वहां केवल घृणा, हिंसा और लोगों के बीच लड़ाई होती है। भाजपा लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहती। अगर लोग शांति से कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें प्रेम से सुनी जा सकती हैं।

दूसरी नोटबंदी है सीएए, एनआरसी : राहुल गांधी ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को दूसरी नोटबंदी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इनके जरिये सरकार एक बार फिर गरीब जनता को लाइन में खड़ा करना और अपने 15 उद्योगपति दोस्तों की मदद करना चाहती है। राहुल ने कहा, 'वे गरीब लोगों को अपने कागजात दिखाने के लिए कहेंगे, लेकिन उद्योगपतियों से नहीं। यह असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है।' राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी के लिए भी सरकार को जमकर घेरा।

भाजपा ने छह नेताओं को दी जागरूकता की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जागरूकता फैलाने और लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी छह नेताओं को सौंपी है। सीएए को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच सबसे ज्यादा अनिश्चितता वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की जिम्मेदारी अनिल जैन को दी गई है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यह बागडोर अविनाश राय को सौंपी गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा और दमन एवं दीव में लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी सरोज पांडे को मिली है। सुरेश भट्ट हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एवं जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारी संभालेंगे। दक्षिण में पार्टी ने रविंद्र राजू को जिम्मेदारी सौंपी है। वह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान, पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप में संवाददाता सम्मेलनों, बैठकों एवं लोगों तक पहुंचने के लिए अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। पूर्वी क्षेत्र का जिम्मा बंगाल में भाजपा के पूर्व प्रमुख राहुल सिन्हा को दिया गया है। वह बंगाल, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में सीएए को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। दमन एवं दीव, अंडमान और लक्षद्वीप जैसे छोटे केंद्रशासित प्रदेशों में जागरूकता अभियानों की तैयारी दिखाती है कि भाजपा देश के हर नागरिक को सीएए के प्रावधानों से संतुष्ट करने के प्रयास में है। इन छह नेताओं के अलावा पार्टी के विभिन्न सांसद और नेता भी देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे।

- उत्तर प्रदेश और बिहार की जिम्मेदारी अनिल जैन को दी गई है
- महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा और दमन एवं दीव में लोगों तक पहुंचने की जिम्मा सरोज पांडे के पास

मेरी रगों में अखंड हिंदुस्तान का खून : परवीन सुल्ताना

जागरण संवाददाता, जालंधर

मैं कलाकार हूं। नागरिकता संशोधन कानून या राजनीति में नहीं पड़ती। मेरे पास संगीत के अलावा किसी और काम के लिए समय नहीं है। मैं लोगों से भी यही उम्मीद करती हूं कि वह एकजुट होकर खूबसूरत हिंदुस्तान की खूबसूरती को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। संगीत मेरा जुनून है जो मुझे विरासत में मिला है। मेरी रगों में अखंड हिंदुस्तान का खून बह रहा है। मेरे पिता इकरामुल माजिद अफगानिस्तान व मां मरूफा बेगम ईरान की रहने वाली थीं। मेरा जन्म असम में हुआ। उक्त बातें शास्त्रीय संगीतकार पद्मश्री बेगम परवीन सुल्ताना ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में कहीं। वह यहां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में प्रस्तुति देने पहुंची थीं।

हिंदुस्तान में सभी को स्वीकार करने की हिम्मत : 25 वर्ष की आयु में पद्मश्री सम्मान पाने वाली सुल्ताना ने कहा कि 1972 में क्लियोपैट्रा ऑफ म्यूजिक,1976 में पद्मश्री हासिल करने के बाद मैंने कभी जिंदगी में पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश दूसरा नहीं है। इसमें सभी को स्वीकार करने की हिम्मत है।

संगीत ही मेरा जीवन : सुल्ताना ने कहा कि संगीत ही मेरा जीवन है। अपने पसंदीदा गानों को लेकर कहती हैं कि वैसे तो कई गाने पसंद हैं लेकिन कुदरत फिल्म में मेरे द्वारा गाया गया गीत ..हमें तुमसे प्यार कितना तथा 1920 एक लव स्टोरी फिल्म का गीत ..वादा तुमसे है वादा तथा गदर फिल्म का गीत ..आन मिलो सजना मेरे पसंदीदा गीत हैं।

पति दिलशाद खान मेरे गुरु, आज भी उनसे सीखती हूं : कहती हैं कि मुझे संगीत विरासत में मिला है। शास्त्रीय संगीत का ज्ञान मैंने मेरे पिता इकरामुल माजिद से मिला। आगे की शिक्षा उस्ताद दिलशाद खान साहब से ली है। उस्ताद दिलशाद खान साहब मेरे गुरु के साथ-साथ मेरे पति भी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे पति के रूप में उस्ताद दिलशाद खान साहब मिले। हम दोनों ने लगभग 1000 से भी ज्यादा प्रस्तुति देश-विदेश में जाकर दे चुके हैं। मैं अब भी उनसे संगीत सीखती हूं।

मिसाल

20 दिसंबर को ड्यूटी पर जा रहे सिपाही को पीट रहे थे उपद्रवी, हाजी कदीर ने वर्दी के ऊपर पहनाया पठानी सूट, हज का दुपट्टा

फरिश्ते ने अजय को रहमान बना बचाई जान

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद

जबरदस्त पथराव और फायरिंग के बीच उपद्रवियों के चंगुल में फंसे सिपाही की आंख के सामने मौत खड़ी थी। किसी भी पल जिंदगी जाने का अंदेशा था। ऐसे में फरिश्ते की तरह आए हाजी ने अपने हज का फर्ज अदा किया। सिपाही को रिश्तेदार बताकर उपद्रवियों से छुड़ाया, घर ले जाकर मरहम-पट्टी की, फिर उसे सुरक्षित थाने तक पहुंचाया। रास्ते में कोई दोबारा हमला न बोल दे, इसलिए सिपाही को पठानी सूट भी पहनाया। हज से लेकर आए दुपट्टे को गले में डाल दिया।

वाकया 20 दिसंबर की दोपहर तीन बजे के करीब का है। जुमा की नमाज के बाद उप्र के फीरोजाबाद शहर में उपद्रव शुरू हो चुका था। थाना उत्तर में तैनात सिपाही अजय कुमार शुक्रवार को उपद्रव के समय पुलिस लाइन स्थित आवास पर थे। तभी फोन कर उन्हें थाने बुलाया गया। अजय बाइक से चल पड़े। जाटवपुरी से पहले उपद्रवियों ने घेर कर पिटाई शुरू कर दी। उन पर ईंट-पत्थर बरसाने लगे। इसी बीच, हाजी कदीर उनके लिए फरिश्ते की तरह पहुंचे। वह उन्हें बचाकर घर लाए। चोट ज्यादा थी। सिपाही को अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन उपद्रव के माहौल में सिपाही को घर से बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं था, ऐसे में हाजी कदीर ने एक रास्ता निकाला।

उन्होंने सिपाही को वर्दी के ऊपर पठानी सूट पहना दिया। हज यात्रा से लेकर आए विशेष दुपट्टे को ऊपर डाल दिया। इसके बाद हाजी ने सिपाही को बाइक पर अपने पीछे बैठाया और रसूलपुर थाने की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सिपाही को हिदायत दी कि वह जब तक थाने नहीं पहुंच जाते, तब तक अपना नाम रहमान बताएं। उनकी युक्ति काम आई और वह सकुशल थाने पहुंच गए।

आंखों के सामने घूम गई परिवार की तस्वीर : सिपाही अजय का कहना है कि हाजी कदीर मेरे लिए भगवान बनकर आए। उपद्रवी जिस तरह से मुझे मार रहे थे, उससे लग रहा था कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस दौरान मुझे अपनी आंखों के सामने परिवार की तस्वीर नजर आने लगी थी। मैं ही नहीं, मेरा परिवार हाजी कदीर का पूरी जिंदगी अहसानमंद रहेगा।

शहर, गांव के मुख्य चौराहों पर लगेंगे अमनपसंदों के फोटो

गाजियाबाद : सीएए के विरोध में हुई हिंसा और प्रदर्शन के बीच जिन लोगों ने पुलिस-प्रशासन का सहयोग कर माहौल को बिगड़ने से बचाया, उनको अधिकारी अनोखे ढंग से सम्मानित करेंगे। अधिकारी न केवल उनका धन्यवाद करेंगे, बल्कि उनकी फोटो शहर, गांव के मुख्य चौराहों पर लगाए जाएंगे। ताकि वहां से गुजरने वाले लोग उनसे सीख लें। 10 दिन पहले जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, मेरठ, हापुड़ के साथ गाजियाबाद में बिगड़े माहौल को शांत करने में जितनी सूझबूझ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की रही, उससे कहीं ज्यादा योगदान अमन पसंद लोगों का भी रहा।

जन्म से श्रेष्ठता की बात सही नहीं, व्यक्ति कर्म से होता है श्रेष्ठ : भय्याजी जोशी

जागरण संवाददाता, रांची

- आरएसएस के सरकार्यवाह ने ऊंच-नीच समाप्त करने दिया जोर
- मंगलुरु में विहिप की तीन दिवसीय केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भय्या जी जोशी ने कहा कि हिंदू समाज में जन्म से श्रेष्ठता की जो बात हो रही है वह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। हमें एक सशक्त, संस्कारित, जागृत, सज्जन, स्वाभिमानी, पुरुषार्थी तथा विज्ञान के साथ चलने वाले ऐसे सक्रिय हिंदू चाहिए जो निर्दोष संगठित शक्ति का निर्माण कर विश्व को नेतृत्व देने में समर्थ हों।

भय्याजी जोशी शनिवार को मंगलुरु के संघ निकेतन में चल रहे विश्व हिंदू परिषद की तीन दिवसीय केंद्रीय प्रबंध समिति एवं प्रन्यासी मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे मूल्यों का क्षरण हुआ है। मातृभूमि के प्रति उदासीनता भी दिखाई देती है, जो मात्र दृष्टिकोण बदलने के कारण हुआ है। समाज से ऊंच-नीच समाप्त कर हमें एक समरस समाज बनाना है। गोरक्षा हमारे लिए केवल पशु रक्षा नहीं है। श्रीराम जन्मभूमि हमारे लिए स्वाभिमान का केंद्र है।

विहिप ने अनुच्छेद 29-30 में की संशोधन की मांग : विश्व हिंदू परिषद ने संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। मंगलुरु में चल रही बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। मांग की गई कि दोनों अनुच्छेदों में संशोधन कर अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का विस्तार करते हुए, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के भेदभाव को मिटाने के लिए उसमें सभी धार्मिक व भाषाई समुदायों को सम्मिलित किया जाए।

महिलाओं के साथ अभद्रता पर जताई चिंता : बैठक में संस्कारित, सबल व स्वावलंबी भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए देश में बढ़ती दुष्कर्म व महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना भी बनाई गई। महिलाओं की स्थिति पर पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इसे रोकने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। इसमें अभिभावकों, शिक्षाविदों, संत-महात्माओं, सामाजिक संगठनों, व मीडिया जगत से जुड़े लोगों के साथ शासन-प्रशासन को आगे आना होगा।

बैठक में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पाक्षिक पत्रिका हिंदू विश्व के धर्म जागरण विशेषांक का विमोचन किया गया।

125 करोड़ रजिस्ट्रेशन अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार आधार कार्ड के लिए हो चुके हैं। आधार को पहली बार सरकार ने वर्ष 2010 में लांच किया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 29 दिसंबर 2019

पूस के रात-दिन इसलिए हुए बहुत सर्द

पूस की रात अपनी सर्दी के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार रातों के साथ दिन भी सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जनजीवन सिकुड़ गया है। अलबत्ता तो घर में ही ठंड लग रही है, ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। दो लोगों के मिलने पर बातचीत की शुरुआत सर्दी के प्रकोप से ही हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसकी ही चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। ऐसे में इस बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही सर्दी की वजहों पर पेश है एक नजर:

श्रीनगर में सर्दी के कारण जमी डल झील और बर्फ में से रास्ता बनाता नाविक। ● एएनआइ

10 डिग्री से नीचे तापमान

अमूमन प्रति वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कुछ स्थानों पर तापमान दो से 4 डिग्री तक गिर जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी में दिसंबर महीने में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री से अधिक नहीं पहुंचता। दिल्ली, उत्तरी राजस्थान का तापमान इस महीने में 20 से 22 के आसपास रहता है। लेकिन इस बार अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है।

कितनी सर्द है यह ठंड

सर्दी की तीव्रता तय करने के लिए मौसम विभाग के कुछ पैमाने हैं। दिन में जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे ठंडा दिन माना जाता है। लेकिन जब यह गिरावट कम से कम 6.5 डिग्री हो जाए तो इसे गंभीर सर्दी की स्थिति कहते हैं।

सीकर में पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ। ● पेट्र

धर्मशाला में पेड़ पर बैठा उल्लू।

दिल्ली में सर्दी का इंतजाम करते और आग तापते लोग। ● एपी

1901 के बाद इतनी सर्द रही दिल्ली

27 दिसंबर तक दिल्ली में औसत अधिकतम तापमान 20 से कम ही रहा। दिल्ली में 118 वर्षों का रिकार्ड टूट गया है। इतने दिनों में ऐसा चार बार ही हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के लिए 1901 से अबतक का दूसरा सबसे ठंडा महीना दिसंबर है। 1901 के दिसंबर में यहां का अधिकतम औसत तापमान 17.3 था। दिल्ली में 14 से 27 दिसंबर के बीच लगातार 14 दिन काफी ठंडे रहे। 1997 के बाद से यह सबसे लंबी अवधि है। उस वर्ष लगातार 13 दिन शीतलहर की चपेट में रहे।

स्थिति अस्वाभाविक नहीं है

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की सर्दी में कुछ भी असामान्य नहीं है। सामान्यत: उत्तर और उत्तरपूर्व भारत में पश्चिमी हिस्से और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंडी हवाएं आती हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागर से नमीयुक्त हवा लेकर आता है। इस वजह से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश भी होती है। ठंड की तीव्रता जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की बर्फबारी पर भी निर्भर करती है। ये स्थितियां हर वर्ष समान नहीं रहतीं। बदलती रहती हैं। इसी के हिसाब से ठंड भी कम या ज्यादा पड़ती है।

बहुत नीचे स्तर पर बनने वाले बादल

भारत और पाकिस्तान के बड़े भूभाग में निचले स्तर पर छाये घने बादलों ने भी मौसम को सर्द करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु-गंगा के मैदानी भूभाग में ऐसे बादलों का बनना चकित करता है। 1997 से ही ऐसे बादल देखे जा रहे हैं। ये बादल तीन सौ से चार सौ मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये सूर्य की रोशनी को व्यापक स्तर पर रोक देते हैं। इसका नतीजा असामान्य ठंड के रूप में सामने आता है।

प्रचंड सर्दी की वजह

जलवायु परिवर्तन : मौसम विज्ञानियों के अनुसार दिसंबर में ऐसी असामान्य सर्दी पड़ने की वजहों में से एक जलवायु परिवर्तन भी है। इसके चलते पूरी दुनिया में लू और शीतलहर की असामान्य हालत पैदा हुई है। आने वाले समय में स्थिति और विषम होगी। भारत के अलग-अलग इलाकों में बेमौसम बारिश से मौसम विज्ञानी भी हैरान थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अनिश्चितता की स्थिति ऐसी हो गई कि मौसम को भांपना मुश्किल हो गया है। इसके कारण लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पश्चिमी विक्षोभ : सर्दी की एक वजह यह भी है। अक्सर सामान्य से गंभीर पश्चिमी विक्षोभ की स्थितियां बन रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी की तरफ से हवाएं काफी नीचे के स्तर से बहने के कारण ठंड में इजाफा होता गया। इसके साथ दिसंबर में हर पश्चिमी विक्षोभ के बाद पैदा हुए धुंध, कुहासा और बारिश ने इसे बढ़ाने का काम किया।

न्यूज गैलरी

नहीं रहे 'मेरा नाम जोकर' के बौने कलाकार नत्थू दादा

राजनांदगांव : राजकपूर, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कई नामी सिने हस्तियों के साथ फिल्मों में काम कर चुके बौने कलाकार नत्थू दादा का 70 वर्ष की उम्र में शनिवार तड़के चार बजे निधन हो गया। छोटे कद के बड़े कलाकार नत्थू दादा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रामपुर गांव के रहने वाले थे। नत्थू दादा ने करीब 20 साल के अपने फिल्मी सफर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकपूर के साथ 'मेरा नाम जोकर' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले नत्थू दादा इन दिनों गरीबी में जीवन बसर कर रहे थे। उनका अंतिम संस्कार गृह ग्राम रामपुर में किया गया। 1969 में भिलाई में जब फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उस समय नत्थू दादा अपने साथी के साथ दारा सिंह को देखने भिलाई पहुंचे थे। तब दारा सिंह ने भीड़ के बीच उन्हें अपने हाथों में उठा लिया था। दारा सिंह ने ही उन्हें मायानगरी (मुंबई, तब की बांबे) में राज कपूर से मुलाकात करवाई। 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में नत्थू दादा ने अभियन की शुरुआत की। (नईदुनिया)

नत्थू दादा फाइल

सेना ने सिक्किम में फंसे 1700 पर्यटकों को बचाया

गंगटोक : भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के नाथू ला दर्रे के पास फंसे करीब 1,700 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। करीब 300 वाहनों में 1500 से 1700 के आसपास पर्यटक गंगटोट से यात्रा कर रहे थे। एक सरकारी बयान के अनुसार भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार शाम को जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पर्यटक फंस गए। उस समय पर्यटक नाथू ला की त्सोमगो झील से लौट रहे थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब 1,700 यात्रियों को निकाला गया। उनमें से 570 लोगों को सेना के शिविर में ठहराया गया है। पर्यटकों को खाना, गरम कपड़े और दवाएं उपलब्ध कराई गईं। बर्फ हटाने के लिए और संपर्क बहाल करने के लिए सेना बुलडोजर एवं क्रेन की मदद ले रही है। पर्यटकों के गंगटोक लौटने तक राहत अभियान जारी रहेगा। (प्रेट्र/आइएएनएस)

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या

कोलकाता : बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका नाम रहीम शेख था। फायरिंग में तीन लोग जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात रहीम दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। भारती मोड़ के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगने से रहीम वहीं गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने जब हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उनपर भी गोलियां बरसा दी और भाग खड़े हुए। फायरिंग में तीन लोग जख्मी हो गए। (जासं)

कर्मनाशा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त

हादसा ▶ उत्तर प्रदेस का कई राज्यों से संपर्क टूटा, 450 करोड़ रुपये की लागत से बना था

जागरण संवाददाता, चंदौली

उप्र-बिहार सीमा पर स्थित कर्मनाशा नदी पर 450 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-2 पर बना पुल शुक्रवार देर रात ओवरलोड वाहनों के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के पूर्वी छोर के शुरुआती चार पिलर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे सड़क का ऊपरी हिस्सा धंस गया। इस दौरान पुल से गुजर रहे वाहन चालकों में अफरातफरी मच गई। पुल पर मौजूद वाहनों को लेकर किसी तरह चालक पश्चिमी छोर पहुंचे। अब वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से उप्र का बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड से संपर्क टूट गया है।

मार्ग बंद होते ही उप्र छोर पर लगभग दस किमी वहीं बिहार में 20 किमी वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस बैरिकेडिंग कर छोटे वाहनों को नौबतपुर बाजार में नदी पर बने 100 साल पुराने पुल से गुजार रही है। कर्मनाशा नदी पर करीब 254 मीटर लंबा पुल बनाया गया था।

2003 में शुरू हुए पुल का निर्माण 2009 में पूरा हुआ और वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इसके निर्माण में तकरीबन 450 करोड़ रुपये लागत आई थी और 30 वर्ष इसकी मियाद निर्धारित की गई थी। इस पुल से प्रतिदिन ढाई से तीन हजार ट्रकों के अलावा हजारों छोटे वाहनों का आवागमन होता था।

ओवरलोड ट्रकों की कतार से हुई घटना : शुक्रवार को पुल के दोनों छोर पर बालू लदे करीब ढाई सौ ओवरलोड ट्रक लाइन में खड़े थे, पुल भार नहीं झेल सका और उसके पूर्वी छोर के चार पाए टूट गए। इससे पुल का ऊपरी हिस्सा भी धंस गया। कार्यदायी संस्था की ओर से पुल की देखरेख व मरम्मत हर माह होनी चाहिए, लेकिन करीब एक साल से मरम्मत नहीं हो सकी थी।

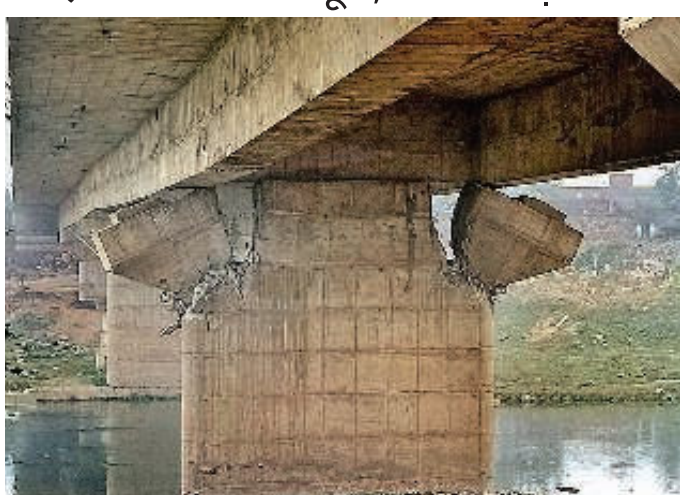

चंदौली (उप्र) में कर्मनाशा नदी पर बने पुल का खंभा वाहनों के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गया। जागरण

- 2009 में पुल पर शुरू हुआ आवागमन, 30 साल थी मियाद
- पुल से रोजाना तीन हजार ट्रकों के अलावा हजारों छोटे वाहनों का आवागमन होता है

'एक साथ सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड वाहनों के खड़े होने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसकी जांच कराई जाएगी। निर्माण इकाई प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पीसीएल) की भी जांच होगी। वैसे आवागमन के लिए क्षतिग्रस्त पुल के दोनों ओर अस्थाई व्यवस्था कराकर मार्ग को चालू कराया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन दिन रात काम चलेगा।'

- कर्नल योगेश गढ़वाल, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआइ

केंद्रीय मंत्री ने ली जानकारी

केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने पुल के क्षतिग्रस्त होने का संज्ञान लिया। जिलाधिकारी से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य आरके पांडेय से वार्ता कर तत्काल यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के साथ पुन: स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा कि 2009 में बनकर तैयार हुए इस पुल के मात्र 10 वर्ष में क्षतिग्रस्त होने की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सिख ने मस्जिद के लिए दी जमीन, बन सकेगा हाईवे

सत्येन ओझा, मोगा

- मोगा के दर्शन सिंह ने 16 मरले जमीन दान कर पेश की मिसाल
- गांव के मुस्लिम समुदाय ने भी 250 साल पुरानी मस्जिद शिफ्ट करने की दी सहमति

पंजाब में मोगा के गांव माछीके के किसान दर्शन सिंह सेखों की पहल से नेशनल हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने हाईवे की जद में आ रही मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए 16 मरले जमीन दान कर दी है। गांव के मुस्लिम समुदाय ने भी देश हित में 250 साल पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने पर सहमति दे दी है।

जालंधर-बरनाला हाईवे पर कस्बा निहालसिंह वाला के तहत गांव माछीके में मस्जिद हाईवे के बीच आ रही है। ये हाईवे जालंधर से मोगा शहर तक पूरी तरह बन गया है, लेकिन मोगा-बरनाला के बीच कुछ स्थानों पर अधूरा पड़ा है। माछीके में हाईवे का निर्माण मस्जिद के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था।

छह साल से अटका था मामला : यह मामला पिछले छह सालों से अटका हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, वे इसके लिए तैयार भी हो गए थे। मामला डिप्टी कमिश्नर व पंचायत के बीच कई सालों से चल रहा था। पंचायत मस्जिद के लिए जो जगह उपलब्ध करा रही थी, वह गांव से दो किलोमीटर दूर है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय वहां मस्जिद बनाने के लिए तैयार नहीं था। गांव में मुस्लिम समुदाय के 15 परिवारों की आबादी लगभग 100 है।

मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के नाम रजिस्ट्री : एक सप्ताह पहले दर्शन सिंह सेखों ने गांव में ही अपनी 16 मरले जमीन देने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया। यह प्रस्ताव मिलने से प्रशासन की बड़ी समस्या हल हो गई। सेखों ने भी जमीन बिना किसी शर्त के निशुल्क मस्जिद के लिए दे दी। मौजूदा रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत साढ़े सात लाख रुपये बनती है। एक सप्ताह पहले इस जमीन की रजिस्ट्री भी गांव की मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के नाम करा दी।

मुस्लिम समुदाय खुश

सोसायटी के अध्यक्ष रूप मोहम्मद ने गांव में मस्जिद के लिए जगह मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही मस्जिद का निर्माण कराकर पुराने स्थान की मस्जिद को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। दर्शन सिंह के प्रस्ताव से पूरा मुस्लिम समुदाय खुश है।

पार्टी फंड के नाम पर हरियाणा के मंत्री से मांगे तीन करोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मोबाइल नंबर को स्पूफ करके हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से पार्टी फंड के नाम पर तीन करोड़ रुपये की मांग की गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के दादा हैं। वह निर्दलीय चुनाव जीते थे और भाजपा का समर्थन करने पर उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते में चंडीगढ़ निवासी उपकार सिंह और सिरसा के जगतार सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मोबाइल नंबर को स्पूफ करके रणजीत सिंह चौटाला को फोन किया। इसमें उनसे पार्टी फंड के लिए तीन करोड़ रुपये की मांग की गई। गृह मंत्रालय से फोन आने की वजह से उन्होंने पैसे देने की बात से इन्कार नहीं किया, लेकिन बार-बार कॉल आने से शक जरूर हुआ। उन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत की। सेल ने नंबर को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। सेल के कहने पर रणजीत सिंह ने शुक्रवार को पैसे ले जाने के बहाने उपकार सिंह को हरियाणा भवन में बुलाया। इंडिया गेट पर पहुंचते ही उपकार सिंह ने मंत्री को कॉल की, तभी उसकी लोकेशन का पता लगाकर स्पेशल सेल की टीम ने दबोच लिया। उससे पूछताछ कर जगतार सिंह को चंडीगढ़ से पकड़ा गया। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण स्पेशल सेल के अधिकारियों ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है। सेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों के पास जानकारी थी कि मंत्री के पास काफी पैसे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय के नाम पर वह आसानी से पैसे दे देंगे। इसलिए उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। दोनों के खिलाफ जालसाजी के पुराने मुकदमे होने की कोई जानकारी अभी सेल को नहीं मिली है।

क्राइम पेट्रोल से आया आइडिया : उपकार सिंह का चंडीगढ़ का रहने वाला है। वह एमएससी व पीएचडी है। जबकि सिरसा का जगतार टैक्सी स्टैंड चलाता है। दोनों चंडीगढ़ में एक फ्लैट बुक कराने के दौरान मिले थे। आरोपितों का कहना है कि पैसे की कमी थी। क्राइम पेट्रोल देख कर उन्हें इसका आइडिया आया। इसके लिए वे कॉल स्पूफिंग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी कॉल कई सर्वर से होकर जाती है और पकड़ना मुश्किल होता है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों तक पहुंची।

तीन करोड़ मांगने की बात अफवाह : रणजीत सिंह

उधर, सिरसा में रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के नाम से तीन करोड़ रुपये मांगने की कोई फोन कॉल नहीं है। किसी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई है।

राजदीप सरदेसाई पर पोल के लिए अमित मालवीय की आलोचना

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर आक्रामक ऑनलाइन पोल चलाने के लिए भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड ने सत्तारूढ़ पार्टी से कहा है कि वह इस मामले में अपने पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दे। अमिक मालवीय से कथित ट्विटर पोल हटाने के लिए भी कहा गया है।

दरअसल, मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऑनलाइन पोल चलाया। इसमें पूछा गया कि क्या राजदीप सरदेसाई को आइएस के जनसंपर्क का काम देखना चाहिए? उन्होंने ट्विटर यूजरों को जवाब के लिए चार विकल्प भी दिए- सहमत, दृढ़तापूर्वक सहमत, असहमत और वे अप्रासंगिक हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि मालवीय के इस निंदनीय कृत्य से उसे हैरानी हुई है। ट्विटर पर चलाया गया यह पोल न सिर्फ बेमजा है, बल्कि यह सरदेसाई की ईमानदारी और देशभक्ति पर भी सवाल उठाता है, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं।

एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि यह ऑनलाइन पोल स्वस्थ बहस और असहमति के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी इसकी आलोचना की है और कहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता का यह बर्ताव अपमानजनक है।

हनी ट्रैप मामले में व्यवसायी, अफसर व मीडियाकर्मी भी थे शामिल

अनिल शुक्ला, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की चार आरोपितों के खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में एसआइटी (विशेष जांच दल) द्वारा भोपाल की जिला अदालत में पेश चालान में कई चौंकाने वाले राजफाश हुए हैं। चालान में मानव तस्करी मामले की पीड़िता और हनी ट्रैप मामले की आरोपित मोनिका यादव ने पुलिस को दिए बयानों में बताया है कि इन आरोपितों के साथ मध्य प्रदेश के कई बड़े व्यवसायी, मीडियाकर्मी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।

शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित श्रीवास्तव की अदालत में पेश चालान से पता चला है कि मामले में आरोपित आरती दयाल, श्वेता विजय जैन के साथ व्यवसायी अरुण सहलोत और मीडियाकर्मी वीरेंद्र शर्मा छह-सात वर्षों से मिलकर काम करते थे। मानव तस्करी मामले में पीड़ित युवती मोनिका यादव ने एसआइटी को दिए बयानों में बताया है कि अरुण सहलोत ने ही आइएएस पीसी मीणा के अश्लील वीडियो वायरल किए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद श्वेता विजय जैन और आरती दयाल के बीच दूरियां बन गई थीं।

मोनिका ने बयानों में बताया है कि आरोपितों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने वाले हर मामले में एक अन्य मीडियाकर्मी गौरव शर्मा ही माध्यम होता था और मीडियाकर्मियों के माध्यम से ही ब्लैकमेल के पैसों का लेन-देन होता था। आरोपितों ने ब्लैकमेलिंग के जरिये ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी ठेके दिलाने का काम ले रखा था। इस मामले में छतरपुर के एक थाना प्रभारी की भी भूमिका सामने आई है, जिसे आरोपितों द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने संबंधी सभी बातें मालूम थीं।

मोनिका ने बयान में बताया कि आरती दयाल ने छतरपुर में एक स्थानीय नेता मनोज त्रिवेदी का अश्लील वीडियो बनाया था। वह उससे मोटी रकम वसूलना चाहती थी, लेकिन उस थाना प्रभारी ने आरती को बताया कि मनोज प्रभावशाली नेता है। उसकी बात सुनकर आरती ने मनोज को ब्लैकमेल करने का इरादा छोड़ दिया था। आरोपितों ने छतरपुर के कार शोरूम संचालक मनीष अग्रवाल, भोपाल के व्यवसायी नरेश सीतलानी, खुद को सरकारी अफसर बताने वाले अरुण निगम व हरीश खरे को ब्लैकमेल करके मोटी रकम और सरकारी ठेके हासिल किए थे। ब्लैकमेलिंग के जरिये आरोपितों ने आइएएस पीसी मीणा से 20 लाख रुपये, व्यवसायी नरेश सीतलानी से पांच लाख रुपये और एक अन्य आइएएस अधिकारी से एक करोड़ रुपये लिए थे। इस मामले में मीडियाकर्मी गौरव शर्मा भी शामिल था, जिसके हिस्से में 33 लाख रुपये आए थे। गौरव शर्मा ही पूरे पैसों का सेटलमेंट कराता था। इस मामले में एसआइटी पूरक चालान पेश करेगी, जिसमें गौरव शर्मा और ओमप्रकाश नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

एसआइटी ने चालान में बताया है कि आरोपित आरती दयाल की गुलाबी डायरी में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर संबंधी जानकारी और अंतरंग वीडियो के आधार पर की गई ब्लैकमेलिंग से करोड़ों की उगाही की जानकारी दर्ज है।

मेरी कॉम के बर्ताव से आहत हुईं निखत

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

निखत ने कहा, मेरी कॉम ने जैसा बर्ताव किया, उससे मैं आहत हुई हूं। उन्होंने रिंग के अंदर भी कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक है। मैं जूनियर हूं, मुकाबला खत्म होने के बाद अगर वह गले लग जाती तो यह अच्छा होता। लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उन्होंने मुकाबले के बाद भी मुझे अपशब्द कहे लेकिन कोई बात नहीं।'

तेलंगाना का विरोध : तेलंगाना मुक्केबाजी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे एपी रेड्डी ने मेरी कॉम की जीत के फैसले का जोरदार विरोध किया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बाई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने बीच में आकर हालात नियंत्रित किए। अजय सिंह ने उन्हें रिंग के पास से हटने को कहा और निराश निखत ने खुद उन्हें शांत कराया। बाद में एपी रेड्डी ने कहा कि इस तरह की राजनीति में मुक्केबाजी आगे कैसे बढ़ेगी। वहीं, अजय सिंह ने कहा कि मेरी कॉम के बारे में कोई क्या कह सकता है, यह हमेशा ही कम होगा। उन्होंने कहा कि मेरी कॉम एक प्रतिभाशाली मुक्केबाज हैं। जहां तक निखत की बात है तो वह भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद हैं और उन्होंने इस मुकाबले में भी प्रभावित किया।

तैयारी

श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र के ऑडिटोरियम में उपलब्ध होगी सुविधा

नववर्ष पर मां वैष्णो की अटका आरती होगी लाइव

राकेश शर्मा, कटड़ा

माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नववर्ष पर आधार शिविर कटड़ा में मां वैष्णो देवी की दिव्य लाइव अटका आरती की सुविधा शुरू कर रहा है। जनवरी में यह सुविधा आधार शिविर कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र के ऑडिटोरियम में उपलब्ध होगी।

वातानुकूलित ऑडिटोरियम में 450 श्रद्धालु बैठकर स्क्रीन पर लाइव अटका आरती का आनंद ले सकेंगे। श्राइन बोर्ड 70 एमएम की सिल्वर स्क्रीन लगाएगा। वहीं, डॉलबी सिस्टम लगाया जाएगा। लाइव आरती के दौरान बिजली कटौती से किसी भी तरह की रुकावट न पड़े, इसके लिए त्रिस्तरीय बिजली व्यवस्था की जाएगी। ऑडिटोरियम इस तरह से अत्याधुनिक बनाया जाएगा कि श्रद्धालु खुद को प्राचीन गुफा के प्रांगण यानी अटका आरती स्थल पर बैठा महसूस कर सकें।

मिलेंगी सुविधाएं

लाइव अटका आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में क्लॉक रूम के साथ ही शौचालय आदि की सुविधा भी मिलेगी। जलपान केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, ताकि आरती में शामिल श्रद्धालु खरीद कर चाय-कॉफी आधी पी सकें।

माता वैष्णो देवी। फाइल

क्या है अटका आरती :

हर श्रद्धालु यह उम्मीद करता है कि उसे भी मां वैष्णो देवी की आरती में शामिल होने का मौका मिले। लेकिन मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का प्रांगण, जिसे अटका स्थल भी कहा जाता है, सीमित स्थल होने के कारण हर कोई दिव्य आरती में शामिल नहीं हो सकता है। सीमित जगह होने के कारण एक बार में 200 से 300 श्रद्धालु ही बैठ सकते हैं। वहीं, अटका आरती का 2,000 रुपये प्रति श्रद्धालु शुल्क होने के कारण हर श्रद्धालु इसमें शामिल नहीं हो पाता।

श्राइन बोर्ड के केंद्रों में खोले जाएंगे बुकिंग काउंटर

लाइव अटका आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आध्यात्मिक केंद्र के साथ ही यात्रा पंजीकरण केंद्र, पूछताछ एवं आरक्षण केंद्र, निहारिका कांप्लेक्स आदि में बुकिंग काउंटर खोले जाएंगे, ताकि श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा कर इस लाइव अटका आरती में शामिल हो सकें।

श्रद्धालुओं से लिया जाएगा मामूली शुल्क : लाइव अटका आरती में शामिल होने के लिए मामूली शुल्क होगा, जो 20 से लेकर 50 रुपये के बीच हो सकता है।

श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रसाद : लाइव अटका आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को निशुल्क मिश्री का प्रसाद उपलब्ध करवाने के साथ ही मां वैष्णो देवी की आरती की किताब व पटका आदि भी निशुल्क दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे मां वैष्णो देवी की दिव्य आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है।

पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया नित्यानंद स्वामी का आश्रम

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- आश्रम दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में अवैध रूप से बनाया गया था
- आश्रम की दो संचालिकाएं फिलहाल गुजरात में न्यायिक हिरासत में हैं

दो साधिकाओं के अचानक लापता होने के बाद विवादों में आए नित्यानंद स्वामी के आश्रम को अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। यह आश्रम दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में अवैध रूप से बनाया गया था। उधर, दोनों लापता साधिकाओं के वेस्टइंडीज के बारबडोस में होने का पता चला है।

नित्यानंद स्वामी के पूर्व साधक ने बेंगलुरु आश्रम से अपनी दो पुत्रियों को उनकी मंजूरी के बिना अहमदाबाद आश्रम में लाने पर विरोध जताया था।

इस मामले में पुलिस शिकायत के बाद जांच हुई तो पता चला कि आश्रम डीपीएस स्कूल परिसर में गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में डीपीएस संचालकों व आश्रम संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इसी बीच, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को नित्यानंद के आश्रम पर हथौड़ा चला दिया। आश्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उधर, लापता बहनों ने हाई कोर्ट को भेजे अपने शपथपत्र में भारत में खुद की जान को खतरा बताते हुए यहां आने पर पुख्ता सुरक्षा की मांग की है।

अहमदाबाद आश्रम की दो संचालिका प्राणप्रिया और तत्वप्रिया फिलहाल गुजरात में न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों पर मासूम बच्चों के साथ मारपीट करने और बालआश्रम के अलावा अपहरण जैसे संगीन आरोप हैं।

छह प्रावधान करेंगे समाधान

विवेक कौल
अर्थशास्त्री और इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक

करीब महीने भर बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। एक फरवरी, 2020, को पेश होने वाले इस बजट से देश को काफी आशाएं हैं। देश देखना चाहता है कि वित्तमंत्री और सरकार आर्थिक सुस्ती को कम करने के लिए, क्या क्या कदम उठा सकती हैं। चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त के बीच देश की जनता के कल्याण से जुड़ा यादगार और आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश करने की उनसे उम्मीदें हैं। छह हथियारों के इस्तेमाल से वित्तमंत्री बजट का सिक्सर लगा सकती हैं।

1 सबसे पहले तो वित्तमंत्री और सरकार के लिए जरूरी है कि वो भारत में चल रही आर्थिक सुस्ती को थोड़ा गंभीरता से लें। अभी तक सरकार और उसके मंत्री देश को ये समझाने में लगे हैं कि आर्थिक सुस्ती भारत में है ही नहीं। ये सही नहीं है। किसी समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम उस समस्या को मानने की जरूरत होती है। बजट इस समस्या को मानने का अच्छा मौका है।

2 आर्थिक सुस्ती का एक प्रमुख कारण आर्थिक खपत में आयी सुस्ती है। लोग काफी वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला खर्च कम कर रहे हैं या फिर कई क्षेत्रों में हो रहे निजी उपभोग की विकास दर में पहले जैसी वृद्धि नहीं हो रही है। इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सरकार लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दे। इसका सरल और सबसे तेज तरीका है आयकर में कटौती करना। अगर वित्तमंत्री आयकर के साथ छेड़-छाड़ नहीं करना चाहतीं तो आयकर के स्लैब बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आयकर में जो अलग अलग किस्म की छूट और डिडक्शन मिलते हैं, इनमें भी वृद्धि की जा सकती है। इससे आयकर देने वालों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा और उनके इस पैसे को खर्च करने की संभावना बढ़ जाती है। जब वो ऐसा करेंगे तो व्यापर का फायदा होगा। इससे आर्थिक विकास दर में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। बहुत लोगों का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग आयकर नहीं देते हैं। इसलिए इस कदम से अर्थव्यवस्था को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। पर यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि ये कतई जरूरी नहीं कि बहुत सारे भारतीय एक साथ पैसा खर्चा करना शुरू करें। जब आयकर में कटौती होगी, इससे आयकर देने वाले लोग पैसा खर्च करेंगे। इससे और लोगों की आय बढ़ेगी। एक आदमी का खर्च किसी और आदमी की आय होता है। जब इन लोगों की भी आय बढ़ेगी तो इनके भी पैसे खर्च करने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे अर्थव्यवस्ता में गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) काम करेगा और अर्थव्यवस्था का पहले से ज्यादा तेजी से विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी।

3 अगर सरकार आयकर से कम पैसे कमाएगी तो उससे कहीं और से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आयकर में कमी आने की वजह से निजी खपत बढ़ेगी तो सरकार माल और सेवा कर से ज्यादा पैसे कमा सकती है। इसके अलावा ये जरूरी हो जाता है कि सरकार विनिवेश से अच्छे पैसे कमाए। लिहाजा विनिवेश का जरूरी लक्ष्य जल्दी हासिल किया जाए। अमूमन सरकारें विनिवेश पर साल के दूसरे हिस्से में ही ध्यान देती हैं।

4 सरकार अपना पैसा सोच समझ कर उन क्षेत्रों पर खर्च करे जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसाकि अंग्रेजी में कहते हैं, देअर शुड बी मोर बैंग फॉर द बक। विजय केलकर और अजय शाह अपनी किताब इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक में लिखते हैं कि 10,000 किमी का चार लेन हाईवे बनाने में करीब एक लाख करोड़ रूपए खर्च होता है। तो ये जरूरी है कि सरकार इस किस्म का खर्च करे ताकि खस्ते पड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को बचाने में पैसा लगे।

5 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के पास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई है। सरकार इस जमीन को धीरे धीरे बेच कर पैसा कमा सकती है। इससे देश के भौतिक मूल ढ़ांचे को सुधारा जा सकता है।

6 अंत में, वित्तमंत्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो पिछले साल जैसा बजट, जहां उन्हें बहुत सरकारी चीजों को उलटना पड़ा था, बिल्कुल न पेश करें।

आम बजट बने खास

अर्थव्यवस्था की विकास दर छह साल की सबसे तलहटी पर है। खुदरा महंगाई कुछ हद तक नियंत्रण में है लेकिन अचानक कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें सुरसा के मुंह की तरह खुलने लगती हैं तो आम जनता बजरंगबली के प्रतिकूल आकुल होने लगती है। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन लगातार दूसरी बार गिरा है। आधारभूत क्षेत्र का आउटपुट अक्टूबर में 5.8 फीसद पर जा चुका है। पिछले 14 सालों में यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जीएसटी संग्रह सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। 2017-18 और 2018-19 में रोजगार सृजन की दर क्रमशः 3.9 फीसद और 2.8 फीसद रही है। कई राज्यों की वित्तीय स्थिति उनके अपने कर्मों के चलते खराब है। लोकलुभावन घोषणाओं के मद में खजाना लुटाने वाले राज्य केंद्र की ओर ताकते नजर आते हैं। खेती-किसानी की अपनी दिक्कतें हैं। आम बजट 2020-21 की तैयारियां जोरों पर हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी अपेक्षाएं साझा कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव ये भरोसा दिलाती है कि खुद के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गति देने की इसमें कूवत है। पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी तेज विकास दर से पाने की परीक्षा होगी। लिहाजा उन्हें आय और व्यय में संतुलन साधने के लिए कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। देश के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए वित्तमंत्री को आम नहीं खास बजट पेश करना होगा। ऐसे में वर्तमान आर्थिक हालातों के बीच खास बजट की उम्मीद करना हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

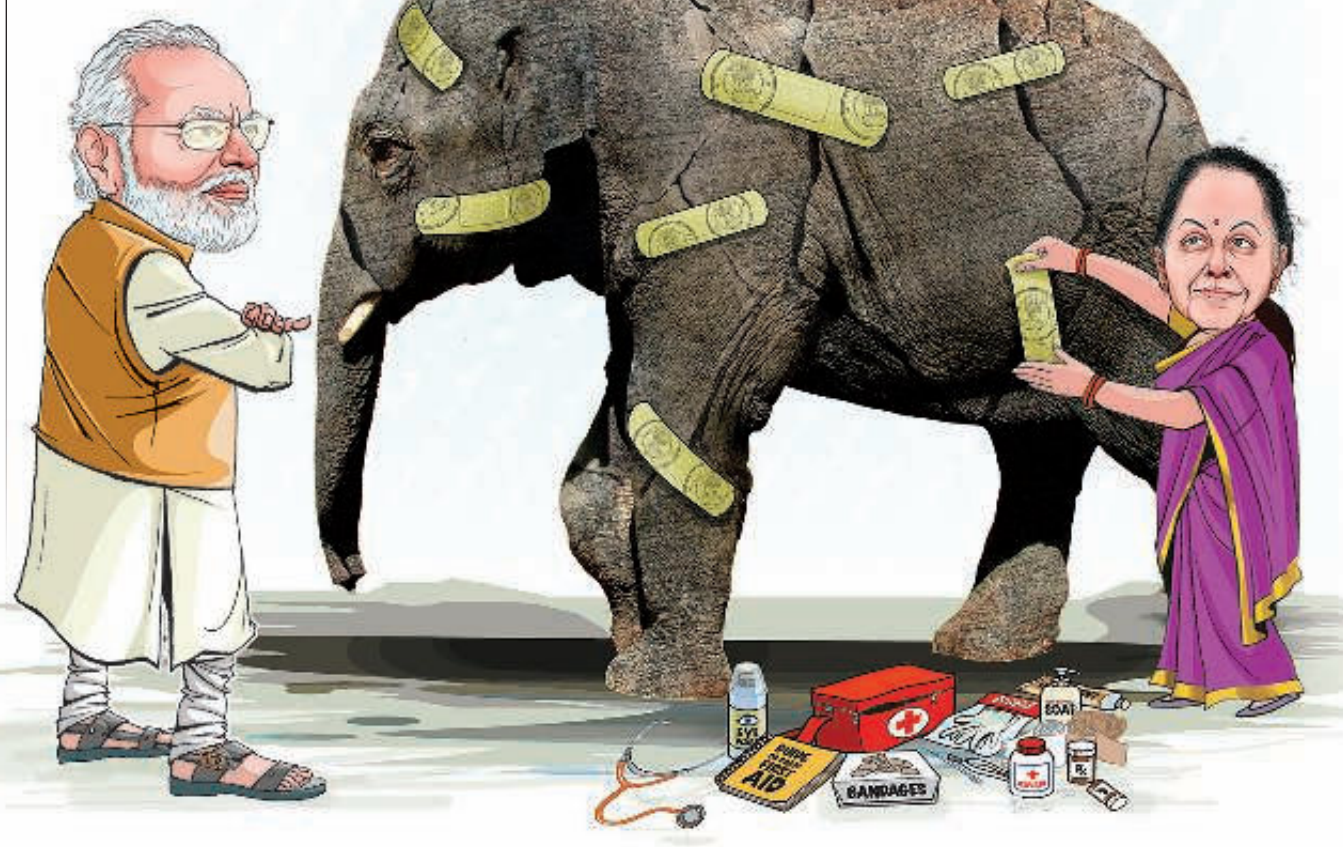

चहुंतरफा चुनौती

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ वक्त से धीमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों साफ किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती जरूर है, लेकिन मंदी का डर नहीं है। बावजूद इसके कई ऐसे पहलू हैं, जिनसे मंदी की आहट साफ सुनी जा सकती है। ऐसे में आगामी बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार की कोशिशों से पहले जानिए आखिर कहां-कहां है सुधार की जरूरत और कौन से सेक्टर बदहाली में हैं।

वैश्विक हालात भी बेहतर नहीं

अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के बाद मचे बवाल के बीच दुनिया पिस रही है। उस पर नीतियों की अनिश्चितताओं ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह संकट ज्यादा देखा जा रहा है। वैश्विक जीडीपी विकास दर 3 फीसद है। यह पिछले साल की अपेक्षा 0.6 फीसद कम है। जबकि व्यापार वृद्धि दर 2018 के 3.8 के मुकाबले घटकर के 1.1 हो गई है।

आर्थिक बदहाली

दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था थम सी गई है। सितंबर में खत्म दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर घटकर 4.5 फीसद रह गई। यह मार्च 2013 के बाद सबसे सुस्त चाल है। मार्च 2013 में विकास दर 4.3 थी।

रुपये का गिरना जारी

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट लगातार जारी है। जुलाई के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 68.9 थी, लेकिन एक महीने में ही यह 72 के पास पहुंच गया। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 71.43 है।

मांग में कमी

भारत में वस्तुओं की मांग में काफी कमी आई है। यह किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसा ही है। निजी उपभोग में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद का करीब 60 फीसद है।

5 ट्रिलियन का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है। हालांकि इन हालातों में यह काफी मुश्किल लगता है। इसका कारण है कि हम अभी आधे रास्ते से कुछ ही आगे पहुंचे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था करीब 2.9 ट्रिलियन की है। पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को करीब 8 फीसद की रफ्तार चाहिए, लेकिन इसकी सूरत दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है।

किसानों का हाल

2019 की दूसरी तिमाही में कृषि अर्थव्यवस्था 4335.47 अरब रुपये थी जो तीसरी तिमाही में गिरकर 3651.61 अरब पहुंच गई। 2011 से 2019 तक कृषि अर्थव्यवस्था का औसत 4126.42 था। आज हम इस औसत से भी नीचे आ गए हैं, जबकि 2018 की चौथी तिमाही में यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 5869.41 अरब पर पहुंची थी। वहीं 2011 के तीसरी तिमाही में यह अपने सबसे कम स्तर 2690.74 अरब पर पहुंच गई थी।

रोजगार की स्थिति

रेटिंग एजेंसी केयर के मुताबिक, 2017-18 में रोजगार की दर 3.9 फीसद थी, जो 2018-19 में गिरकर 2.8 फीसद रह गई है। एजेंसी के मुताबिक, बड़े उद्योग वास्तविकता में रोजगार में नकारात्मक विकास के गवाह हैं।

निर्यात में गिरावट

अप्रैल 1991 से नवंबर 2019 के दौरान औसत निर्यात दर 10.8 फीसद रही है। नवंबर 2019 में सालाना कुल निर्यात में 0.34 फीसद की कमी आई है। नवंबर में भारत का कुल निर्यात 26 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसी महीने में कुल आयात 38.1 अरब डॉलर रहा। इस महीने का घाटा 12.1 अरब अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। अगस्त से हर महीने निर्यात नकारात्मक ही रहा है। अगस्त 2019 में निर्यात में 6.180 फीसद की गिरावट थी जो सितंबर में 6.303 और अक्टूबर में 0.980 दर्ज की गई है।

मर्ज समझकर लगाएं मरहम

डॉ विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु, वित्तीय एवं समग्र विकास विशेषज्ञ

गरीबी मिटाने और गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था को 9 फीसद की दर से बढ़ाना होगा। ये बात केंद्रीय वित्तमंत्री अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन बजट का दिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला। विभिन्न सेक्टर के लिए खर्च और आवंटन की सरकार की मंशा बजट से पारिभाषित होती है। हर आर्थिक भागीदार इसे समझता है। भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। कुछ दीर्घ और सूक्ष्म स्थितियां मंदी को और तेज कर रही हैं। ये बातें अतिशयोक्ति लग सकती हैं लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

संकेत और शोर

18 दीर्घ संकेतांकों के अध्ययन का निचोड़ यह है कि इनमें से 11 तो पांच साल के औसत में सबसे निचले स्तर पर हैं। उपभोक्ताओं से जुड़े क्षेत्रों के कमजोर संकेत औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। आधारभूत संकेतक जैसे मूल्य संकेत (मांग बनाम आपूर्ति) भी गिर रहे हैं। इसी तरह, आर्थिक वृद्धि के चार स्तंभ निजी निवेश, सरकारी व्यय, घरेलू उपभोग और निर्यात की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ता आधारित है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60 फीसद का योगदान देती है। लेकिन यह हांफ रही हैं। तीन सौ सहायक उद्योगों को जोड़ने वाले रियल स्टेट की स्थिति भी डावांडोल है। ऑटो सेक्टर उबड़-खाबड़ रास्ते पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति भी ठीक नहीं है। सरकार इन्कार की मुद्रा में बिल्कुल नहीं हैं। जीएसटी, आइबीसी, डिजिटाइजेशन जैसे सुधारात्मक कदम अच्छे हैं लेकिन इनका फायदा नहीं दिख रहा। वैसे यह आने वाले कल की बात है, और उससे पहले आज है।

आशा से समृद्ध होती है अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए समग्र नीतिगत ढांचे और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी है जो विनियामक मंजूरी, कड़ी प्रक्रियाएं, समान भूमि अधिग्रहण, शीघ्र कार्यान्वयन, नवाचार को बढ़ावा और परिणामों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाए। बोझिल विनियमन, खराब नीति, इंस्पेक्टर राज, जांच और गहन निगरानी से विकास कार्य बाधित होता है। प्रचलित श्रम कानून, जटिल कर संरचना और नौकरशाही के झंझट केवल प्रतिस्पर्धा में बाधक बनते हैं। वित्तमंत्री को चाहिए कि वे युवाओं को आशा दें। इकोसिस्टम को उद्यमियों के अनुकूल बनाएं। किसानों को सहायता दें और गरीबों का जीवन स्तर सुधारें।

विकास से आएगा रोजगार

रोजगार सृजन की सरकार की क्षमता सीमित है। बड़े उद्योग भी देश की बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर सके हैं। करोड़ों का निवेश करने वाली कंपनियां भी दस से अधिक नौकरियां नहीं दे सकीं। एमएसएमई सेक्टर की संख्या इसमें 250 है। एमएसएमई सेक्टर के लिए टॉनिक दिए जाने की दरकार है। बढ़ती बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता ही नौकरी और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। उद्यमशीलता को सींचने और उसे बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता कोष और संस्थागत नीतियां वित्तमंत्री बना सकती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था बने मजबूत

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान, उन्हें प्रोत्साहित और पोषित करने के साथ एक न्यूनतम लेकिन गारंटीयुक्त आय जरूरी है। निर्माण, आधारभूत संरचना, चमड़ा और हस्तकरघा जैसे सहायक उद्योग रोजगार का सृजन कर सकते हैं। किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। एक ऐसे सक्षम पारिस्थितिक तंत्र की जरूरत है जो उपभोग, आमदनी और समान विकास को सही गति दे। ग्रामीण विकास गरीबी को तीन गुना अधिक गति से कम करता है। वित्त मंत्री को चाहिए कि समग्र, सुधारवादी और किसान केंद्रित नीतियों के निर्माण को बढ़ावा दें। बजट में किसान धन का प्रावधान करें।

वंचित निकलें गरीबी से बाहर

असमानता और गरीबी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। नकद वितरण योजनाओं ने कई मायने में गरीबी घटाई है। यदि सरकार लक्ष्यहीन और बेतरतीबी से लागू सामाजिक व्यय योजनाओं को विघटित कर दे और प्रतिकर योग्य छूट व कॉरपोरेट करों, पूंजीगत लाभ व कर क्रेडिट जैसी रियायतों को छोड़ दे तो यह जीडीपी को छह प्रतिशत मुक्त करेगा।

जनसांख्यिकी की लाभांश

आर्थिक-सामाजिक रूप से अविकसित भौगोलिक स्थिति और अशांति राष्ट्र और समाज विरोधी ताकतों के लिए चारे का काम करती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकार उद्योग जगत की साझेदार होती है। ऐसे में रोजगार और मौकों का सृजन करने पर दोनों ही क्षेत्रों को ध्यान देने की जरूरत है।

वित्तमंत्री से लगी हैं उम्मीदें बेशुमार

वित्तमंत्री को इससे आगे बढ़ना होगा। उन्हें ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जिससे पाई-पाई की निगरानी और उनका हिसाब हो सके। साथ ही एक मजबूत ढांचा जिससे आवंटित पैसे का प्रभाव पड़े। आवंटन और प्रभाव का अंतर स्पष्ट है। कुछ बजट भाषणों पर सरसरी निगाह डालें तो कई गलतियां नजर आती हैं। अधिकांश बजट बड़ी सरकार के पास जाती हैं। परिव्यय से परिणाम तक और निवेश से भुगतान तक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मध्यम वर्ग के वोट के साथ उनकी जेब का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार की निष्क्रियता बेरोजगारी, सामाजिक अशांति बढ़ाएगी।

बेचैन किसान को बजट से मिले चैन

अनिल सिंह
संपादक, अर्थकाम.कॉम

देश में 86.2 फीसद लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। दिक्कत यह है कि सरकार तक बाकी 13.8 प्रतिशत अपेक्षाकृत बड़े किसानों की ही बात पहुंचती है। लघु और सीमांत किसानों की बुनियादी दिक्कतों को दूर करना बजट में प्राथमिकता पर लेना होगा।

किसान बेचैन है। वह बदल रहा है। हाथ-पैर मार रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में उसकी नई पीढ़ी को पता है कि सरकारें मनचाहे वक्त पर, मनचाहे इलाके में बारिश भी ला सकती हैं तो खेती के लिए वह भगवान के भरोसे नहीं रहा। अब उसे सरकार का ही भरोसा है। वही उसकी माई-बाप है। उसे पता है कि सरकार अगर चाह ले तो उसका मुकद्दर चमक सकता है।

हालांकि यह मानने के बावजूद वह नया कुछ जानने-सीखने और कोशिश करने में कोई कोताही नहीं बरतता। पहले देश के अधिकांश किसान निजी खपत के लिए खेती करते थे। बाजार से उनका वास्ता अनाज के बदले हल्दी, नमक व किराने का सामान खरीदने तक सीमित था। बाकी खर्चे घर के नौकरी करनेवाले सदस्य पूरे करते थे। लेकिन इधर बाहर नौकरी मिलने की गुंजाइश कम होती गई तो हर किसान कुछ न कुछ ऐसा पैदा करता है जिससे उसे बाजार से लगे-हाथ कैश मिल सके।

हम बड़े किसानों की नहीं, बल्कि उन लघु व सीमांत किसानों की बात कर रहे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है और जो देश के कुल किसानों का 86.2 प्रतिशत बनाते है। हालांकि इन किसानों के पास देश की 47.3 प्रतिशत ही फसली जमीन है। दिक्कत यह है कि सरकार तक बाकी 13.8 प्रतिशत अपेक्षाकृत बड़े किसानों की ही बात पहुंचती है।

ये भी नोट करने की बात है कि देश में लघु व सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। दसवीं कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 से 2015-16 के बीच इनकी संख्या तकरीबन 90 लाख बढ़ गई, जबकि कुल किसानों में इनका हिस्सा 84.9 प्रतिशत से बढ़कर 86.2 प्रतिशत हो गया। जानकारों का मानना है कि अगले दो दशकों तक भारत को इन किसानों से मुक्ति नहीं मिलेगी। सरकार को इनकी समस्या सुलझानी है तो इन्हें सबसे अच्छी तकनीक व बाजार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए वह चीन के सफल अनुभव से काफी कुछ सीख सकती है। चीन हर साल भारत से करीब छह गुना ज्यादा रकम कृषि शोध व अनुसंधान पर खर्च करता है।

देश के बड़े व समृद्ध किसानों की बात सरकार तक पहुंचती रहती है। करीब दस दिन पहले ही 17 दिसंबर को कृषि व कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि आगामी बजट में अपनी मांगें शामिल करवाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं। इनमें उद्योग संगठन सीआइआइ, राष्ट्रीय सहकारी संघ, ग्राहक पंचायत, गन्ना किसान संघ, खाद कंपनी इफ्को, मसाला निर्यातक फोरम व कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के प्रतिनिधियों के साथ ही बड़े किसानों के नुमाइंदे और तमाम कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। इन्होंने एग्रो मेडिसिनल फॉरेस्ट्री विकसित करने, विदेश में भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांड बनाने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने जैसे अनेक सुझाव दिए। लेकिन देश के 86.2 प्रतिशत आम किसानों का भला कैसे होगा, इसका कोई ठोस सुझाव सामने नहीं आया।

आपको याद होगा कि जुलाई में पेश किए अपने पहले बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने दावा किया था कि बजट समेत उनकी सारी नीतियों के केंद्र में 'गांव, गरीब और किसान' है। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने, ग्रामीण इलाकों के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की स्फूर्ति योजना, अगले पांच सालों में 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर संगठन (एफपीओ) बनाने और जीरो बजट फार्मिंग जैसी अच्छी बातें कही थीं। उम्मीद है कि फरवरी 2020 में पेश होनेवाले नए बजट में वे इन घोषणाओं पर अमल की प्रगति का विवरण जरूर देंगी।

लेकिन कम से कम एक मसला है जिस पर छह सालों से बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। सीतारमण ही नही, उनके पहले भी मोदी सरकार के हर वित्त मंत्री कृषि मंडियों से संबंधित एपीएमसी एक्ट को बदलने की बात करते रहे हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। वैसे, इस एक्ट में संशोधन का काम राज्य सरकारों को करना है। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा व उसके सहयोगी दलों की सरकारें रही हैं, वहां भी यह काम अभी तक नहीं किया गया है। आखिर, जटिल से जटिल मसलों पर संशोधन कानून पास करवाने में कामयाब भाजपा के पास किसानों के मामले में इच्छाशक्ति क्यों कमजोर पड़ गई है?

सरकार को समझना होगा कि गांवों और किसानों का मसला सड़क व घर बनवा देने और दान-दक्षिणा या सब्सिडी लुटाने तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान यूनीलीवर और डाबर जैसी कंपनियों की सेहत गांवों में मांग घटने से गड़बड़ाने लगती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों का ही नहीं, सारी अर्थव्यवस्था का ठहराव दूर होता है। यकीन है कि इस व्यापक सोच के साथ वित्त मंत्री सीतारमण आगामी बजट में 'गांव, गरीब और किसान' के लिए जरूर कोई न कोई सार्थक व सकारात्मक पहल करेंगी।

जनमत

क्या अर्थव्यवस्था की सुस्ती में जान फूंकने के लिए आम बजट-2020 में सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए?

हां 90%
नहीं 10%

क्या चहुंतरफा चुनौतियों के बीच पेश किया जाने वाला आम बजट-2020 सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा?

हां 95%
नहीं 05%

आपकी आवाज

उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है कि 2020 में मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला आम बजट देश की आर्थिक व्यवस्था के अच्छे दिन लाने वाला और आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने वाला होगा। सरकार को देश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कड़वे और कठोर फैसले तो जरूर लेने चाहिए, लेकिन कोई भी फैसला नोटबंदी जैसा न हो, बल्कि फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ उद्योग-धंधों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े और न ही देश में बेरोजगारी बढ़ाने वाला कोई फैसला हो, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले फैसले हों।

राजेश कुमार चौहान

बजट हर सरकार के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा होता है। जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों को साधना होता है। निश्चित ही इस बार जनोन्मुख बजट आना राजनीतिक आवश्यकता है।

अमन कुमार

ऑनलाइन कंपनियों को बंद किया जाए। इससे रोजगार बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।

संतोष

सबसे बड़ा रुपैया..

हफ्ते, महीने और साल भर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग भी सीमित आय का बजट बनाते हैं। विशाल देश का बजट तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा और मशक्कत की जरूरत होती है। जो इस समय वित्तमंत्री के नेतृत्व में जारी है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के जाम हुए चक्के को गति देने की है। खपत बढ़ाने के लिए लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास रहने देने का भी विचार किया जा रहा है। बिना छूट के सपाट आयकर दरें, अत्यधिक कमाई वालों के लिए नई टैक्स दरें और कारपोरेट टैक्स की तरह निजी आयकर में कटौती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

आय अपेक्षित नहीं

आर्थिक सुस्ती के हालात में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह उम्मीद से कम रहा है। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में यह संग्रह 4.5 फीसद के साथ साढ़े छह साल के सबसे निचले स्तर पर रहा है। जीएसटी के तहत भी धन संग्रह कम हो रहा है। विनिवेश भी लक्ष्य से बहुत पीछे रहा है। 1.05 लाख करोड़ के लक्ष्य में से अभी तक सिर्फ 17,354 करोड़ सरकार की झोली में आ सके हैं।

लागत है बड़ी

सरकार अगर नई टैक्स दरें लागू करती है तो उसके खजाने को 1.3 लाख करोड़ की चपत लग सकती है। हालांकि इससे 2.9 करोड़ ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनकी कर योग्य आय पांच लाख से अधिक है। कारपोरेट टैक्स कटौती के माध्यम से सरकार पहले ही 1.45 लाख करोड़ रुपये की जेब ढीली कर चुकी है, जिसका की सुस्ती पर कोई खास असर नहीं दिखा है।

नतीजा कितना प्रभावी: कम कमाई के बावजूद आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ज्यादा खर्च करने का मन बना रही है। इसके चलते जीडीपी के 3.3 फीसद वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पाना सरकार के लिए नामुमकिन हो सकता है। दूसरा विकल्प सरकार के सामने ये है कि वह कुछ हद तक अपने खर्च कम करे।

दैनिक जागरण

जीवन की दशा बदलनी है तो पहले कर्म की दिशा बदलिए

आरोप-प्रत्यारोप का खेल

राहुल गांधी नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार के साथ-साथ संघ और भाजपा पर जिस तरह निशाना साधने में लगे हुए है उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। उनके आरोपों से आक्रोशित भाजपा उन्हें केवल झूठा ही नहीं करार दे रही है, बल्कि झूठों के सरदार और वर्ष के सबसे बड़े झूठे की संज्ञा भी दे रही है। लगता नहीं कि भाजपा के जवाबी हमलों का उन पर कोई असर पड़ रहा है। वह मोदी सरकार पर नित-नया आरोप उछालकर आगे बढ़ते और भाजपा तथ्यों का हवाला देकर उनका पीछा करती ही दिख रही है। पता नहीं यह सिलसिला कब तक कायम रहेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि उनके आरोप तथ्यों से मेल खा रहे हैं या नहीं? ऐसा इसीलिए है, क्योंकि अपने देश में विपक्षी नेता आम तौर पर आरोपों के सहारे ही राजनीति करते हैं। वे प्रायः जानबूझकर मनगढ़ंत आरोपों का सहारा लेते हैं। सत्तापक्ष के पास यह सुविधा नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी बात साबित भी करनी पड़ती है। राहुल गांधी इसी का जमकर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने पहले राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर मनचाहे आरोप लगाए और अब यही काम नागरिकता कानून, नागरिकता रजिस्टर और जनसंख्या रजिस्टर को लेकर करने में लगे हुए हैं। यह तब है जब राफेल मामले में उनके आरोप न केवल आधारहीन साबित हुए, बल्कि उन्हें अपनी गलतबयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि राहुल और उनके सहयोगी यह समझ बैठे हैं कि वे मनमाने आरोपों के सहारे ही सरकार के खिलाफ एक विमर्श तैयार करने और माहौल खड़ा करने में सक्षम हैं। सत्तापक्ष उनकी ओर से बनाए जा रहे माहौल की काट तभी कर सकेगा जब अपने विमर्श को आगे बढ़ाने के साथ ही यह संदेश देने में सक्षम होगा कि सरकार उन सब मसलों पर सही दिशा में बढ़ रही है जिन्हें लेकर विपक्ष उस पर तरह-तरह के आरोप मढ़ रहा है। राजनीति में धारणा का महत्व अधिक होता है। धारणा के इस खेल में कई बार मिथ्या आरोप भारी पड़ते हैं और तथ्य एवं तर्क कमजोर। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि जनता तक उसकी बातें न केवल सही तरीके से पहुंचें, बल्कि वह उन पर यकीन भी करे। उसे इसका भी आकलन करना होगा कि किन कारणों से नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस उसके खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी है और वह भी तब जब संसद के दोनों सदन उस पर मुहर लगा चुके हैं?

सोच पर सवाल

जहां कन्या को देवी रूप में पूजा जाता हो...नवरात्र पर घर-घर में कन्या का पूजन हो...वहां पर भी अगर बेटियों का उत्पीड़न हो, यह गंभीर चिंतन का विषय है। यह सभ्य समाज के लिए शर्मनाक दाग भी है, जिसे मिटाना सबकी प्राथमिकता में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बेटियां न घर में सुरक्षित हैं और न ही बाहर। समाज में न जाने किस तरह की सोच पनप रही है कि यहां पर रिश्तों की भी अहमियत नहीं समझी जा रही है। देश भर में दुष्कर्मियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने के बावजूद ऐसे तत्वों में जरा भी डर नहीं है। चंबा जिला के सलूणी क्षेत्र में घर पर बेटी को अकेले पाकर बाप ने दुराचार किया। इसके बाद बेटी ने भागकर चंबा पहुंचकर पुलिस को आपबीती बताई। कांगड़ा जिला में एक तांत्रिक ने झाड़-फूंक कर नाबालिग से जबकि अन्य मामले में एक व्यक्ति ने रिश्ते में भाभी से दुष्कर्म कर दिया। सभी मामले पुलिस के पास पहुंचे हैं, लेकिन समाज के लिए यह गंभीर चिंतन का विषय है कि इस तरह की सोच पर कैसे लगाम लगाई जा सके? अभिभावकों में तो दहशत है ही वहीं महिलाओं में डर है कि वे किस पर विश्वास करें। जब वे घर पर ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे जा पाएंगी? सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए गुड़िया एप व शक्ति हेल्पलाइन भी जारी की है, लेकिन ऐसे मामलों में वे भी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में समाज को अधिक सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बाहर से नहीं आते, बल्कि बीच के ही लोग होते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की पहचान करनी होगी व उन पर हमेशा नजर रखी जानी चाहिए। अभिभावकों के साथ बेटियों को भी अधिक सतर्क होना होगा। बेटियों को आत्मरक्षा के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें इसके लिए भी प्रेरित किया जाए कि हमेशा अपने पास बचाव के लिए ऐसी चीजें अवश्य रखें जिनकी सहायता से आपात स्थितियों में प्रयोग कर बचा जा सके। बेटियों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का तो पता होना ही चाहिए, यह भी ज्ञान हो कि किस व्यक्ति की नजरें कैसी हैं। समय पर कदम उठाने से बड़ी घटना से बचा जा सकता है। इसलिए सबको सजग होना होगा। इसमें सरकार के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर भी समुचित कदम उठाने होंगे ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

हिमाचल प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं झकझोरने वाली हैं। इससे एक वर्ग की घटिया सोच भी उजागर होती है। साथ ही इससे महिलाओं में असुरक्षा और गहराती है कि वे किस पर भरोसा करें

भाजपा के सबक सीखने का समय

संजय गुप्त

शायद भाजपा में भितरघात की नींव उसी समय पड़ गई थी जब यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व गैर आदिवासी नेता को आगे करके ही चुनाव मैदान में उतरेगा

झारखंड में भाजपा की पराजय से यही सामने आया कि केंद्रीय सत्ता में रहते हुए कोई दल चाहे जितने बेहतर काम कर ले, वह राज्य सरकार से आम जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। राज्य सरकार से जनता की अपेक्षाएं अलग होती हैं और केंद्र सरकार से अलग। बहुत समय नहीं हुआ जब भाजपा का डंका बज रहा था और वह एक के बाद एक राज्यों में जीत हासिल कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वह एक के बाद एक राज्य गंवा रही है। पहले उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवाए, फिर महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र का मामला थोड़ा अलग है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसने हरियाणा किसी तरह बचा लिया, लेकिन झारखंड में वह अपनी हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ सकती। रघुवर सरकार सुशासन के मोर्चे पर तो कमजोर साबित हुई ही, भाजपा झारखंड में अपना गठबंधन भी सही तरीके से नहीं बना सकी और यह तो साफ ही है कि केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे ही राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते।

आज का मतदाता यह बखूबी समझता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसे किन मुद्दों के आधार पर वोट डालना है? करीब सात महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की थी तो राष्ट्रीय मुद्दों और साथ ही अपनी जनकल्याणकारी नीतियों के कारण। इसके बाद हरियाणा में उसने कमजोर प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र शिवसेना की दगाबाजी से खोया। झारखंड की हार का अवलोकन करते समय भाजपा को इस पर विचार करना होगा कि भितरघात, गुटबाजी और नेताओं की महत्वाकांक्षा कितनी घातक साबित होती है? मुख्यमंत्री रघुवर दास को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हराने वाले सरयू राय की छवि एक ईमानदार नेता की रही है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ने को इसलिए विवश हुए, क्योंकि भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाने से इन्कार कर दिया। वह जमशेदपुर पश्चिम सीट से अपना टिकट तय मानकर चल रहे थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उन्हें चुनावी मैदान में न उतारने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास के खिलाफ ताल ठोंक दी और उन्हें मात भी दे दी। उन्हें रघुवर दास विरोधियों का भी भरपूर साथ मिला। पशुपालन घोटाले से लेकर मधु कोड़ा के कारनामे उजागर करने वाले सरयू राय का टिकट कटने से आम भाजपा कार्यकर्ता भी निराश हुए। यह निराशा अन्य अनेक स्थानों पर भी नजर आई, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह देखा कि किस तरह दूसरे दलों से आए दागदार छवि वाले नेताओं को आनन-फानन भाजपा में शामिल कर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने रघुवर दास की लोकप्रियता का आकलन किए बिना ही घर-घर रघुवर नारे को मंजूरी दे दी। लगता है कि इस नारे ने भितरघात को और तेज किया। समझना कठिन है कि रघुवर विरोधियों की सक्रियता के बावजूद संगठन बेपरवाह क्यों बना रहा? राजनीति में सक्रिय लोगों की महत्वाकांक्षा को साधना आसान काम नहीं होता। अगर सरयू राय फिर से सत्ता हासिल करने में सहायक थे तो फिर यह नहीं देखा जाना चाहिए था कि उनके मुख्यमंत्री रघुवर दास से रिश्ते कैसे हैं? कायदे से उन्हें साधने की जिम्मेदारी तो खुद रघुवर दास को उठानी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया गया और नतीजा सामने है। निःसंदेह सामने यह भी है कि खुद सरयू राय भी सत्ता से बाहर हो गए।

अवधेश राजपूत

झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। पांच साल पहले भाजपा की जीत में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भी हाथ था। वह चुनाव एक तरह से अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन चुनाव हार जाने से वह मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पांच साल सरकार अवश्य चलाई, लेकिन शायद भाजपा में भितरघात की नींव उसी समय पड़ गई थी जब यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व गैर आदिवासी नेता को आगे करके ही चुनाव मैदान में उतरेगा। यह अपने आप में चुनौती थी। एक तो गैर आदिवासी नेता को आगे किया गया और दूसरे यह नहीं देखा गया कि पार्टी के आदिवासी नेता इस पर क्या सोच रहे हैं और वे रघुवर के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं या नहीं? ऐसा तब हुआ जब बाबूलाल मरांडी बहुत पहले ही भाजपा से अलग हो चुके थे। जाहिर है कि विरोधी दलों ने इस बात को उछाला कि भाजपा आदिवासियों की परवाह नहीं कर रही है। आखिर कोई भी दल आदिवासी बहुल राज्य में इस समुदाय के नेताओं के बगैर आगे कैसे बढ़ सकता है? ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास आदिवासी नेता नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें हाशिये पर रखना सही समझा गया? चूंकि ऐसा ही किया गया इसलिए हैरानी नहीं कि आदिवासियों के बीच गलत संदेश गया हो और भितरघात भी तेज हुई हो। यह भी ध्यान रहे कि चुनाव के पहले रघुवर सरकार में शामिल रही आजसू भी भाजपा गठबंधन से अलग हो गई थी। अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो सत्ता के करीब पहुंच जाते।

नए साल में दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। पांच साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। उसने ऐसे समय जोरदार जीत हासिल की थी जब नरेंद्र मोदी को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। पिछले कुछ समय से केजरीवाल सरकार ने जिस तरह अपनी छवि को सुधारने पर जोर दिया है उससे स्पष्ट है कि इस बार भी तगड़ा मुकाबला होगा। आम तौर पर किसी भी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल पार्टी की जीत-हार के सिलसिले से ही बनता है। झारखंड की हार दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली नहीं कही जा सकती।

दिल्ली में कांग्रेस भी कमर कस रही है। इधर कांग्रेस ने जिस तरह क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बनाकर अपनी स्थिति सुधारी है वह किसी से छिपी नहीं, लेकिन उसके लिए दिल्ली में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वह नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता रजिस्टर और जनसंख्या रजिस्टर यानी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के सहारे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश अवश्य करेगी। यह समय बताएगा कि इसका उसे लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन इस समय जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं उनसे भाजपा को चिंतित होना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि विरोधी राजनीतिक दल यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि झारखंड में उसकी हार नागरिकता संशोधन कानून के कारण हुई। निःसंदेह यह तथ्यों से परे एक तरह का नकारात्मक प्रचार है, लेकिन यह भी सही है कि इसका सफलतापूर्वक सामना करके ही भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में समर्थ हो पाएगी। उसे इन पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा।

response@jagran.com

सर्दी की सिहरन में भाव खाती धूप

हास्य-व्यंग्य

ज्ञान चतुर्वेदी

धूप का रुख किसी सरकारी दफ्तर की तरह है जो खुल तो गया हो, लेकिन वहां अभी काम शुरू न हो पाया हो

बड़ी तेज सर्दी पड़ रही है भाई साहब। चिल्ला जाड़े कहते थे इसे हमारे दादाजी। कहते थे कि इस बार के चिल्ला जाड़े निकलते नहीं दिखते हमें। वह हर ऐसी सर्दी में अपने मरने की भविष्यवाणी करते थे और ठाठ से अगले पच्चीस साल और जिए। वह मानते थे कि सर्दी का इंतजाम ही ईश्वर ने बूढ़ों की मुक्ति के लिए किया है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, पर दादाजी से अलग सोचता हूं। मेरा मानना है कि मरने के लिए हर मौसम मुफीद है। बहरहाल। ठंड बेहद ज्यादा है। गर्म कपड़ों में कहीं गुम हूं मैं, पर मन धूप में बैठने को कर रहा है। लॉन के एक छोटे से कोने में धूप आ भी गई अभी। वहीं पर कुर्सी डालकर धूप सेंकने बैठ गया मैं, पर यह कैसी धूप है कि इसमें कोई आंच ही नहीं। क्या धूप भी नकली आने लगी आजकल? अभी तो धूप स्वयं ही ठिठुरती सी लग रही है।

'यार, थोड़ी सी गर्मी तो दे?' मैंने धूप से उसकी कमजोर सर्विसेज की शिकायत की। धूप का रुख किसी सरकारी दफ्तर की तरह है जो खुल तो गया हो, लेकिन वहां अभी काम बाकायदा शुरू न हो पाया हो। बाबू लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। धूप की टेबल पर गर्मी की फाइल अधखुली पड़ी है। सर्दी के दिन हैं साहब। कर्मचारियों को आते-आते टेम लग जाता है। आने दें। देख रहे हैं न-फाइल सामने पड़ी है। आने दें। गर्मी अलॉट करने वाले बाबू आएं कि धूप गर्म भी होगी।

'थोड़ी देर बैठिये तो श्रीमान। गर्मी भी मिलेगी और धूप पर ही निर्भर न रहें। सरकार क्या-क्या करेगी? खुद भी इंतजाम करके रखें। प्योर वूल का स्वेटर क्यों नहीं डालते? सस्ता स्वेटर डालकर धूप के भरोसे बैठ गए हो।' धूप उस प्यून की तरह बड़बड़ाने लगी जिसे दफ्तर टाइम पर खोलना पड़ता हो।

'बैठे ही हैं यार, पर धूप में बैठने का कुछ तो मतलब निकले।' मैंने टोपा खिसकाते हुए कहा। धूप कुछ नहीं बोली। घास पर अलसाई बैठी रही। धुआं सा है या शायद कोहरा हो। तभी पड़ोस के दो पिल्ले खेलते-खेलते इसी तरफ निकल आए हैं। धूप के बचे हुए टुकड़े पर वे खूब खिलंदड़ी करने लगे। एक ने खेल-खेल में दूसरे की टांग में काट लिया है तो वह दांत दिखाता हुआ गुर्रा रहा है।

'क्यों बे? क्यों काटा रे उसे?' मेरे भीतर बैठे सजग नागरिक और मजलूमों के हक के लिए हरदम जागृत होने का भ्रम पाले लेखक ने दूसरे पिल्ले को फटकारा। 'क्यों? क्यों न काटें? 'यह पिल्ला शक्ल से ही बड़ा ढीठ टाइप का है। क्या इससे भिड़ना शास्त्रोचित कहा जाएगा? लेखक होने के कारण बचकर लिखने की लंबी आदत है मुझे। समझदार व्यंग्यकार जानता है कि उसे कहां चुप रह जाना चाहिए। मैं उसे घूरकर चुप रह गया। मन को समझाया कि यदि ऐसी ठंड न होती और अपनी शॉल को मैं हटा पाता तो देता एक लात उसे। पहले मारी भी है। आपको पता ही है, पर अभी यह ठीक न होगा। इसी बीच पिल्ले एक दूसरे का पीछा करते हुए दूर भाग गए।

'और चौबेजी?' तभी मोहल्ले के अरोरा साहब मफलर लपेटे, दूध की थैलियों का झोला टांगे हुए घर के सामने से निकले और मुझे बाहर बैठा पाकर रुक गए।

'बस, ठीक है सब।' मैंने कहा।

'धूप सेंकी जा रही है? क्यों? 'अरोरा साहब बोले।

धूप मुस्कुरा दी। मानो मेरी चोरी पकड़ी गई हो, ऐसे। शिकायत करता है कि गर्मी नहीं है, पर धूप ले भी रहा है पट्ठा। जिनके खिलाफ लिखता है उनसे ही लाभ भी लेता रहता है गो कि मानेगा कभी नहीं।

'काहे की सेंक अरोरा जी। धूप भी धूप जैसी कहां बची है आजकल।' मैंने कहा। धूप रूठ गई। नाशुक्रा लेखक। हमीं से धूप लेना और हमारे ही खिलाफ बातें। हमीं से पुरस्कार और हमारे ही खिलाफ बयानबाजी। धूप मुंह फुलाकर दूर निकल गई। सर्दी में धूप भी नकचढ़ी हो गई है। नखरे तो देखो इसके। सही बात कह दी तो असहिष्णुता पर उतर आई है। अपने होने का रूआब दिखा रही है मुझे। 'टोपे से काम न होगा चौबे जी। मौसम खिलाफ है। ऐसे खुलेआम बाहर बैठकर सर्दी को चुनौती मत दीजिए। उमर हो गई है हम लोगों की।' अरोरा जी मुझे समझाने लगे। आजकल लोग समझाते ही हैं कि कलम पर इतना भरोसा ठीक नहीं भाई साहब। मौसम देखकर लिखा करिए। अपनी अभिव्यक्ति पर कुछ ओढ़कर, ढंक कर रहा करिए।

response@jagran.com

ऊर्जा

रिश्तों में जीवन

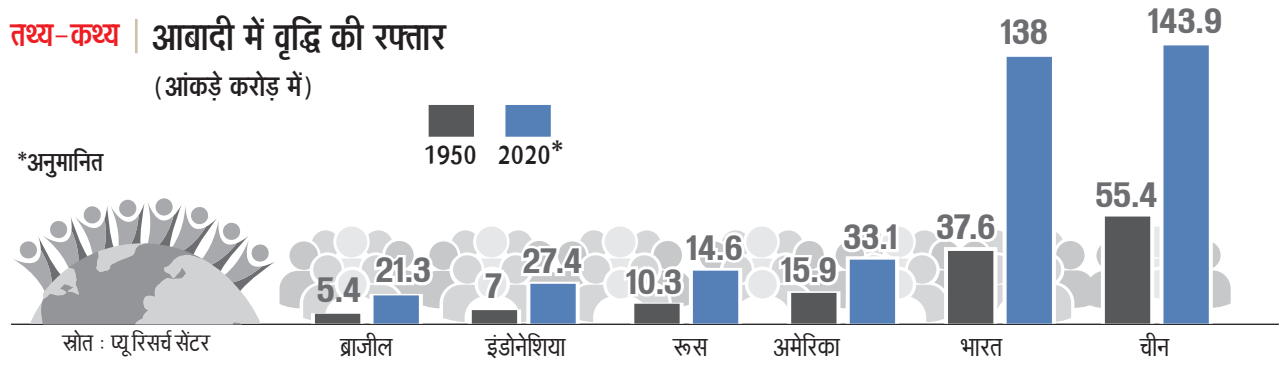

यह दौर परिवारों में तेजी से हो रहे विघटन का साक्षी बना हुआ है। एकल परिवार की अवधारणा में विश्वास के चलते संयुक्त परिवारों की व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। एकल परिवार के इस विचार ने मनुष्य को इतना एकाकी बना दिया है कि वह अपने जीवन में सीमित होकर रह गया है। अपनी सुविधाओं से किसी किस्म का समझौता न करने के कारण भारतीय परिवारों में निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक दौर था जब परिवार के दुख के लिए अपने सुख से समझौता कर लिया जाता था और एक यह दौर है जिसमें परिवार में दुख आए तो सदस्य अपने सुख की तलाश में अलग रहने लगते हैं।

जीवन में रिश्ते हों उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन रिश्तों में जीवन हो। रिश्तों में यदि जीवन नहीं है तब फिर जीवन में रिश्ते होने का कोई औचित्य शेष नहीं रहता। इस दौर में हम रिश्तों में जीवन को समाप्त करने पर तुले हुए है। पहले तो जीवन के वास्तविक रिश्तों से दूर होकर एकाकी होने के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं और फिर जब रिश्तों की आवश्यकता महसूस होती है तब इस जरूरत को पूरा करने के लिए आभासी मंचों का आश्रय लेते हैं। आभासी दुनिया कभी वास्तविकता की पूर्ति कर ही नहीं सकती, जीवन में इंसान की पूर्ति पैसा नहीं कर सकता। रिश्ते, रिश्ते होते है और भौतिकता सिर्फ भौतिकता, किंतु जीवन को सुखी, संपन्न और एकाकी बनाने की लालसा धन, वैभव, यश, कीर्ति इत्यादि अर्जित कर लेने के पश्चात भी संयुक्त परिवार के आनंद और सुख से वंचित कर देती है। इसका असर मानसिक जीवन पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं बच्चों की परवरिश भी प्रभावित होती है।

जीवन में भावनाओं की पूर्ति वास्तविक रूप में न हो तो इंसान आभासी दुनिया का राहगीर बन जाता है। यह दुनिया उसे भ्रम में बांध देती है कि वह सबका है और सब उसके, किंतु जरूरत के समय वास्तविकता का बोध हो जाता है जब वह स्वयं को अकेला पाता है। इसीलिए रिश्तों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि आभासी दुनिया का आसरा लेने की नौबत न आए।

सौरभ जैन

तथ्य-कथ्य | आबादी में वृद्धि की रफ्तार

(आंकड़े करोड़ में)

स्रोत : प्यू रिसर्च सेंटर

मिल गया लंबी उम्र का मंत्र

मुकुल व्यास

इस नई खोज से ऐसी उपचार विधियां विकसित की जा सकती हैं जो लंबी उम्र में बाधा बनने वाले प्रोटीनों को हटा देंगी

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दीर्घ जीवन के लिए एक खास प्रोटीन की भूमिका का पता लगाया है। एक अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ कीड़े यदि पी62 नामक प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं तो वे अधिक समय तक जीते हैं। यह प्रोटीन दरअसल कोशिका के विषाक्त प्रोटीनों को पहचान लेता है। सेनफोर्ड बर्नहम प्रीबिस मेडिकल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज का पूरा विवरण 'नेचर ' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस खोज से अल्जाइमर जैसे आयु संबंधित विकारों का बेहतर इलाज खोजने में मदद मिल सकती है जो विकृत प्रोटीनों के जमा होने से उत्पन्न होते हैं। इससे पता चलता है कि 'ऑटोफेगी' प्रक्रिया को बढ़ावा देकर जीवनकाल में वृद्धि की जा सकती है। कोशिकाएं इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को रिसाइकल करने के लिए करती हैं।

उन्होंने कहा कि इस शोध से पहले हमें यह तो पता था कि ऑटोफेगी प्रक्रिया का संबंध आयु-वृद्धि से है, लेकिन दीर्घ जीवन पर पी62 प्रोटीन के प्रभाव को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिक पहले यह सोचते थे कि कोशिका के स्तर पर रिसाइक्लिंग सभी अपशिष्ट उत्पादों पर लागू होती है। ऑटोफेगी बहुत चुनिंदा तरीके से काम करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोशिका विभिन्न किस्म के कचरों को कोशिका के रिसाइक्लिंग केंद्रों में पहुंचाने के लिए पी62 प्रोटीन जैसे अलग-अलग 'रिसाइक्लिंग माध्यमों' का इस्तेमाल करती है। पी62 प्रोटीन कोशिका के क्षतिग्रस्त प्रोटीनों और जीर्ण-शीर्ण माइटोकोंड्रिया को रिसाइक्लिंग केंद्रों में पहुंचाने का काम करता है। रिसाइक्लिंग और दीर्घ जीवन में पी62 की भूमिका को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सी एलिगंस नामक अल्पजीवी, पारदर्शी गोलकृमि का प्रयोग किया। इससे पहले हेनसेन की टीम ने पता लगाया था कि कीड़ों को कम अवधि का हीट शॉक देने पर पी62 के स्तर में वृद्धि हो जाती है।

इस खोज से उत्साहित होकर वैज्ञानिकों ने पी62 प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न करने के लिए सी एलिगंस में आनुवंशिक फेरबदल किया। इन कीड़ों का सामान्य जीवनकाल तीन महीने होता है जो इस कवायद से प्रभावित हुआ। शोधकर्ताओं को इस बात पर हैरानी हुई कि पी62 के स्तर में वृद्धि करने पर कोशिका के रिसाइक्लिंग माध्यमों और रिसाइक्लिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो गई और वे ज्यादा कचरे की रिसाइक्लिंग करने में कामयाब रहे। इससे स्पष्ट होता है कि पी62 ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पी62 जैसे प्रोटीनों के जरिये चुनिंदा ऑटोफेगी का अध्ययन करके ऐसी उपचार-विधियां विकसित की जा सकती हैं जो लंबी उम्र में बाधक प्रोटीनों को हटा देंगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस खोज को सीधे मनुष्यों पर आजमाने में सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि मनुष्यों में पी62 के उच्च स्तर को कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया है। इस बात को ध्यान रखकर वैज्ञानिकों को चुनिंदा ऑटोफेगी में पी62 के लाभदायक कार्यों को बढ़ावा देना होगा।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

सीबीआइ में सन्नाटा

देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआइ में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीबीआइ में दर्ज होने वाले मामलों में कमी आई हो या फिर उन मामलों की जांच धीमी हुई है। सिर्फ हाईप्रोफाइल मामलों में कमी आई है। पहले सीबीआइ में किसी न किसी बड़े नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज होते रहते थे और देश की जनता उन हाईप्रोफाइल मामलों की स्थिति जानने को उत्सुक रहती थी। जाहिर है ऐसे मामलों की जांच के हर पहलू पर मीडिया की भी गहरी नजर होती थी। जनता को हाईप्रोफाइल मामलों की जांच की सही जानकारी देने के लिए सीबीआइ में भारी-भरकम मीडिया विभाग भी बन गया, लेकिन पिछले साढ़े पांच साल में मोदी सरकार के दौरान उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सामने नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि किसी में यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि सीबीआइ में क्या हो रहा है और वह कौन-कौन से मामलों की जांच कर रही है।

मंत्रिपद की आस

नेताओं की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। संसद सत्र समाप्त होते ही मंत्री बनने की लाइन में लगे भाजपा नेताओं के मन में कुलबुलाहट होने लगी है। कुछ नेताओं को लग रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ऐसे नेता अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं। मंत्री पद पाने की ख्वाहिश रखने वाले नेताओं ने मीडिया के लोगों से इस बात को लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है कि कब फेरबदल हो रहा है। ऐसे नेताओं के नजदीक रहने वाले छोटे नेताओं ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है 'भैया फलां मंत्री बन रहे हैं।' भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी तरह के फेरबदल के दूर-दूर तक कोई आसार न दिख रहे हों, लेकिन नेताओं की चाहत है कि छूटे नहीं छूटती।

राजरंग

रेलवे अफसरों की झेंप

पिछले दिनों दिल्ली में हुई रेलवे की वैगन कांफ्रेंस में रेलवे अधिकारियों को बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। सम्मेलन के दौरान रेल अधिकारियों ने अपने नए डिजाइन के वैगनों की तारीफ में खूब कशीदे काढ़े। साथ ही कहा कि वाहन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए रेलवे ने कई नए कदम उठाए हैं। साथ ही वैगन और रैक में भी सुधार किया गया है जिससे आने वाले दिनों में वाहन निर्माता सड़क के बजाय रेल को तरजीह देंगे, परंतु सम्मेलन में मौजूद एक बड़ी कार कंपनी के उच्च अधिकारी ने रेलवे अफसरों के दावों पर पानी फेर दिया। कार कंपनी के अधिकारी ने कहा कि आप रेलवे वाले बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। आपके दावों पर भरोसा करके हमारी कंपनी ने अपनी कारों के लिए आपकी रैक ले ली, लेकिन जिन वैगनों को 18-20 साल चलने का दावा किया गया था, उनकी छतों से तीन साल में ही पानी टपकने लगा। रास्ते में कारों के एक्सेसरीज निकाल लिए जाते हैं। रैक के पोर्ट तक पहुंचने में भी तीन दिन के बजाय सात-सात दिन लग जाते हैं। कार कंपनी के अधिकारी की बातें सुनकर वहां मौजूद रेलवे के आला अफसर झेंप गए और उन्होंने कार कंपनी के अधिकारी की शिकायतें दूर करने का भरोसा देकर स्थिति को संभाला।

दूसरी पारी की तैयारी

सियासी गलियारों में जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि हकीकत भी कुछ वैसी ही हो। खासतौर से मामला जब राजनीतिक दलों के नेतृत्व में स्थिति को लेकर असमंजस का हो। कांग्रेस इसका ताजा उदाहरण है जहां कहने को पार्टी का संचालन अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं, मगर पार्टी के सियासी कदमों से लेकर संगठनात्मक फैसलों पर करीब से नजर डालें तो साफ है कि चाहे निर्णय सोनिया कर रही हों, मगर इन पर छाप राहुल गांधी की है। इस लिहाज से यह कहना गैर मुनासिब नहीं कि सोनिया गांधी की सरपरस्ती में राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में अपनी दूसरी पारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ताजा मिसाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के गठन से जुड़ी है। युवा नेता पूर्व सांसद राजीव सातव को स्क्रीनिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है और राहुल से इनकी निकटता पार्टी में किसी से छिपी नहीं है। इससे पहले चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, वहां टिकट बंटवारे में भी परोक्ष रूप से राहुल की ही चली। नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस के विरोध आंदोलन में भूमिका और तस्वीरों से साफ है कि राहुल गांधी केंद्रीय भूमिका में दिखाई दें, यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि सोनिया की सदारत से राहुल गांधी द्वारा पार्टी की औपचारिक रूप से कमान संभालने का एलान बस किसी भी वक्त हो सकता है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

4,350 करोड़ रुपये से अधिक रहा है इस वर्ष फिल्मों का कारोबार, एक अनुमान के मुताबिक। पिछले वर्ष के मुकाबले यह आंकड़ा हजार करोड़ रुपये अधिक है।

अनंत विजय

आजकल

हैशटैग से प्रेरित सफल फिल्में

फिल्मों के लिहाज से वर्ष 2019 बहुत ही शानदार रहा है। हालांकि देश भर में कायम आर्थिक सुस्ती को फिल्मों से जोड़ने के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर बीते दिनों खूब विवाद हुआ, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि फिल्मों के लिहाज से यह वर्ष वाकई बहुत अच्छा रहा है। एक नया तथ्य यह भी उभरा है कि हैशटैग पर बनती फिल्मों के सफल होने की गारंटी बढ़ गई है। बीते वर्षों से हैशटैग पर फिल्म बनने की जो शुरुआत हुई है उसकी कामयाबी से यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है

फिल्म 'वॉर' और 'कबीर सिंह' का पोस्टर। प्रतीकात्मक तस्वीर

देश में आर्थिक मंदी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान का खूब मजाक बना था। रविशंकर प्रसाद ने तब कहा था कि जब एक दिन में फिल्में सौ करोड़ से अधिक कमा रही हैं तो मंदी कैसे हो सकता है। जब उनका यह बयान आया था तब उसका ना सिर्फ मजाक बना था, बल्कि विपक्ष समेत कई स्वतंत्र स्तंभकारों ने रविशंकर प्रसाद को घेरा था। टेलीविजन चैनलों पर बहस भी हुई थी। कई लोगों ने रवि बाबू के इस बयान को गंभीर मुद्दे को हल्के में लेनेवाला करार दिया था। बाद में इस मुद्दे पर सफाई आदि भी आई। लेकिन अब जो आंकड़ें आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कम से कम हिंदी फिल्म उद्योग मंदी से प्रभावित नहीं है। रविशंकर प्रसाद भले ही मजाक में कह रहे हों, लेकिन अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ 30 प्रतिशत से अधिक हो तो वहां मंदी जैसी बात तो नहीं ही कही जा सकती है। वर्ष 2019 में फिल्मों के कारोबार का आंकड़ा 4,000 करोड़ को पार कर गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष फिल्मों का कारोबार 4,350 करोड़ से ज्यादा का रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इस वर्ष एक हिंदी फिल्म 'वॉर' ने 300 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया, जबकि तीन हिंदी फिल्मों ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा और दो ने 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके अलावा तीन फिल्में ऐसी रहीं जिनका कारोबार 150 करोड़ से अधिक रहा। इस लिहाज से देखें तो 2019 फिल्मों के कारोबार के लिहाज से अब तक का सबसे अधिक मुनाफा देने वाला वर्ष बन गया।

'वॉर' के बाद 'कबीर सिंह' ने 280 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। इस फिल्म की काफी आलोचना भी हुई थी लेकिन बावजूद इसके दर्शकों ने इसको पसंद किया। 'कबीर सिंह' तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में शाहिद कपूर ने एक ऐसे शख्स की भूमिका निभाई है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सर्जन बनने के बाद भी वह शराब पीकर और ड्रग्स के डोज लेकर ऑपरेशन करता है। महिलाओं के प्रति हिंसा उसके व्यवहार उसके काम-काज के दौरान दिखता है। यह वही दौर था जब 'उरी' और 'केसरी' जैसी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही थीं तो दूसरी तरफ 'कबीर सिंह' जैसी फिल्म को भी दर्शक हाथों हाथ ले रहे थे। कबीर सिंह के अलावा 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भी ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस किया। 'हाउसफुल 4' और 'टोटल धमाल' आदि भी कमाई में अव्वल रहीं।

इस वर्ष हिंदी सिनेमा में एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए। वो है देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का जमकर कारोबार करना। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में राष्ट्रवाद को लेकर काफी बातें होने लगीं थीं। राष्ट्रवाद के पक्ष और विपक्ष में तर्क-कुतर्क भी हुए, हिंसा से लेकर आंदोलन भी हुए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद कई बार ट्रेंड भी करता रहता है। राष्ट्रवाद का ये विमर्श अब भी अलग अलग रूपों में जारी है। फिल्मकारों ने राष्ट्रवाद के इस विमर्श को अपनी फिल्मों का विषय बनाया और जमकर मुनाफा कमाया। अगर हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में बनी फिल्मों पर नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि इस दौर में तीन दर्जन से अधिक फिल्में ऐसी बनीं जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद के साथ-साथ भारत और भारतीयता को सकारात्मकता के साथ पेश करनेवाली फिल्मों ने जमकर कमाई की। 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' का उदाहरण तो सबके सामने है ही। इसके अलावा अगर हम 'नाम शबाना' और 'गाजी अटैक' जैसी फिल्मों को भी लें तो उसने अच्छा मुनाफा कमाया। पहले ज्यादातर 'लगान' जैसी फिल्में बनती थीं जिसमें अंग्रेजों से गुलामी का बदला लिया जाता था और देशप्रेम की भावना को उभार कर निर्माता निर्देशक दर्शकों को सिनेमा तक खींच कर लाते थे, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थितियां बदलने लगीं। अब तो देश के गौरव को स्थापित करनेवाली फिल्में दर्शकों को पसंद आने लगीं। दर्शकों को देश की सफलता की कहानी भी पसंद आने लगी। 'मिशन मंगल' की सफलता इसकी एक बानगी भर है। इसमें भारत की अंतरिक्ष में कामयाबी की गौरव गाथा है। राष्ट्रवाद की लहर से फिल्म उद्योग अछूता नहीं रहा।

इस तरह की फिल्मों की सफलता से हिंदी फिल्मों से खान साम्राज्य के दबदबे में कमी भी आ गई है। आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' फ्लॉप रही। शाहरुख खान की 2019 में कोई फिल्म आई नहीं। इसके पहले 'जीरो' को दर्शक नकार चुके हैं। ले देकर सलमान खान अब भी मैदान में डटे हुए हैं। इससे अलग कुछ ऐसे चेहरे हिंदी फिल्मों में स्थापित हुए जिसमें लोग अपने जैसी छवि देखते हैं। आयुष्मान खुराना से लेकर विकी कौशल जैसे अभिनेताओं ने अपनी अदाकारी से खुद को तो स्थापित किया ही, फिल्मों को भी सफल बनाया।

इन सबसे अलग हटकर एक और तथ्य है जिसकी ओर फिल्मकारों ने ध्यान दिया और वो सफल रहे। पिछले पांच वर्षों से फिल्मकारों ने खबरों पर फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं। जिस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चली और उसका हैशटैग ट्रेंड करने लगा उन खबरों पर फिल्म बनी। नोएडा में आरुषि तलवार हत्याकांड पर मेघना गुलजार ने 'तलवार' फिल्म बनाई। इसी तरह से लखनऊ में हुए एनकाउंटर और फिर परिवार का मुठभेड़ में मारे गए अपने लड़के का शव लेने से इन्कार कर देने की घटना चर्चा का विषय बनी थी। उस समय इस खबर को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखा गया था। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इस घटना को केंद्र में रखकर फिल्म 'मुल्क' का निर्माण किया। यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। अनुभव ने ही उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों की मौत और उनके शव पेड़ पर लटके मिलने की बेहद चर्चित खबर को केंद्र में रखकर 'आर्टिकल 15' बनाई। इस खबर की भी देश-विदेश में चर्चा हुई थी। सीबीआइ जांच तक हुई थी। कई दिनों तक न्यूज चैनलों पर पेड़ से लटकी दो लड़कियों की तस्वीरों पर चर्चा की गई थी। इसी तरह से अलीगढ़ के एक समलैंगिक प्रोफेसर की कहानी पर 'अलीगढ़' के नाम से फिल्म बनी। मेघना गुलजार अब 'छपाक' लेकर आ रही हैं जो एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी की कहानी है। इसमें दीपिका पादुकोण केंद्रीय भूमिका में हैं। हैशटैग पर फिल्म बनने की जो शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई थी वह 2019 में आकर और मजबूत हुई और अब इसने एक ट्रेंड का रूप ले लिया है।

कुछ फिल्मकार इसको फिल्मों में यथार्थवादी कहानियों की वापसी के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कहानियों से दर्शकों को उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जो खबरों से नहीं मिल पाता है। फिल्मों में खबरों को फिक्शनलाइज करके दिखाया जाता है जिससे उनको ये छूट रहती है कि वो अपने हिसाब से खबर को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। इस प्रवृत्ति को फिल्म 'मुल्क' से लेकर 'तलवार' तक में देखा जा सकता है। इस तरह की फिल्मों के निर्देशकों को ये छूट भी मिल जाती है कि खबर को लेकर जन भावना के साथ अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को पहुंचा दे या फिर निर्देशक अपनी विचारधारा के हिसाब से दर्शकों को ज्ञान दे। लेकिन जनभावना अगर छूटती है तो फिल्म की सफलता संदिग्ध हो जाती है जिसका उदाहरण 'अलीगढ़' फिल्म की असफलता में देखा जा सकता है। 'तलवार' में मेघना ने लगभग जन भावना के अनुरूप ही फिल्म का क्लाइमेक्स रचा।

वर्ष 2019 को हम फिल्मों के इतिहास में कारोबार के लिहाज से अब तक के सबसे सफलतम वर्ष में रख सकते हैं। इस वर्ष को फिल्मों के अधिक लोकतांत्रिक होने के वर्ष के रूप में भी याद किया जा सकता है।

फिर से

सबसे बेहतर है कुएं का जल

जल जीवन का आधार है, मगर क्या कभी आपने सोचा है, जीवन देने वाला जल अगर मृत्यु का पर्याय बन जाए तो क्या होगा? जल प्रदूषण के कारण ऐसा होना मुमकिन है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा जल से भरा है। इसमें से केवल तीन प्रतिशत जल ही मानव के पीने योग्य है। मानव इस तीन प्रतिशत जल को भी आज सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। आज हमारे जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। जल प्रदूषण दो तरह का होता है। एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण प्राकृतिक कारकों में से एक है। आर्सेनिक एक तत्व है जो पानी में मिला होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) आर्सेनिक की मात्रा जल में पीने योग्य होता है। दस पीपीबी से ज्यादा होने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। आर्सेनिक से होने वाले रोग को अर्सेनिकोसिस कहते हैं। इसका सबसे पहला संकेत है शरीर के अंगों पर धब्बे का उभरना। इसे मेलोनोसिस कहते हैं। इस अवस्था के बाद भी अगर कोई आर्सेनिक युक्त पानी का सेवन करता है तो हाथ-पैर की त्वचा कठोर हो जाएगी।

मनुष्य के शरीर में आर्सेनिक कुछ सेवन करने, सांस के जरिये तथा त्वचा के संपर्क में आने से प्रवेश करता है। त्वचा या बाल से चिपककर खून के जरिये यह शरीर में प्रवेश करता है। लंबे समय तक इसका असर शरीर पर दस-पंद्रह साल बाद दाग धब्बे के रूप में सामने आता है। बाद में यही निशान घाव व कैंसर में परिणित हो जाते हैं। इसके अलावे भी कई गंभीर रोग आर्सेनिक युक्त पानी के सेवन से होता है।

विश्व में लगभग 70 देशों के 15 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त भूजल से प्रभावित हैं। इनमें से 11 करोड़ लोग दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के दस देशों बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, लाओस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताईवान और वियतनाम में रहते हैं। इन आंकड़ों से जान सकते हैं कि इन देशों में पेयजल के मामले में कितनी समस्या होगी। इस मामले में भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। कई राज्य इसकी चपेट में है। भारत में आर्सेनिक की पहली रिपोर्ट 1983 में आई। उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और आज यह काफी विकराल रूप में हमारे सामने है।

बिहार के भोजपुर जिले के सेमरिया ओझा पट्टी गांव में 2002 में पहली बार आर्सेनिक युक्त पानी का पता चला। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2004 में पहली बार पता चला। असम के 17, बिहार के 13, छत्तीसगढ़ के दो, झारखंड के चार, कर्नाटक के दो, पंजाब के 17, उत्तर प्रदेश के 17 व पश्चिम बंगाल के नौ जिले आर्सेनिक प्रभावित हैं।

आर्सेनिक से प्रदूषित जल के खतरों

से बचने के लिए ज्यादातर लोग वर्षा जल संचयन, कुओं के जीर्णोद्धार के बजाय आर्सेनिक फिल्टर और पाइपों के जरिये की जाने वाली जलापूर्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। परंतु कई शोध हुए तो पता लगा कि कुएं का पानी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। कुएं का पानी खुला होने की वजह से धूप और हवा (ऑक्सीजन) के संपर्क में रहता है। कुएं के पानी में मौजूद आयरन (लौह तत्व) के संपर्क में आकर आर्सेनिक नीचे चला जाता है। इस वजह से कुएं के पानी में आर्सेनिक नहीं होता है। पानी के स्वच्छ स्रोतों की बात की जाए तो हमें पारंपरिक जल स्रोतों की तरफ दोबारा मुड़ना होगा। वर्षा के जल का संचय करना होगा। तालाब, बावड़ी, कुएं आदि को रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी सतही जल हमें मिल पाएंगे। साथ ही पानी की बर्बादी को रोकना होगा।

(कमल उपाध्याय की फेसबुक वॉल से संपादित अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

पुलिस बदला लेगी! चार का बदला, पूरी गली से लेगी! बदला बर्बाद करके लेगी! पुलिस काली पट्टी बांधने की सजा, जिंदगी काली करके लेगी। ऐसी बातें बोलने वाले पुलिस अधिकारी असल में पुलिस को बदनाम ही कर रहे हैं।

रोमाना इस्सार खान@romanaisarkhan

उत्तर प्रदेश के मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रहे, पुलिस को मां-बहनों की गालियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे, आगजनी कर रहे, दंगाइयों से यह कहना कि 'तुम पाकिस्तान चले जाओ', एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है।

उमा भारती@umasribharti

मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के पक्षपात किए जाने के आरोपों को पूरी तरह खारिज करता हूं। अपने समग्र क्रिकेट खेल के करियर में मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़ा। मुझे हमेशा अपने देश की टीम, प्रबंधन और प्रशंसकों का प्यार एवं सहयोग मिला। पाकिस्तान जिंदाबाद।

मोहम्मद यूसुफ@yousaf1788

अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर किस कारण आप यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गए और आपकी पत्नी को भी तानिया से फातिमा बनना पड़ा? लोग आपके इस विचार को भी जानना चाहेंगे, तो क्या उन कारणों पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे।

आभास मलदाहियार@Aabhas24

रचनाकर्म

पानी और जीवन का अंतर्संबंध

स्मिता

इस उपन्यास में लेखक ने न केवल जल संकट और उसके उपायों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है, बल्कि स्त्री सशक्तीकरण को भी रेखांकित किया है...

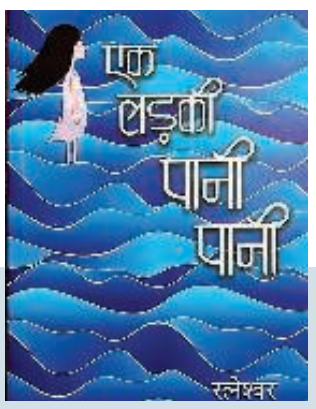

पुस्तक : एक लड़की पानी पानी
लेखक : रत्नेश्वर
प्रकाशन : राजपाल, नई दिल्ली
मूल्य : 325 रुपये

कथाकार रत्नेश्वर ने अपने नए उपन्यास 'एक लड़की पानी-पानी' में विज्ञान और अध्यात्म, दोनों का बड़ी खूबसूरती के साथ मेल किया है और जल संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी कलम चलाई है। आज जहां हिंदी का हर तीसरा लेखक प्रेम-प्यार और राजनीति के किस्से लिखने में मशगूल है, वहीं रत्नेश्वर का पर्यावरण समस्या (जल संरक्षण) पर लिखा यह दूसरा उपन्यास 'एक लड़की पानी पानी' (पहला- रेखना मेरी जान) भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाता हुआ प्रतीत होता है।

यह उपन्यास जल संकट के कारण होने वाले दुष्परिणामों की ओर संकेत करता है। मसलन, स्थिति कुछ ऐसी होगी कि पैसे की तरह पानी भी एटीएम से निश्चित मात्रा में मिला करेगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए विकसित और विकासशील देशों को अपनी सारी शक्ति झोंकनी होगी।

लेखक ने जल संरक्षण और संवर्धन जैसे बेहद जरूरी और गंभीर विषयों को उठाया है और साथ ही स्त्री सशक्तीकरण, छूआछूत, यहां तक कि विज्ञान के जटिल प्रश्नों के जवाब भारतीय दर्शन और अध्यात्म में मौजूद होने जैसे तथ्यों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ उपन्यास में बुना है।

उपन्यास की नायिका श्री कथित छोटी जाति के एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसका मन और मस्तिष्क असीम ऊर्जा से अनुप्राणित है। वह दूसरों से अलग और अद्भुत सोचती है व अपने ज्ञान-विचार से दूसरों को आकर्षित-अचंभित करती रहती है। गरीब परिवार से होने के बावजूद वह स्कॉलरशिप से मिली रकम से नागपुर के वॉटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान में पढ़ाई करती है और यहीं से जलस्रोतों पर शोध के लिए अमेरिका भी जाती है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ाने के आइडिया से वह न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेश में भी अपने दिमाग का लोहा मनवाती है। पानी के स्रोतों की खोज में वह वैदिक मंत्र, साधना और पौराणिक ग्रंथों के ज्ञान की भी मदद लेने की बात कहती है। आग में तपकर ही सोना खरा हो पाता है, नायिका श्री का आचार-व्यवहार, ज्ञान इसी ओर इंगित करता है। जिस तरह से कहानी में अत्याधुनिक कंप्यूटर, वैज्ञानिक खोजों को दर्शाया गया है, निश्चित तौर पर उसके पीछे लेखक का गहरा शोध रहा होगा। बीच-बीच में लेखक ने महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है, जैसे कि एक खास जाति के लोगों का सिर्फ जमीन देखकर जलस्रोतों का पता लगाने का अद्भुत ज्ञान आदि। कॉलेज और हॉस्टल लाइफ का भी रोचक वर्णन इसमें किया गया है। लड़के-लड़कियों की चुहलबाजी, रैगिंग के मजेदार किस्से कहानी को बोझिल होने से बचा लेते हैं। उपन्यास का एक खूबसूरत पहलू है रैगिंग के बहाने लड़कियों में आत्मविश्वास का भाव जगाना और स्त्री सशक्तीकरण का संदेश देना। न सिर्फ जलस्रोतों की खोज का कार्य एक स्त्री के हाथ में है, बल्कि प्यार व शादी के विचार भी वे सशक्त तरीके से सबके सामने रखती हैं।

लेखक उपन्यास में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने से बचते रहे हैं। ऐसे हिंदी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिनके अंग्रेजी शब्द अधिक प्रचलित हैं। उदाहरणस्वरूप 'पानी गेंद' का शब्द प्रयोग किया गया है जबकि वाटर बॉल अधिक चलन में है।

नायिका बिहार से है, इसलिए वहां के स्थानीय शब्दों, खास शहरों-गांवों का जिक्र पाठकों को अपनापन महसूस कराएगा। भारतीय दर्शन और अध्यात्म के प्रति अमेरिकी संस्थान और लोगों का सम्मान मन में भारतीय होने के गर्व का भाव पैदा करता है। 'रेखना मेरी जान' की तरह ही लेखक ने कहानी का अंत पाठकों के स्व-विचार के भरोसे छोड़ दिया है। वे चाहें, तो ऐसा सोच लें कि सृष्टि के कल्याण के लिए नायक-नायिका जल समाधि ले लेते हैं या फिर कोई उन्हें उस स्थान से हटा कर ले जाता है या फिर अथाह जल उन दोनों को सतह पर ले आता है।

सफलता की यात्रा का मंत्र

जितेंद्र कुमार

पुस्तक : रुक जाना नहीं
लेखक : निशान्त जैन
प्रकाशक : हिंद युग्म, नई दिल्ली
मूल्य : 150 रुपये

सिविल सेवा परीक्षा हमेशा ही एक बड़ी चुनौती मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चयनित हुए अभ्यर्थियों पर नजर डालें तो इसमें हिंदी माध्यम वालों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। ऐसे में इस माध्यम से परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में कई दफा निराशा का आना स्वाभाविक है। निशान्त जैन की यह किताब इसी तरह की निराशा और तनाव के समय सही राह दिखाने की एक प्रभावी कोशिश है।

इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह किताब एक गाइड की तरह है, जो न सिर्फ सही राह दिखाती है, बल्कि उससे बढ़कर दुरूह सफर में चलते रहने लायक जोश बनाए रखने की भरपूर कोशिश करती है। लेखक ने इस किताब में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं के दैनिक जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। चाहे वह स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, लाइफ स्किल हो या लेखन कला। लेखक ने लगभग हर जरूरी विषय पर अपनी कलम चलाई है। लेखन कला को निखारने के लिए प्रचलित नुस्खों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए गए हैं।

लेखक ने किताब के जरिये बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, पर आंख मूंदकर लक्ष्य की ओर चलने से बचने की सलाह भी देते हैं। एक शेर के जरिये यह बात कही गई है- 'मंजिल मिले न मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है।' निशान्त सिविल सेवा में कार्यरत हैं और वह खुद इस परीक्षा में हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं। जैन ने अपने स्कूल जीवन से लेकर आइएएस बनने तक के प्रेरणादायक सफर को पाठकों से साझा किया है। आइएएस की परीक्षा में सफल हुए 26 अन्य युवाओं की कहानियां इस किताब की जान हैं। चाहे वह 23 साल की पूजा पार्थ की कहानी हो, जो बिना कोचिंग के परीक्षा पास करने में सफल रहीं या उत्तर प्रदेश के आशीष कुमार हों, जो नौवें और अंतिम प्रयास में आखिरकार आइएएस के रूप में चयनित हुए। व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरणा लेकर लिखी गई यह किताब बाजार में उपलब्ध सेल्फ हेल्प पुस्तकों से अपेक्षाकृत बेहतर कही जा सकती है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

सेना प्रमुख का कथन 'लोगों को हिंसा के लिए भड़काने वाले नेता नहीं हैं' का विरोध उचित है?

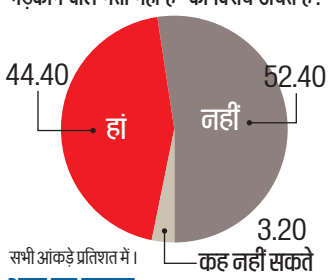

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रेलवे बोर्ड के स्वरूप में प्रस्तावित बदलाव से रेल सेवाओं में सुधार होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सोचो देता कौन है संविधान को कष्ट,
सोचो करता कौन है शांति व्यवस्था नष्ट!
शांति व्यवस्था नष्ट कौन बरसाए पत्थर,
आग लगाता कौन समर्थन उनको देकर??
स्वयं खींचकर चीर बन रहा है रक्षक जो,
क्या है उसका नाम हाथ रख दिलपर सोचो!!

- ओमप्रकाश तिवारी

मनोज झा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

किशनगंज छोड़ रांची क्यों जा रहे मांझी

किशनगंज में आज एआइएमआइएम की रैली है जहां ओवैसी के साथ जीतनराम मांझी की मौजूदगी की भी खबर थी, जिससे राज्य में दलित-मुस्लिम सियासत को एक नई दिशा मिल सकती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतनराम ने कल अचानक रांची जाने की घोषणा कर दी

सबसे पहले तो इस ताजा सूचना पर गौर करें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के मुखिया जीतनराम मांझी आज किशनगंज नहीं जाकर अचानक से रांची जा रहे हैं। किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) की रैली है, जिसके मुख्य वक्ता पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। दूसरी ओर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ओवैसी की रैली में मांझी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जबकि रांची की महफिल में उन्हें बिल्कुल आखिरी क्षणों में न्योता भेजा गया है। सवाल है कि मांझी का कार्यक्रम अचानक से बदल कैसे गया? किशनगंज में क्या नुकसान था और रांची में क्या नफा है?

यह बात सभी को पता है कि रांची में हेमंत के शपथ ग्रहण की तैयारियां झारखंड के चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद शुरू हो गई थीं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वहां की नई सरकार में शामिल होने जा रहे झामुमो, कांग्रेस और राजद के अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ राजग विरोधी कई पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा था। इनका जमावड़ा आज कुछ देर बाद रांची में दिखेगा भी। इसे इत्तेफाक मानें या इरादतन, जीतनराम मांझी का नाम इन मेहमानों की सूची में शनिवार के दिन तक नहीं था। जाहिर है कि यदि आपको न्योता ही न मिला हो तो फिर इच्छा रहने के बावजूद आप किसी दावत या महफिल में जाएंगे तो नहीं। लिहाजा मन मसोस कर ही सही, मांझी ने उन ओवैसी के मजमे का मुख्य अतिथि बनना स्वीकार कर लिया, जिनको लेकर बिहार में विपक्ष का महागठबंधन अभी दूरियां बनाए हुए है। दूरियां इसलिए, क्योंकि ओवैसी खुद को बिहार की मुस्लिम सियासत के नये दावेदार के तौर पर पेश करने की जुगत में है। उनकी इस दावेदारी को दम तब से मिला है, जबसे उनकी पार्टी ने हालिया उपचुनाव में किशनगंज विधानसभा सीट जीत ली है।

ऐसी उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल किशनगंज में आज ओवैसी की रैली में ठीक-ठाक भीड़ भी जुटेगी। महागठबंधन के राजद और कांग्रेस जैसे घटक बिहार में मुस्लिम वोटों की इस दावेदारी से कुछ ज्यादा परेशान हैं। इन दलों के कुछ नेता तो उन्हें भाजपा का एजेंट तक बताने से भी

असदुद्दीन ओवैसी।

जीतनराम मांझी।

गुरेज नहीं करते।

ओवैसी के इस उभार में अलग-अलग प्रदेशों में कुछ नेता और पार्टियां अपना नुकसान तो कुछ अपना नफा भी देखती हैं। बिहार के संदर्भ में यदि राजद या कांग्रेस ओवैसी के इस उभार को रोकना चाहेंगी तो मांझी की पार्टी जैसे छोटे दलों के नेता इसमें अपना हित देख रहे हैं। प्रदेश के जातीय और वर्गीय समीकरणों पर गौर करें तो मुस्लिम वोट के साथ किसी एक बड़ी जाति या वर्ग का जुड़ाव सत्ता की सीढ़ी को थोड़ा आसान बना देता है। विगत में लालू प्रसाद यादव की अगुआई में माई (मुस्लिम-यादव) समीकरण की सफलता इसका उदाहरण है। लालू ने मुस्लिम और यादवों के साथ दलितों को भी जोड़कर पंद्रह साल तक राज किया। बाद में नीतीश कुमार ने इस समीकरण को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि भाजपा के साथ मिलकर माई से बड़ा और व्यापक राजनीतिक आधार तैयार किया। नीतीश के इस राजनीतिक प्रयोग में निश्चित तौर पर दलितों की राजनीतिक ताकत भा स्थापित हुई। बड़ी संख्या में दलितों ने नीतीश का साथ दिया। नीतीश ने न सिर्फ महादलितों का एक नया मज़बूत वर्ग तैयार किया, बल्कि इस समाज के मांझी जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचाया। तब से मांझी की सियासी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से ऊंची हुई है। वह खुद को दलित राजनीति के नये दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिशों में हैं।

उधर, मुस्लिम सियासत की नई इबारत लिखने को आतुर ओवैसी को बिहार की मुख्य राजनीतिक धारा में प्रवेश पाने के लिए मांझी जैसे ही सही, किसी पतवार की जरूरत है। जाहिर है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ किशनगंज में आज रैली में मांझी ने बिना देर किए मुख्य अतिथि बनने का न्योता स्वीकार कर लिया। और तो और, ओवैसी की कृतज्ञता चुकाने के अंदाज में मांझी ने नागरिकता कानून को दलित विरोधी भी बता दिया।

बिहार में कुछ महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में महागठबंधन यह कतई नहीं चाहेगा कि मुस्लिम या दलित राजनीति का कोई नया पैरोकार मंच पर आए, क्योंकि इन दोनों ही आधारों में नीतीश की अगुआई में राजग काफी हद तक सेंध लगा चुका है। ऐसे में ओवैसी की महफिल को थोड़ा फीका करने के लिए मांझी को रोकना शायद जरूरी समझा गया। फिर क्या था, शनिवार को आनन-फानन में मांझी को रांची आने का न्योता भेजा गया। मांझी किशनगंज जाने को पहले से अनमने थे ही और उन्होंने बिना देर किए न्योता कुबूल कर लिया।

1 जनवरी से अपने वाहनों की कीमत में पांच फीसद का इजाफा करेगी वाहन कंपनी निसान मोटर इंडिया। बकौल कंपनी, निर्माण लागत बढ़ने के कारण वाहनों के दाम बढ़ाने पड़े हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 29 दिसंबर 2019

बंगाल

राजीव कुमार को नया पद दे रही सरकार

देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अफसरों की व्यापक कमी है। बंगाल में भी आइएएस और आइपीएस अफसरों की भारी कमी है। ऐसे में यदि जिस पद पर आइएएस को होना चाहिए, वहां आइपीएस को बैठाया जा रहा है तो इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है? एक आइएएस अफसर कई विभाग संभालते हैं। ऐसे में किसी आइपीएस को किसी विभाग का प्रधान सचिव बना दिया जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। बंगाल में सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटाले केवल इस राज्य में ही नहीं, देश भर में चर्चित रहे हैं और इन घोटालों के सुबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को ममता बनर्जी सरकार ने अब राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है। वह इससे पहले सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर थे। राजीव कुमार काफी तेज तर्रार पुलिस अफसर माने जाते हैं, लेकिन सारधा कांड की वजह से उनकी देश भर में काफी फजीहत हो चुकी है। इस मामले पर केंद्रीय स्तर पर भी राजनीतिक माहौल ममता के विपक्ष में बना था। वैसे यह पहला मौका है, जब आइटी विभाग के प्रधान सचिव के पद पर किसी आइपीएस अफसर की नियुक्ति हुई है। इससे पहले तक आइएएस अफसर ही यह पदभार संभालते आए हैं। वर्ष 1989 बैच के आइपीएस अफसर राजीव कुमार अब आइएएस अफसर देवाशीष सेन से यह कार्यभार लेंगे। हालांकि इस मामले में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि राजीव कुमार विगत 24 दिसंबर से डेढ़ महीने की छुट्टी पर हैं। उनके छुट्टी पर होने के दौरान उन्हें नई पोस्टिंग मिलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विभागीय सचिव के पद पर आमतौर पर आइपीएस अफसरों की नियुक्ति नहीं की जाती है, हालांकि ममता सरकार ने वर्ष 2015 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जेल विभाग के प्रधान सचिव के पद पर आइपीएस अफसर की नियुक्ति करने की अपील की थी, जो आइएएस कैडर का पोस्ट है। राज्य सरकार ने अब आइएएस अफसर ए सुबैया को जेल विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले इस पद पर आइपीएस अफसर संजय मुखर्जी थे। राजीव कुमार के ट्रांसफर के बाद अब एडीजी (सीआइडी) का पद कौन संभालेगा, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। मालूम हो कि राजीव कुमार की अनुपस्थिति में सिद्धिनाथ गुप्ता उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटालों की जांच कर रही सीबीआइ राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। बीते अक्टूबर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी। सीबीआइ ने राजीव कुमार की जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे समय में राजीव कुमार को नया पद दिए जाने को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है।

चिटफंड घोटाले के सुबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे अफसर राजीव कुमार को ममता सरकार ने राज्य के आइटी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है

बिहार

चिकित्सकों की बर्खास्तगी का सही कदम

कई बार आपने खबरों में ऐसी सुना होगा या पढ़ा होगा कि अमुक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या फिर चिकित्सक बिना सूचना के लंबे समय से गायब रहा और उस पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो पाई। कई बार आपने स्वयं भी ऐसा महसूस किया होगा। खासकर बिहार में तो ऐसे अनेक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां चिकित्सक कई दिनों तक पहुंचते ही नहीं हैं। कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जहां की व्यवस्था वहां पदस्थापित गैर-स्वास्थ्यकर्मी यानी क्लर्क स्तर के कर्मचारी के माध्यम से चलती है और नर्सिंग स्टाफ के भरोसे पूरे दिन काम चलता है। शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानियों के कारण भी दिल्ली और अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली में यह मामला काफी उछला था कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में यहां आकर इलाज सस्ते में करा लेते हैं।

ऐसे में बिहार के लोगों की दिक्कतों को सरकार ने संज्ञान में लिया है और बिना सूचना के लंबे समय से गायब चल रहे 15 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर राज्य सरकार ने कड़ा संदेश दिया है। यह बिल्कुल सही कदम है। सरकार आखिर उनलोगों को सेवा में क्यों रखे, जिन्हें नियम-कानून और अपनी ड्यूटी की कोई परवाह ही नहीं है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के प्रयास में ऐसे कदम उठाने ही होंगे। स्थिति यह है कि लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिले

प्रतीकात्मक

के अस्पतालों में आते हैं, पर डॉक्टर से भेंट नहीं हो पाती है। कई जगहों पर तो आयुष चिकित्सक या पैरा मेडिकल कर्मचारियों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाने की वजह से उन्हें मौत का भी शिकार होना पड़ता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन पर मरीजों की जिंदगी, उनका भरोसा टिका है, वे उस ड्यूटी तक को नहीं समझ पाए। अस्पतालों में नहीं आना और निजी प्रैक्टिस करना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ऐसे में डॉक्टरों को यह समझना होगा कि उन पर समाज का कितना बड़ा दायित्व है। उन्हें लोग धरती का भगवान समझते हैं। लेकिन वही अपना दायित्व भूल जाएं तो क्या होगा। राज्य के नियम-कायदे होते हैं, कोई भी व्यवस्था इसी से चलती है। अगर हर कोई अपनी मनमर्जी करने लगे, तब तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी। सरकार डॉक्टरों को वेतन देती है, उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। यह वेतन जनता के टैक्स से मिलता है, तो फिर उनके प्रति यह उपेक्षित और लापरवाही भरा रवैया क्यों। आश्चर्य तो यह कि विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित ये डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित हैं और इस संबंध में विभाग को कोई सूचना देने की भी जरूरत नहीं समझी। यह तो खुद को नियम-कानून से ऊपर समझने वाली बात हो गई। आश्चर्य तो यह भी कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या इस अवधि में वेतन का भी भुगतान होता रहा? जिन इलाकों में ये डॉक्टर पदस्थापित थे, वहां के लोगों को इतने लंबे समय तक जो असुविधा झेलनी पड़ी, उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आखिर किसी की मनमर्जी का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? अगर सरकारी सेवा में आए हैं तो उस अनुरूप आचरण और नियमों का अनुपालन अपरिहार्य है। इससे विमुख होने पर कार्रवाई भी लाजिमी है। इस लिहाज से सरकार ने बर्खास्तगी जैसे कदम उठाकर बिल्कुल सही संदेश दिया है।

उत्तराखंड

संसाधनों की बढ़ती हुई चुनौती

देश भर में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए तकरीबन सभी राज्य सरकारें अपनी ओर से विविध किस्म के कवायद करती रहती हैं। खासकर ऐसे राज्यों में यह चुनौती बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो भौगोलिक लिहाज से बेहद विषम हो, क्योंकि ऐसे राज्यों में अन्य राज्यों के मुकाबले आमदनी के स्रोत सीमित होते हैं। इसी कवायद के तहत उत्तराखंड प्रदेश सरकार भी आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए हाथ-पांव मार रही है, लेकिन उसे अब तक अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई। हालत ये है कि जिन क्षेत्रों में लंबे अरसे से आमदनी बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है, वहां पेश आने वाली रुकावटें दूर करने को संबंधित महकमे पुख्ता रोडमैप तक बना नहीं पा रहे हैं। खनन के साथ कमोबेश यही हो रहा है। पिछले तकरीबन तीन साल से उपखनिजों के चुगान को लेकर कई बार नीति में संशोधन किया जा चुका है। हर साल कोशिश यही की जा रही है कि पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुरक्षित और जरूरी खनन को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो। तस्वीर उलट है। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य के इर्द-गिर्द भी राजस्व वसूली नहीं पहुंच रही है।

राज्य में गैर विकास मदों में खर्च तो बढ़ रहा है, पर तुलनात्मक रूप से आय बढ़ाने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ना लाजिमी है।

हालांकि इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश में अवैध तरीके से खनन रोकने में सरकारी मशीनरी के दम फूल रहे हैं। इसी तरह खनन के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने को भी ठोस तैयारी नदारद है। मुख्य सचिव को इस मामले में संबंधित महकमों को हिदायत देनी पड़ी है।

दरअसल उपखनिज चुगान व्यावसायिक गतिविधियों व राजस्व वृद्धि से जुड़ा मसला तो है ही, साथ में सुरक्षित खनन नहीं होने की स्थिति में बरसात के मौसम में नदियों से बाढ़ का खतरा भी उपस्थित होता है। बेहतर यही होगा कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर खनन को लेकर पारदर्शी नीति बनाई जाए, जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के कारगर उपाय हों। खनन के साथ जीएसटी, आबकारी, स्टांप और रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा और वनों से होने वाले कर राजस्व को बढ़ाने की चुनौती भी बरकरार है। ऊर्जा महकमे में कर वसूली की हालत भी चिंताजनक है। पिछली समीक्षा बैठक में भी इसमें सुधार के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे। विभाग कर और करेत्तर राजस्व दोनों ही मोर्चे पर वसूली पर खरा नहीं उतर पाया। छपान और लीसा की बिक्री को लेकर वन महकमे के हालात भी खासे अच्छे नहीं हैं। आमदनी कम और खर्च बेतहाशा होने की समस्या से परेशानहाल सरकार पर आर्थिक संसाधनों में इजाफा करने का भारी दबाव है। इन संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर गठित नीति नियोजन प्रकोष्ठ समय-समय पर सुझाव देता रहता है, लेकिन करों में वृद्धि का जोखिम लेने के मूड में सरकार नहीं है। हालांकि जन सेवा से जुड़े महकमों की कार्यप्रणाली में सुधार और सुविधाओं को बेहतर बनाकर यह कदम उठाया जा सकता है। इसके लिए महकमों को काफी कुछ बदलाव करने होंगे।

झारखंड

परीक्षा के मामले पर ठोस निर्णय जरूरी

झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। झारखंड राज्य बनने से पहले भी जब वह बिहार का हिस्सा था तब भी हालात कमोबेश ऐसे ही थे। हालांकि इस दशा में सुधार के लिए कई बार प्रयास जरूर किए गए हैं लेकिन अब तक अपेक्षित कामयाबी मिल नहीं पाई है। राज्य में इसका असर सिविल सेवा पर भी पड़ा है। ऐसे में झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर ठोस निर्णय लिया जाना जरूरी है। नई सरकार के गठन बाद इस परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वह इस पर ठोस निर्णय लेकर परीक्षा प्रक्रिया को पूरी कराएगी।

यह उम्मीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सरकार ने ही अपने पिछले कार्यकाल में यह परीक्षा शुरू कराई थी। तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार में यह परीक्षा बदले पैटर्न में शुरू हुई थी। लेकिन, बाद में सरकार बदलने पर इसमें फिर से बदलाव कर दिया गया था। इस बीच पांच साल बीत गया और यह परीक्षा बार-बार विवादित रहने के कारण मुकाम तक नहीं

प्रतीकात्मक

पहुंच पाई। इसकी प्रारंभिक परीक्षा ही लगातार विवादित रही और इस कारण जेपीएससी को इसके परिणाम में तीन-तीन बार संशोधन करने पड़े। अभी भी इसकी मुख्य परीक्षा का परिणाम झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद लंबित है। इसके बाद इस पर न तो राज्य सरकार कोई निर्णय ले पाई और न ही झारखंड लोक सेवा आयोग। कोर्ट के आदेश के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए या इस आदेश को चुनौती दी जाए, इसपर भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस परीक्षा में शामिल अन्य अभ्यर्थी संशय में हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिनकी उम्र इस परीक्षा की तैयारी में बीत गई है। उन्हें इस बात की भी आशंका है कि कहीं बाद में भी यह मामला कोर्ट में जाकर विवादों में न फंस जाए। यह परीक्षा पूरी नहीं होने के कारण अगली सिविल सेवा परीक्षा भी लंबित है। जो परीक्षा प्रत्येक साल होनी चाहिए थी, वह उन्नीस वर्ष में महज पांच बार ही पूरी हो पाई है। अब हेमंत सोरेने की अगुवाई में नई सरकार से उम्मीद वाजिब है कि यह न केवल इस पर ठोस निर्णय लेगी, बल्कि अगली परीक्षाओं के लिए आवश्यक नियमावली भी बनाएगी, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो।

डाटागीरी

वैश्विक लैंगिक समानता में आइसलैंड सबसे आगे

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

बीते दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की तरफ से एक सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में आइसलैंड सबसे ऊपर है, जबकि नार्वे और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। रिपोर्ट में लैंगिक समानता का निर्धारण आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका व राजनीतिक सशक्तीकरण के पैमाने पर किया गया है। डब्ल्यूईएफ का कहना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का विश्लेषण 'अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कार्यकारी अधिकारियों के सर्वे की संयुक्त पद्धति' के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में महिला और पुरुषों के बीच की असमानता का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को पैमाना बनाया गया है। इस वार्षिक मापदंड के जरिये रिपोर्ट कहती है, 'हर देश के हितधारक प्रत्येक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अपनी प्राथमिकता तय करने में सक्षम हैं।'

रिपोर्ट की खास बातें

- वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता 68.6 फीसद है। पिछली बार की तुलना में इसमें सुधार हुआ है।
- राजनीतिक सशक्तीकरण के स्तर पर सबसे अधिक असमानता है। दुनियाभर में 35,127 संसदीय सीटों में महज 25 फीसद पर ही महिलाओं का कब्जा है और 3,343 मंत्रियों में सिर्फ 21 फीसद ही महिलाएं हैं।
- मौजूदा रुझानों को देखते हुए सभी वैश्विक लैंगिक अंतर को दूर करने में औसतन 99.5 वर्ष लगेंगे। रिपोर्ट के पहले अंक से अभी तक 107 देशों को लगातार इसमें शामिल किया गया।
- मौजूदा हिसाब से पश्चिमी यूरोप में लैंगिक असमानता खत्म करने में 54 वर्ष, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में 59 वर्ष, दक्षिण एशिया में 71.5 वर्ष, सब-सहारा अफ्रीकी देशों में 95 वर्ष, पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में 107 वर्ष, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 140 वर्ष, उत्तरी अमेरिका में 151 वर्ष और पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 163 वर्ष लगेंगे।

वैश्विक लैंगिक असमानता इंडेक्स रैंकिंग 2020

रैंकिंग	देश	स्कोर
1.	आइसलैंड	0.877
2.	नार्वे	0.842
3.	फिनलैंड	0.832
4.	स्वीडन	0.820
5.	निकारगुआ	0.804
6.	न्यूजीलैंड	0.799
7.	आयरलैंड	0.798
8.	स्पेन	0.795
9.	रवांडा	0.791
10.	जर्मनी	0.787
21.	ब्रिटेन	0.767
50.	बांग्लादेश	0.726
53.	अमेरिका	0.724
81.	रूस	0.706
92.	ब्राजील	0.691
101.	नेपाल	0.680
102.	श्रीलंका	0.680
106.	चीन	0.676
112.	भारत	0.668
121.	जापान	0.652
151.	पाकिस्तान	0.564
153.	यमन	0.494

कंपनियों में महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रतिशत
(हर वर्ग में शीर्ष पांच देश)

देश	प्रतिशत
30 फीसद से अधिक	
फ्रांस	43.4
आइसलैंड	43
नार्वे	42.1
स्वीडन	36.3
इटली	34
20 फीसद से अधिक	
नीदरलैंड	29.5
लातविया	28.8
ऑस्ट्रेलिया	28.7
ब्रिटेन	27.2
कनाडा	25.8
10 फीसद से अधिक	
ऑस्ट्रिया	19.2
आयरलैंड	17.6
पुर्तगाल	16.2
स्लोवाक गणराज्य	15.1
कोलंबिया	15.1
भारत	13.8

हरियाणा की जेलों में कैदी करेंगे जहर मुक्त खेती

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जुटा रहे फीडबैक, आचार्य देवव्रत से करेंगे मुलाकात
- जेल अधीक्षकों को आचार्य से जीरो बजट प्राकृतिक खेती का फार्मूला सीखने के निर्देश
- कृषि विभाग पहले ही दिखा चुका जीरो बजट खेती के फार्मूले में रुचि

प्रतीकात्मक

हरियाणा की जेलों में खाली पड़ी जमीनों पर जहर मुक्त (आर्गेनिक) खेती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जेलों में न केवल आर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएंगी, बल्कि कैदियों के इस्तेमाल के बाद जो भी सब्जियां बचेंगी, उन्हें मार्केट में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बाहर लाया जा सकेगा। राज्य के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सभी जेलों में खाली पड़ी जमीनों का ब्योरा जुटाने में लगे हैं, ताकि पूरे प्रदेश में जेलों के भीतर आर्गेनिक खेती की शुरुआत की जा सके।

हरियाणा में प्राकृतिक खेती की परिकल्पना गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राचार्य रहते उन्होंने जीरो बजट जहर मुक्त खेती की परिकल्पना की थी, लेकिन हिमाचल के राज्यपाल रहते हुए उनकी इस परिकल्पना को देश भर में स्वीकार किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य की प्राकृतिक खेती के प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई। अब गुजरात के राज्यपाल के रूप में आचार्य जीरो बजट प्राकृतिक खेती के कांसेप्ट को पूरे देश में लाने पर गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

क्या है आचार्य देवव्रत का जीरो बजट खेती फार्मूला

आचार्य देवव्रत देश के ऐसे पहले राज्यपाल हैं, जो लोकसभा में जैविक कृषि पर कार्यशाला के दौरान देश के नीति निर्धारक सांसदों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर इसी साल चार जनवरी को आचार्य देवव्रत ने जीरो बजट खेती का फार्मूला पेश किया, जो अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में दस्तावेज बन चुका है। जीरो बजट खेती से मतलब रासायनिक खादों की बजाय बिना लागत वाली प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल से है। एक एकड़ जमीन के लिए जैविक खाद जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में 10 किलो देसी गाय का गोबर, पांच से 10 लीटर गोमूत्र, एक से डेढ़ किलो गुड़, एक से डेढ़ किलो बेसन, थोड़ी खेत की मिट्टी मिलाकर घोल बनाया जाता है। घोल को एक टंकी में रखकर दो-तीन मिनट तक हिलाएं और इसके बाद इसे बोरी से ढक कर 72 घटे के लिए छांव में रख दें। सुबह शाम घोल को दो-दो मिनट के लिए हिलाते रहें। इस घोल को सप्ताह के अंदर प्रयोग से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

आर्गेनिक खेती करने वालों को मुफ्त की जा सकती है बिजली-पानी

किसान नेता के रूप में स्थापित हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आर्गेनिक खेती के प्रचार प्रसार को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इस बात की संभावनाओं पर भी विचार चल रहा है कि यदि कोई किसान पूरी तरह से आर्गेनिक खेती पर आ जाएगा तो उसे बिजली व पानी की सप्लाई मुफ्त की जा सकती है। सरकार हालांकि पहले ही कम रेट पर किसानों को बिजली व पानी देती है, लेकिन आर्गेनिक खेती करने वालों पर पहले से पड़ने वाला खर्च और भी कम हो जाएगा। साथ ही लोगों को जहर मुक्त खाना भी मिल सकेगा।

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी जीरो बजट प्राकृतिक खेती के आचार्य देवव्रत के प्रोजेक्ट से पूरी तरह सहमत हैं। इस खेती की बारीकियों को समझने के लिए दलाल ने पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल को गुजरात भी भेजा था। अब जेल मंत्री चौ. रणजीत सिंह चौटाला ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। हरियाणा में कोई जेल ऐसी नहीं है, जिसके पास अपनी खुद की खाली जगह नहीं है। वहां अभी भी खेती हो रही है, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला इस खेती को प्राकृतिक जहर मुक्त खेती में बदलने की आचार्य देवव्रत की अवधारणा पर आगे बढ़ने जा रहे हैं।

जेल मंत्री रणजीत चौटाला रविवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों पर बारीकी से बातचीत करेंगे। चौटाला ने सभी जेल अधीक्षकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं अथवा कोई कोई सीनियर प्रतिनिधि भी रविवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत के साथ होने वाले संवाद में शामिल हो, ताकि सभी जेलों में आर्गेनिक खेती की संभावनाओं पर तेजी के साथ आगे कदम बढ़ाए जा सकें।

जेलों में तैयार होगी आर्गेनिक फसलों की पौध : हरियाणा की जेलों में आर्गेनिक खेती के साथ-साथ नई पौध भी तैयार की जाएगी। इस पौध को तैयार करने में सरकार खासकर जेल विभाग का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। जेल में बंद कैदी हर रोज वहां दिहाड़ी करते हैं। उन्हें जब आर्गेनिक खेती की आदत पड़ेगी और इसमें रुचि होगी तो तैयार पौध को जेल से बाहर भी सप्लाई कर परियोजना को गति प्रदान की जा सकेगी।

झारखंड में अप्रशिक्षित व पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश स्थगित

राज्य ब्यूरो, रांची

- पारा शिक्षकों में हर्ष, नई सरकार के प्रति जताया आभार
- हाई कोर्ट ने लगा दी थी रोक, इसके बावजूद जारी कर दिया था आदेश
- मामला संज्ञान में आने के बाद आनन-फानन स्थगित किया आदेश
- 31 मार्च तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर की गई थी कार्रवाई

प्रतीकात्मक

झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों व पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने संबंधित अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। विभाग ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपने आदेश को स्थगित किया। इससे पहले, विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों व पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को जारी कर दिया था। शनिवार को सभी अखबारों में इस आशय की खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग न आनन-फानन में उक्त आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया।

विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी (एस) 6701/19 वाद लंबित है। इस मामले में न्यायालय के आदेश आने तक इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

इधर, उक्त आदेश वापस लेने के बाद पारा शिक्षकों में हर्ष है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय कुमार दूबे ने कहा है कि नई सरकार की इस घोषणा से साढ़े चार हजार अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके लिए मोर्चा ने नई सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया गया था। इस अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले लगभग साढ़े चार हजार पारा शिक्षकों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके लिए मोर्चा ने नई सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया गया था। इस अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले लगभग साढ़े चार हजार पारा शिक्षकों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहले ही कार्यमुक्त कर दिया है। इधर, हाई कोर्ट ने इसी साल अक्टूबर में जारी अपने आदेश में राज्य सरकार का यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इसके बाद कई जिलों में अप्रशिक्षित पारा शिक्षक काम पर वापस लौट आए हैं। इधर, विभाग ने 24 दिसंबर को सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश दोबारा जारी कर दिया। यह आदेश ही स्थगित किया गया है। हालांकि इस संबंध में सभी जिलों को पत्र सोमवार को भेजा जाएगा।

विभाग के आदेश के बाद जिलों में भी जारी हो गया आदेश

अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने संबधित पत्र मिलने के बाद कुछ जिलों ने इसे लागू करने का भी आदेश जारी कर दिया। रांची में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में शनिवार को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, अवर विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया था।

पचमढ़ी की वनस्पतियों पर शोध कैंसर का इलाज होगा संभव

आशीष दीक्षित, होशंगाबाद

- लखनऊ रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों को उपलब्ध कराए वनस्पतियों के नमूने
- प्रारंभिक शोध में पांच तरह की वनस्पतियां विलुप्तप्राय पाई गईं

मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पाई जाने वाली वनस्पतियों पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ रिसर्च सेंटर में शोध किया जा रहा है। वहां के विशेषज्ञों ने पचमढ़ी में पाई जाने वाली 1439 वनस्पतियों के नमूने लिए हैं। प्रारंभिक शोध में पाया गया है कि इनमें से पांच तरह की वनस्पतियां विलुप्तप्राय हैं। जानकारों की मानें तो कुछ वनस्पतियां कैंसर और पथरी की बीमारी के इलाज में उपयोगी हो सकती हैं। विस्तृत शोध रिपोर्ट का इंतजार है।

पाई जाती हैं कुल 1439 वनस्पतियां: गौरतलब है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र वानस्पतिक विविधता की संगम स्थली है। यहां थैलोफाइट्स की 30, ब्रायोफाइट्स की आठ, टेरिडोफाइट्स की 71, जिम्नोस्पर्म की सात एवं एंजियोस्पर्म की 1200 प्रजातियां सहित कुल 1439 वनस्पतियां पाई जाती हैं।

वर्ष 1999 में बना संरक्षण क्षेत्र : पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयोग संरक्षण क्षेत्र है। यह मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया था।

हिमालय की वादियों की दुर्लभ वनस्पतियां भी यहां मिलीं : विशेषज्ञों के अनुसार, पचमढ़ी के जंगलों से दो दुर्लभ प्रजातियों के आर्किड (रंग-बिरंगे फूलों वाले विभिन्न आकार के पौधे) मिले हैं। आयुर्वेद में इन्हें जीवक तमेलेक्सिस मूसीफेरा और जीवंती तडेंड्रोबियम मेक्रिया नाम से जाना जाता है। करीब चार साल पहले पचमढ़ी के जंगलों में यूलोफिया ओकरियेटा और नरवेलिया प्रेनियाना आर्किड मिले थे। यह हिमालय की वादियों में पाए जाते हैं।

> पचमढ़ी में कई दुर्लभ वनस्पतियां हैं। इन्हें संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन वनस्पतियों पर शोध किया जा रहा है।
> -डॉ. ओएन चौबे, प्राचार्य, शासकीय नर्मदा कॉलेज, होशंगाबाद

> लखनऊ रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों की टीम वनस्पतियों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। वनस्पतियों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
> -एसके सिंह, संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद

95 वें रेडिट गिफ्ट्स एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेने वाले माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स एक 33 वर्षीय अमेरिकी महिला को सीक्रेट सांता के तौर पर मिले। गेट्स ने महिला को मूवीज, वीडियो गेम्स के अलावा 37 किलो किताबें तोहफे में भेजीं।

थमने वाला है भारतीय टेनिस का पेस

खत्म होते साल के साथ टेनिस की दुनिया से एक ऐसी खबर आई, जिसने इस खेल के प्रशंसकों को एक पल के लिए थाम दिया। यह खबर थी दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस के संन्यास की। करीब तीन दशक टेनिस कोर्ट पर बिताने के बाद अगले वर्ष वह इस खेल को अलविदा कहेंगे। आइए जानते हैं उनके इस लंबे और शानदार करियर के बारे में, जिसमें जुड़े हैं कुछ विवाद भी...

46 वर्षीय पेस का जन्म कोलकाता में हुआ था

07 ओलंपिक गेम्स में खेलने वाले भारत के इकलौते टेनिस खिलाड़ी

08 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन हैं। ये सभी खिताब उन्होंने पुरुष और मिक्स्ड डबल्स में जीते हैं

05 स्वर्ण पदक एशियन गेम्स में जीते हैं, जबकि 2010 दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कांस्य पदक जीतन में सफल रहे थे

73 वीं विश्व सिंगल्स रैंकिंग पेस के करियर में सर्वश्रेष्ठ रही है, जबकि डबल्स में वह महेश भूपति के साथ नंबर एक खिलाड़ी रह चुके हैं

54 डबल्स खिताब अपने तीन दशक के करियर में खेले हैं पेस ने। वह डेविस कप इतिहास के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी रहे हैं। डेविस कप में पेस के नाम 43 जीत हैं

08 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन हैं। ये सभी खिताब उन्होंने पुरुष और मिक्स्ड डबल्स में जीते हैं

सुर्खियों में

निखिल शर्मा, नई दिल्ली

38 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 20 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर विश्व टेनिस के लिए बेहद अनमोल हैं, लेकिन भारत ने विश्व टेनिस को एक ऐसा दिग्गज दिया, जिसका करियर ही 2020 में 30 साल का हो जाएगा। यह दिग्गज और कोई नहीं 46 वर्षीय लिएंडर पेस हैं। सही मायनों में पेस टेनिस कोर्ट के सबसे युवा जादूगर हैं। उन्होंने वर्ष 1991 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने गत बुधवार को अगले वर्ष टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वह अगले वर्ष चुनिंदा टूर्नामेंट में ही खेलेंगे और 2020 टोक्यो ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक होगा। कह सकते हैं कि इसी के साथ भारतीय टेनिस का एक दौर भी थम जाएगा।

पेस से बढ़कर कोई नहीं: फेडरर ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 20 सिंगल्स खिताब जीते हैं। दुनिया भले ही फेडरर को टेनिस का सबसे बड़ा दिग्गज मानती हो, लेकिन 46 वर्ष की उम्र में भी टेनिस के कोर्ट पर किसी युवा की तरह दौड़ने वाले पेस ने अपने करियर में 18 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें से आठ बार पुरुष डबल्स में और 10 बार मिक्स्ड डबल्स में जीते गए खिताब शामिल हैं। पेस ने फेडरर के कुल ग्रैंडस्लैम खिताब से मात्र दो कम जीते हैं।

1996 का ऐतिहासिक पल: पेस ने 1996 के एटलांटा ओलंपिक में पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। वह सात बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। 2020 में वह ओलंपिक में आठवीं बार उतरने के लिए तैयार हैं। यही नहीं पेस के नाम एशियन गेम्स में पांच स्वर्ण पदक भी हैं।

भूपति के साथ यादगार जोड़ी: पेस ने मिक्स्ड डबल्स में मार्टिना हिंगिस के साथ कई खिताब जीते, लेकिन पुरुष डबल्स में भारत के ही महेश भूपति के साथ उनकी जोड़ी को हमेशा याद रखा जाएगा। दोनों के लिए 1999 का वह समय यादगार रहा था, जब दोनों ने साथ में तीन डबल्स खिताब जीते थे, जिसमें फ्रेंच ओपन और विंबल्डन जैसे ग्रैंडस्लैम खिताब भी शामिल थे।

इस तरह चाहते हैं अलविदा: पेस ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे 2020 टेनिस कैलेंडर का इंतजार है, जिसमें मैं चुनिंदा टूर्नामेंट खेलूंगा, टीम के साथ यात्रा करूंगा और दुनियाभर में अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जश्न मनाऊंगा। आप सभी की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं इस साल आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं।

विवादों में भी रहा नाम: पेस को हमेशा से ही खुलकर बोलने वाला खिलाड़ी माना गया है। पेस और भूपति विश्व टेनिस में अपनी चमक बिखेर रहे थे, लेकिन फिर 2006 में वो समय आया जब दोनों के बीच दरार आ गई। 2006 में दोहा एशियन गेम्स में डबल्स का खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी अलग हो गई। भूपति ने तब कहा था कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। यह मेरा नहीं पेस का फैसला है। हमारी कहानी भारतीय खेल की सबसे खराब कहानी है। मैं खुश हूं कि इस कहानी का अब अंत हो रहा है। पेस उस समय लगातार भूपति के खराब खेल पर सवाल उठा रहे थे और भूपति को यह पसंद नहीं था। इसके बाद दोनों एक बार फिर 2008 ओलंपिक में साथ खेले और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। एक समय ऐसा भी आया जब डेविस कप टीम के खिलाड़ियों भूपति, प्रकाश अमृतराज, रोहन बोपन्ना ने पेस को टीम से बाहर करने की बात रख दी।

सानिया भी रूठीं: 2012 ओलंपिक में अखिल भारतीय टेनिस संघ ने मिक्स्ड डबल्स के लिए सानिया मिर्जा और पेस की जोड़ी बनाई। मिर्जा को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने नाराजगी जता दी। मिर्जा ने खुलेआम कहा कि उनकी जोड़ी महेश के साथ अच्छी है। हालांकि, बाद में मिर्जा ने कहा था कि वह किसी भी खिलाड़ी के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। 2014 में वह समय आया जब पेस और उनकी पत्नी रिया पिल्लई अलग हो गए। वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ रहे थे और उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। तब भूपति खुलकर सामने आए थे और कहा था कि पेस कभी किसी को गाली या मार नहीं सकता है।

पिता ने बताया बेटे का सपना: पेस के पिता वेस पेस ने हमेशा अपने बेटे का समर्थन किया। तब भी जब उन्होंने भूपति और रोहन बोपन्ना पर बेटे के खिलाफ एक होने का आरोप लगाया और अब भी जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। वेस ने कहा कि डेविस कप मार्च में है और फिर जुलाई-अगस्त में टोक्यो में ओलंपिक है। पेस दोनों स्पर्धाओं में देश के लिए खेलना चाहते हैं और अपना शत-प्रतिशत देना चाहते हैं। वह 35 साल खेलने के बाद इस खेल को अलविदा कहेंगे। वेस ने आगे कहा लिएंडर बीते चार-पांच महीनों से संन्यास के बारे में सोच रहा था। वह 46 का हो गया है और अब उम्र उस पर हावी होने लगी है। वह अपनी बेटी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है और यही कारण है कि उसने 2020 में टेनिस को अलविदा कहने का मन बनाया है।

मां चाहती थी इंजीनियर, बन गए सीएम

चर्चित चेहरा

प्रदीप सिंह, रांची

झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर पूरे देश की निगाहें थीं। जिस राज्य के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री (रघुवर दास) ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, उस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सभी के जहन में यह सवाल था। गत 23 दिसंबर को जैसे-जैसे परिणाम आते गए, वैसे-वैसे तस्वीर साफ होती चली गई। जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। छह साल पहले वह 16 माह की छोटी सी अवधि के लिए सीएम रह चुके हैं, लेकिन 29 दिसंबर यानी आज वह रांची के मोरहाबादी मैदान में दूसरी बार इस पद की शपथ लेंगे।

महज 44 साल की उम्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने जा रहे हेमंत भले ही राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हों, लेकिन उनकी मां रूपी सोरेन ने उनके लिए कुछ और ही सपने देख रहे थे। मां उन्हें इंजीनियर बनाना चाहती थीं। हेमंत ने 1990 में पटना के एमजी हाईस्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 1994 में 12वीं पास की। मां की इच्छा को देखते हुए हेमंत ने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआइटी) मेसरा में दाखिला लिया, लेकिन इंजीनियरिंग में मन नहीं रमा। पढ़ाई बीच में छोड़ 2003 में छात्र मोर्चा की राजनीति में जुट गए। पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को संभालने की जवाबदेही भी थी। आखिरकार हेमंत को शौकिया राजनीति छोड़ गंभीर राजनीति में आना पड़ा। वह साल था 2009, जब उनके भाई और कद्दावर नेता दुर्गा सोरेन का निधन हुआ। पिता की उम्र हो रही थी और भाई के आकस्मिक निधन ने उन्हें पूरी तरह से राजनीति में खींच लिया। इंजीनियरिंग कराने का उनकी मां का सपना अधूरा रह गया, लेकिन हेमंत ने काफी कम उम्र में राजनीतिक ऊंचाइयों को छू लिया।

इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड की सत्ता से भाजपा को हटाकर उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर खुद को स्थापित करने में सफलता पाई है। इंजीनियरिंग नहीं कर पाने का मलाल हेमंत को है, लेकिन इस बात का इत्मीनान भी है कि उन्हें उस झारखंड की सेवा करने का मौका मिला है जिसे बड़े संघर्ष के बाद उनके पिता ने आंदोलन कर हासिल किया था।

महज 44 साल की उम्र में दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने जा रहे **हेमंत सोरेन** को राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन उनकी मां की इच्छा उन्हें इंजीनियर बनाने की थी। आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हेमंत का सियासत के साथ-साथ कला से भी गहरा जुड़ाव है। उन्हें पेंटिंग और फोटोग्राफी बेहद पसंद है और समय मिलने पर अकेले ड्राइविंग पर निकल जाते हैं...

झारखंड के रामगढ़ के गोला स्थित पैतृक आवास पर पत्नी कल्पना सोरेन (बीच में) के साथ हेमंत सोरेन खाना बनाने में सहयोग करते हुए। सबसे बाएं उनकी परिजन। सौजन्य :-हेमंत की फेसबुक वॉल से

दिल में बसता है कलाकार: हेमंत अक्सर बीआइटी मेसरा के कैंपस को मिस करते हैं। हाल ही में उन्होंने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने कॉलेज कैंपस की कई तस्वीरें लीं और उन्हें साझा किया। दरअसल, राजनीतिक परिवेश में पले-बढ़े हेमंत के दिल में कहीं न कहीं एक कलाकार भी बसता है। उन्हें चित्रकारी और फोटोग्राफी का बहुत शौक है। वह फुर्सत के क्षण में अपनी पेंटिंग और तस्वीरें दिखाना नहीं भूलते। वह अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले पत्र और स्केच संभालकर रखते हैं। उनका एक और शौक सेल्फ ड्राइविंग का है। अक्सर वह अपनी कार से राजधानी में घूमते देखे जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी हेमंत अक्सर हेलमेट लगाकर बाइक चलाकर रांची घूमने निकल जाते थे। इस दौरान उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता था। चुनाव के बाद भी उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह साइकिल चलाकर अपने बेटे को घुमाते दिखे। उन्हें किताबें पढ़ना भी बेहद पसंद है। यही वजह है कि चुनाव में जीत के बाद उन्होंने प्रशंसकों से बुके की जगह किताबें तोहफे में देने को कहा। हेमंत के पसंदीदा स्थान की बात की जाए तो रांची से सटी पतरातू घाटी उन्हें बहुत पसंद है, जहां की खूबसूरती निहारने वह अक्सर जाते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पालतू कुत्ते उनके पास हैं। लगातार थकान भरी यात्रा के कारण उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ती है, लेकिन वह मिलने आए लोगों को निराश नहीं करते।

झामुमो को बनाया हाईटेक

हेमंत सोरेन को पारंपरिक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को हाईटेक बनाने का श्रेय जाता है। 2014 में उन्होंने भाजपा की तर्ज पर मिस्ड काल से संगठन का सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया। इसे बेहद सफलता मिली। वह लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रिय रहते हैं और लाइव शो में लोगों से रूबरू भी होते हैं। हेमंत का लाइफस्टाइल रूढ़िवादिता और आधुनिकता का मिश्रण है। वह पर्व-त्योहार के मौकों पर पारंपरिक संताली पहनावे में दिखते हैं, तो रोजमर्रा का उनका पसंदीदा पहनावा टीशर्ट-जींस है। सामान्य नेताओं की तरह पारंपरिक कुर्ता-पायजामा में वह ज्यादा नहीं दिखते। पूरी तरह शाकाहारी हेमंत ने जहां संगठन में अपने पिता शिबू सोरेन की पीढ़ी के नेताओं को भी सहेजकर रखा है वहीं दल की दूसरी पंक्ति का नेतृत्व भी तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद वह बच्चों निखिल और अंश को क्वालिटी टाइम देते हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रांची में एक स्कूल का संचालन करती हैं।

ले. जनरल नरवाने : नया मोर्चा, नई चुनौती

इनसे मिलिए

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

एक तरफ अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी की स्थिति और दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर असम में जारी प्रदर्शनों का दौर, ऐसे समय में भारतीय सेना की कमान उस शख्सियत को सौंपी जा रही है जो कश्मीर और असम के हालात से निपटने में माहिर है। बात हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख बिपिन रावत की जगह लेंगे। नरवाने फिलहाल सेना के उप प्रमुख हैं। सितंबर में उप थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे।

सेना के मुताबिक, नरवाने के पास सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने लंबा अनुभव है। इनके नेतृत्व में कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और उग्रवाद रोधी कई अभियानों को सफल अंजाम दिया गया। वहीं, डोकलाम में जब चीनी सेना को अतिक्रमण करने से रोका गया तब नरवाने ही मोर्चे पर डटे थे और उन्होंने चीन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया।

22 अप्रैल, 1960 को मराठी परिवार में जन्मे नरवाने का कमीशन जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की सातवीं बटालियन में हुआ था। पिता वायु सेना में विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि मां ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक थीं। पुणे के जनाना प्रबोधिनी प्रशाला से स्कूली शिक्षा लेने के बाद एनडीए के लिए चयनित हुए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली। उन्होंने चेन्नई की यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से डिफेंस स्टडी में मास्टर की डिग्री ली है व इंदौर के देवी अहिल्या विवि से डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडी में एफ.फिल किया। यह एक संयोग है कि नरवाने के अलावा वर्तमान वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया व नौसेना चीफ करमबीर सिंह भी एनडीए के 56वें बैच से ही हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने फाइल

आगामी 31 दिसंबर को सेना प्रमुख बिपिन रावत अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उनकी जगह लेंगे **लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने**। जानते हैं उनके यहां तक के सफर के बारे में...

...अब तक 700

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

700, यह संख्या है उन मिसिंग केसों की, जिन्हें मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेश पांडेय अब तक सुलझा चुके हैं। वैसे तो उनके बारे में इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आंकड़ा अपने आप में ही यह बताने के लिए काफी है कि राजेश अपने काम में कितने माहिर हैं, लेकिन उनके केस सुलझाने के तरीके इतने जबर्दस्त हैं कि उनकी तारीफ करते हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर उन्हें पांडेय मॉड्यूल का नाम दे चुके हैं। बीते दिनों वह तब चर्चा में आए, जब एक फिल्म निर्माता ने उन पर फिल्म बनाने का निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी।

यूं हुई शुरुआत: 2011 में 12 साल का एक बच्चा गुम हो गया था। राजेश ने उसकी तलाश कर उसे उसकी मां से मिलवाया। बेटे के मिलने पर उस मां के जो आंसू बहे वे राजेश के दिल को छू गए। तभी से उन्होंने गुमशुदा लोगों की तलाश को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

निराला है ढंग: राजेश पांडेय का गुमशुदा लोगों को तलाशने का ढंग बिल्कुल अलग है। वह कभी पुलिस की वर्दी में नहीं रहते और न ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। कभी बेस्ट की बसों में तो कभी लोकल ट्रेनों में, कभी सकरी गलियों में तो कभी किसी दूसरे राज्य में, वह अपने नेटवर्क की मदद से गुमशुदा लोगों की तलाश करते दिखते हैं। उनके नेटवर्क में दूसरे शहरों व अन्य राज्यों के पुलिसकर्मी से लेकर आम लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, वह टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिये ही उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व एक कारोबारी को खोज निकाला था। दरअसल, बिजनेस में नुकसान के चलते वह घर छोड़कर कहीं चले गए थे। परिवार वालों ने जब राजेश से संपर्क साधा तो एक सप्ताह में उन्होंने उस व्यापारी को गुजरात से तलाश लिया। ऐसे ही ढेरों सॉल्व केस उनके नाम दर्ज हैं, जिनमें उन्होंने बिछड़े हुए लोगों को अपनों से मिलवाया। इनमें एक हिंदी फिल्म स्टार की गुमशुदा बेटी का केस भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने गोवा से ढूंढ़ निकाला था।

'पांडेय मॉड्यूल' दिया नाम: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर दत्ता पडसलगिकर भी 52 वर्षीय राजेश पांडेय के काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित हैं। इस वजह से उन्होंने इसे 'पांडेय मॉड्यूल' नाम दिया है। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी जो गुमशुदगी के मामलों की जांच कर रहा हो, उसे राजेश के तरीके से मामले को सुलझाना चाहिए।

राजेश पांडेय फाइल

किसी के गुम होने का दर्द सिर्फ उसका परिवार और उसके करीबी ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल **राजेश पांडेय** ने ऐसे लोगों के दर्द को अपना बनाया और गुमशुदा लोगों की तलाश को अपनी जिंदगी का मिशन। बीते दिनों एक फिल्म निर्माता ने उनके जीवन पर फिल्म बनाने की अनुमति मांगी है...

कल्पनाएं अधूरी उम्मीदें कायम

उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीदों और अपेक्षाओं को लेकर आने वाला साल 2020 कई चीजों का आधार बना रहा। इन्सानी जीवन को सहज, सरल करने वाली और मानवता के कल्याण की खातिर तमाम खोज, शोध और नई तकनीक को हासिल करने का यह साल मानदंड बना रहा। दुनिया ने कल्पना की थी कि साल 2020 तक हम शून्य ऊर्जा खपत वाले कंप्यूटर चिप्स, हाइपरलूप, सुपरफोन जैसी चीजें हासिल कर लेंगे। हमारे शोधकर्ता समय से जरूर पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। आज नहीं तो कल, वे सारी चीजें हमारे पास होंगी। आइए, उनकी वर्तमान स्थिति पर डालते हैं एक नजर:

फ्लाइंग कार तैनात करेगी उबर

उबर 2020 में फ्लाइंग कार प्रदर्शित करने की इच्छुक है, लेकिन यह तय है कि अगले साल ऐसा नहीं होने जा रहा। कंपनी इस पर काम कर रही है। इस वर्ष उबर ने फ्लाइंग गाड़ी को अपनी सेवा में शामिल किया, लेकिन वह अत्याधुनिक नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में यह हेलीकॉप्टर की सवारी करा रही है।

सबके हाथ में मोबाइल

2014 में एरिक्शन मोबिलिटी का अनुमान था कि 2020 तक धरती पर छह वर्ष से अधिक उम्र के 90 फीसद लोगों के पास मोबाइल होगा। विश्व बैंक के जुटाए आंकड़े के अनुसार पहली बार विश्व की जनसंख्या से अधिक मोबाइलधारक हैं। हालांकि मोबाइल के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों से भी दुनिया चिंतित हो चली है। अमेरिका सहित कई देशों में राष्ट्रीय अभियान चल रहा है जिसके तहत अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है कि वे बच्चों को आठवीं से पहले स्मार्टफोन न दें।

सात करोड़ का बिटक्वाइन

क्रिप्टोकरेंगी समुदाय में विशेष स्थान रखने वाले जॉन मैक्फी ने 2017 में भविष्यवाणी की थी कि 2020 के अंत तक एक बिटक्वाइन की कीमत एक मिलियन डॉलर (7, 14, 27, 500 रुपये) हो जाएगी। फिलहाल इसकी कीमत करीब 72 सौ डॉलर (5, 14, 278 रुपये) ही है जो उनके जादुई आंकड़े से काफी दूर है। हालांकि अपने दावे पर वे कायम हैं। उनका कहना है कि यदि वह गलत होते हैं तो अपने शरीर का अंदरूनी हिस्सा खा जाएंगे।

हाइपरलूप की होगी सवारी

2013 में एलन मस्क ने परिवहन के इस पांचवें स्वरूप की कल्पना की। इसमें उन्होंने आठ सौ मील प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्यूब के माध्यम से लोगों को यात्रा कराने की बात कही थी। मस्क से प्रेरित होकर कई टेक उद्यमी इस दिशा में आगे बढ़े। 2015 में एक प्रमुख स्टार्टअप कंपनी ने घोषणा की कि 2020 तक पहली 60 मील की दूरी लोग हाइपरलूप से तय करेंगे। वर्जिन हाइपरलूप वन का कैलीफोर्निया में 16 सौ फुट का टेस्ट ट्रैक है। मस्क की बोरिंग कंपनी लास वेगास में तथाकथित लूप सिस्टम बना रही है। इसमें करीब एक मील लंबा संकीर्ण सुरंग वाला ट्रैक है। इसपर 155 किमी की रफ्तार से टेस्ला कार दौड़ती है।

न्यूनतम ऊर्जा वाले कंप्यूटर चिप्स

2012 में इंटेल ने एक ऐसे सर्वव्यापी कंप्यूटिंग की भविष्यवाणी की जो 2020 तक लगभग शून्य ऊर्जा की खपत करेगा। वह समय लगभग आ भी चुका है, लेकिन फिलहाल अभी भी फोन को प्रतिदिन चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। टॉप कंप्यूटर चिप में गिने जाने वाले आइ 9 इंटेल को 165 वाट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह 65 इंच टेलीविजन का करीब दोगुना है।

खुद से चलने वाली कार

ऑटो और टेक कंपनियां आश्वस्त थीं कि कार चलाने में इंसान की तुलना में कंप्यूटर जल्द ही ज्यादा सक्षम होगा। वर्ष 2015 में टोयोटा मोटर कॉर्प ने कंपनी स्तर पर एक शर्त लगाई कि 2020 तक सड़क पर खुद से चलने वाली कार होंगी। लेकिन 2018 में एक पैदल यात्री की मौत सेल्फ ड्राइविंग उबर कार की चपेट में आने से हो गई। नए वर्ष में टोयोटा की लेक्सस ब्रांड एक ऐसी कार पेश करेगी जो खुद से चलने वाली कार होगी।

सरकारी बैंकों की हालत सुधरी

नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत में सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनपीए की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंक इसमें कमी लाने में सफल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर, 2019) के दौरान 13 सरकारी बैंकों ने मुनाफा दर्ज किया है। बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। (आइएएनएस)

इकोनॉमी की मजबूती के लिए केंद्र और राज्य का समन्वय बेहद जरूरी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोनों को मिलकर योजनाएं बनानी होंगी।

— डॉ. कौशिक बसु, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार

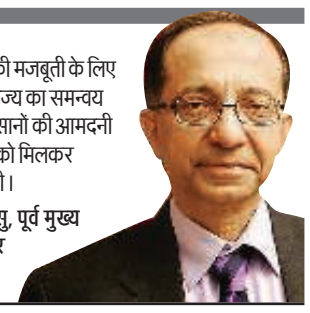

इंटरनेट बंदी से हर घंटे टेलीकॉम कंपनियों को ढाई करोड़ का चूना

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाने पड़े। मोबाइल पर अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने बहुत-सी जगहों पर इंटरनेट को बंद करवा दिया। इसने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

48.3
करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता (चीन के बाद दूसरा स्थान)

9.8
जीबी डाटा प्रति महीने प्रति व्यक्ति उपभोग (दुनिया में सबसे ज्यादा)

97
करोड़ इंटरनेट यूजर होंगे 2023 तक

बंद होने से बड़ी चपत

डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह एक्सेस नाउ के अनुसार भारतीय मोबाइल ऑपरेटरों को सीएए और एनआरसी को लेकर इंटरनेट बंद होने से प्रति घंटे 2 करोड़ 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए थे। शोध के मुताबिक जुलाई 2015 से जून 2016 के मध्य टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट बंद होने से करीब 96 करोड़ का नुकसान हुआ।

दुनिया में सबसे सस्ता डाटा

भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं को दुनिया में सबसे सस्ता डाटा मिलता है। कीमतों की तुलना करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक भारत में एक जीबी डाटा की कीमत 0.26 डॉलर यानी करीब 18.57 रुपये बैठती है। अमेरिका में एक जीबी डाटा की कीमत 12.37 डॉलर (883.56 रुपये) और ब्रिटेन में 6.66 डॉलर (475.71 रुपये) और वैश्विक औसत 8.53 डॉलर (609.28 रुपये) है।

हर मोबाइल में इंटरनेट

देश में छोटे बच्चों से बुजुर्गों तक हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल में है इंटरनेट। मोबाइल आज जरूरत बन चुका है, लेकिन असामाजिक तत्वों के चलते यही मोबाइल समाज के लिए अभिशाप भी बन जाता है। ऐसे लोग अफवाहों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते ही देखते यह अफवाहें जनमानस के दिमाग में रच-बस जाती हैं।

पाकिस्तान और सीरिया से आगे

देश में इंटरनेट बंद करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2016 से मई 2018 के मध्य भारत में सरकारी आदेश पर 154 बार इंटरनेट बंद हुआ। इस फेहरिस्त में पाकिस्तान, इरान, सीरिया, तुर्की जैसे देश भारत से बहुत पीछे हैं। वहीं 2012 से अब तक इंटरनेट के बंद होने के 374 मामले सामने आ चुके हैं। हालिया उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। जहां पर सीएए और एनआरसी के विरोध के कारण इंटरनेट बंद करना पड़ा। यहां तक की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया।

कानूनी पहलू

सरकारी स्तर पर इंटरनेट को बंद करने के लिए बाकायदा कानून मौजूद है। टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी ऑर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स 2017 के तहत अधिकारी टेलिकॉम कंपनियों को इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। हालांकि यह अधिकारी केंद्र या राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए।

रुपे, यूपीआइ से भुगतान पर एमडीआर शुल्क नहीं

तैयारी ▶ पहली जनवरी से कारोबारियों को मिलेगी सुविधा

विदेशी कंपनियों के पेमेंट गेटवे के मुकाबले ग्राहक इन घरेलू पेमेंट साधनों को दे रहे प्राथमिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रुपे कार्ड और यूपीआइ प्लेटफॉर्म के जरिये होने वाले भुगतान को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क से मुक्त रखने का एलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली जनवरी से ऐसे सभी भुगतानों पर एमडीआर शुल्क लागू नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जल्द रुपे और यूपीआइ को डिजिटल पेमेंट के निर्धारित साधनों की सूची में शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर देगा। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद बताया कि डिजिटल पेमेंट के ऐसे सभी निर्धारित साधनों के तहत एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का सालाना राजस्व हासिल करने वाली सभी कंपनियों को रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ क्यूआर कोड के जरिये ग्राहकों से पेमेंट लेने की सुविधा राजस्व विभाग उपलब्ध कराएगा। एमडीआर के तहत प्रत्येक मर्चेंट या दुकानदार को डिजिटल भुगतान लेने पर बैंक को शुल्क अदा करना होता है। यह लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के आधार पर तय होता है। सीतारमण ने कहा 'बैंकों और डिजिटल पेमेंट से जुड़े सभी पक्षों के साथ हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बजट में हुई घोषणा लागू हो रही है।'

प्रतीकात्मक

गौरतलब है कि भुगतान के मामले में देश में ही विकसित रुपे और भीम यूपीआइ जैसे डिजिटल पेमेंट के साधन विदेशी कंपनियों के पेमेंट गेटवे से आगे निकल रहे हैं। वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश बजट में भीम यूपीआइ, यूपीआइ क्यूआर कोड, आधार पे, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे पेमेंट साधनों को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए इनके जरिये होने वाले लेनदेन को एमडीआर से छूट दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि एमडीआर शुल्क में छूट का बोझ आरबीआइ और बैंक मिलकर वहन करेंगे। साथ ही अब सभी सरकारी बैंक रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाएंगे। इससे देश में डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सरकार पहले ही इनकम टैक्स एक्ट और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 में अपेक्षित बदलाव कर चुकी है।

ग्रामीण गरीबी और आर्थिक मंदी भारत की बड़ी चुनौतियां

रायपुर, नईदुनिया : भारत में ग्रामीण गरीबी और आर्थिक मंदी बड़ी चुनौती है। हालांकि यह मंदी ग्लोबल है। इसके बावजूद आर्थिक विकास दर में कमी चिंता का विषय है। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. कौशिक बसु ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत रह गई है। ऐसी स्थिति में कर्ज मांग घटने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास कर्ज देने के लिए पूंजी घट जाती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कर्ज की मांग और आपूर्ति दोनों होने जरूरी हैं। इस मंदी से लड़ने के लिए लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ानी होगी।

यूपीए सरकार के दौरान मुख्य अर्थशास्त्री रहे डॉ. बसु ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को योजना बनाकर काम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और एक-दूसरे को सहयोग जरूरी है। कृषि से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदेश के किसानों को सब्सिडी या बोनस आदि देने की नीतियों के लिए केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी। देश की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे खनिज सम्पन्न राज्यों की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेतीबाड़ी से लेकर कोयला समेत कई तरह के खनिज हैं। देश की आर्थिक तरक्की के लिए ऐसे राज्यों को बढ़ावा देकर व देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव करके बेहतर किया जा सकता है।

फार्मा सेग्मेंट बन रहा हेल्थकेयर सेक्टर के लिए संजीवनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश का हेल्थकेयर सेक्टर तमाम बाधाओं के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके विकास में फार्मा सेग्मेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खर्च में इजाफा, पहुंच में सुधार और बढ़ते निर्यात की वजह से सेक्टर में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि लागत और मूल्य में वृद्धि की बाधाओं को पार करते हुए हेल्थकेयर सेक्टर आने वाले वर्ष में भी बढ़त की ओर अग्रसर दिखता है।

दवा कारोबारियों के संगठन इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस (आइपीए) के मुताबिक सेक्टर में अगली तेज वृद्धि निर्यात में इजाफे के माध्यम से आएगी। आइपीए का कहना है कि चीन, जापान, अफ्रीका, इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका के दवा बाजार हमारे निर्यात में अहम भूमिका निभाएंगे। यह ऐसे बाजार हैं, जिनमें भारत पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। निर्यात में वृद्धि के चलते मात्रा के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्यातक देश बन सकता है। जानकारों का मानना है दो मुख्य वजहों से अगले वर्ष फार्मा सेक्टर में दोहरे अंकों की विकास दर दिख सकती है। इनमें देश में दवा की पहुंच सुनिश्चित करना और नया बाजार तलाशना प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिका को होने वाला निर्यात बरकरार रखकर भी निर्यात विकास दर को गति दी जा सकती है। हालांकि फार्मा सेक्टर इस समय कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इनमें लागत में इजाफा, अमेरिका जैसे बाजारों में नियामक कड़ाई, बाजारों में कीमत नियंत्रण और भारत में जेनरिक दवाओं की अनिवार्यता जैसी चीजें शामिल हैं।

आइपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विकास के पथ पर है। हमें नीतिगत सुधारों के जरिये इसे विकास का पूरा मौका देना चाहिए। रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा है कि यह सेक्टर अगले कुछ वर्षों में 10-12 परसेंट की ग्रोथ रेट से विकास करेगी। सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से सेक्टर की उम्मीदें बढ़ी हैं। इसके माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंध करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने वाले मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी है और ग्लोबल स्तर पर मरीजों की आवक बढ़ाने की कोशिशें भी की जा रही हैं।

- विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हेल्थ सेक्टर कर रहा है बेहतर प्रदर्शन
- सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सेक्टर की ग्रोथ में मददगार

प्रतीकात्मक

सेक्टर में हैं अपार संभावनाएं

- आगामी वर्षों में सेक्टर द्वारा 10-12 परसेंट की गति वृद्धि करने की उम्मीद
- आयुष्मान भारत की मदद अगले दशक में 14 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ने की उम्मीद
- पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में मददगार होगा सेक्टर
- सेक्टर में मजबूती से बढ़ेगा स्वास्थ्य पर्यटन

न्यूज गैलरी

सांख्यिकी मंत्रालय ने गठित की 28 सदस्यीय समिति

नई दिल्ली : सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 28 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व वीफ स्टैटिस्टीशियन प्रणब सेन करेंगे। समिति गठन के बारे में जानकारी देते हुए सेन ने बताया कि इसकी पहली बैठक छह जनवरी को आयोजित होनी है। उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा काफी व्यापक हो सकता है, इस बारे में ज्यादा जानकारी बैठक में ही सामने आएगी। हालांकि सेन समिति के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। (प्रेट्र)

फेसबुक की क्रिप्टोकरेंसी योजना विफल : स्विट्जरलैंड

लंदन: स्विट्जरलैंड ने कहा है कि फेसबुक द्वारा प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी योजना वर्तमान रूप में विफल हो चुकी है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति युलरिक यूली मॉरर ने कहा कि अगर फेसबुक क्रिप्टोकरेंसी के विचार को साकार रूप देना चाहती है, तो उसे इसके स्वरूप में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक की प्रस्तावित योजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि अग्रणी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने लिब्रा नाम से क्रिप्टोकरेंसी लाने की योजना पेश की थी। लेकिन की यह योजना खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। (आइएएनएस)

निर्यात में गिरावट पर अगले वर्ष ब्रेक लगने की पूरी उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्यात में गिरावट पर अगले वर्ष ब्रेक लगने की उम्मीद है। हालांकि संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते निर्यात में होने वाली वृद्धि सीमित रहने की संभावना है। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा कि वर्तमान में निर्यात में आ रही गिरावट की मुख्य वजह पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी है। यह भारत के कुल निर्यात में 13.42 परसेंट की हिस्सेदारी रखते हैं।

वाणिज्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ड्रग, फार्मा और केमिकल्स जैसे उत्पाद आने वाले वर्षों के दौरान निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वर्ष अगस्त के बाद से निर्यात में लगातार गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और ज्वैलरी उत्पादों के निर्यात में गिरावट रही है। इस दौरान श्रम-आधारित सेक्टर जैसे कारपेट, रेडीमेड गारमेंट्स, हथकरघा और चमड़े के उत्पादों का निर्यात भी घटा है।

पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल ग्रोथ में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने इस वर्ष ग्लोबल ट्रेड में 1.2 परसेंट की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। इससे पहले अप्रैल में इसने 2.6 परसेंट की ग्लोबल ग्रोथ की बात कही थी। हालांकि अगले वर्ष यह 2.7 परसेंट रहने की उम्मीद जताई गई है। देश की सर्वोच्च निर्यात संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) के मुताबिक वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे व्यापार के विपरीत स्थितियां पैदा हुई हैं। संरक्षणवाद की बढ़ती नीति ग्लोबल ट्रेड के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रुप में उभरी है। हालांकि संगठन ने अगले वर्ष सुधार की उम्मीद जताई है। फियो के महानिदेशक अजय साही ने कहा कि अगले वर्ष ग्लोबल ट्रेड में सुधार होगा।

प्रतीकात्मक

- वाणिज्य सचिव ने विकास दर बढ़ने की जताई उम्मीद, संरक्षणवाद को ग्लोबल ट्रेड के लिए बताया खतरा

साही के मुताबिक अगले वर्ष ग्लोबल स्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो निर्यात में 15 परसेंट तक की ग्रोथ संभव है। आने वाले समय में ग्रोथ नकारात्मक जोन से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसमें दोहरे अंकों की वृद्धि मुश्किल है। मौजूदा निर्यात दर के हिसाब से इस वर्ष कुल निर्यात 34,000 करोड़ डॉलर तक (करीब 23.8 लाख करोड़ रुपये) मूल्य के बराबर रहने की संभावना है।

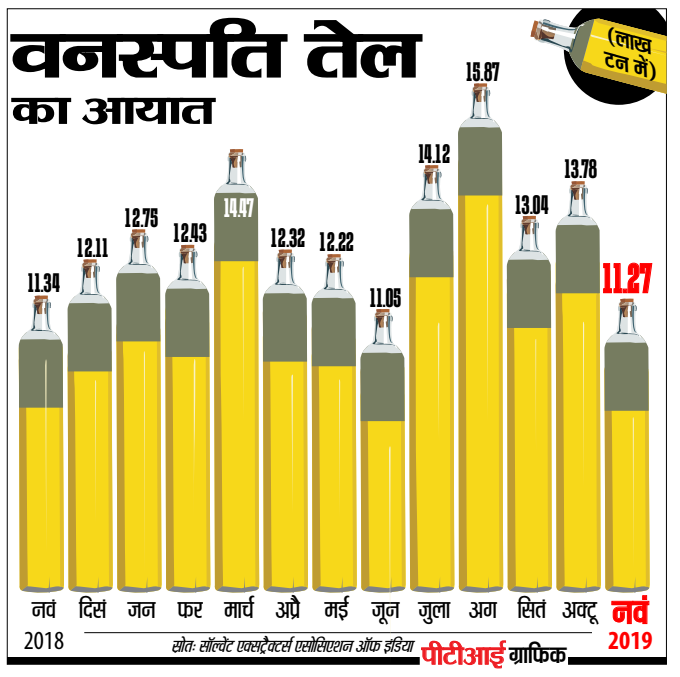

मंदी नहीं, सुस्त है इकोनॉमी : रामगोपाल अग्रवाल

कोलकाता, प्रेट्र : नीति आयोग के फेलो रामगोपाल अग्रवाल ने कहा है कि इकोनॉमी संकट से गुजर रही है। लेकिन मंदी जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जैसे सुधारों की जरूरत थी। लेकिन इन्हें लागू करने में जल्दबाजी हुई। इस दौरान अग्रवाल ने नोटबंदी को नोटबदली बताते हुए कहा कि नोटबंदी शब्द का प्रयोग करना गलत है। सरकार द्वारा नोटबंदी नहीं बल्कि नोटबदली का कदम उठाया गया था।

जीएसटी और आइबीसी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन जरूरी और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों से पहले पर्याप्त तैयारी की जरूरत थी। अग्रवाल ने कहा कि बेहतर विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी होना जरूरी है। सभी जाति और समुदायों को साथ आना होगा और लैंगिक समानता को भी सुनिश्चित करना होगा। इकोनॉमी के लिए पांच लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य पर अग्रवाल बोले कि ऐसा लक्ष्य बुरा नहीं है। लेकिन सरकार को मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने के उपाय भी करने होंगे।

बीएसएनएल-एमटीएनएल के लिए बना जीओएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जीओएम में राजनाथ सिंह, रवि शंकर प्रसाद, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान शामिल

दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनियों बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के 69 हजार करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार ने मंत्रिसमूह का गठन किया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य व उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा तेल, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।

उच्चस्तरीय मंत्रिसमूह (जीओएम) हाल में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के पुनरुद्धार को लेकर लिए गए निर्णयों को तेजी से लागू करेगा। सूत्रों के मुताबिक पुनरुद्धार पैकेज में दोनो कंपनियों की व्यावसायिक सक्षमता का आकलन करने, वीआरएस के जरिये कर्मचारियों की संख्या सीमित करने, बांड जारी करने, परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण तथा बीएसएनएल को 4-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। जीओएम को इन सभी पर चर्चा करके निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने इसी वर्ष अक्टूबर में बीएसएनएल में एमटीएनएल के विलय के लिए 69 हजार करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दोनो सरकारी कंपनियों ने अपने यहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को लागू कर दिया है। जिसके तहत लगभग 92,700 कर्मचारियों ने वीआरएस लेने के लिए आवेदन किया है। इससे कर्ज में डूबी दोनो कंपनियों के वेतन बिल में सालाना 8,800 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। इसके अलावा दोनो कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों में तकरीबन 37,500 करोड़ रुपये प्राप्त होने के आसार हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल को पिछले नौ वर्षों से घाटा हो रहा है। एमटीएनएल केवल मुंबई और दिल्ली में सेवाएं देती है। जबकि बीएसएनएल बाकी हिस्सों में संचार सेवाएं प्रदान करती है। इससे पहले दोनों कंपनियों के विनिवेश की चर्चा हो रही थी। लेकिन सरकार ने रक्षा क्षेत्र की जरूरतों और निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल के रूप में एक सरकारी कंपनी को बनाए रखना जरूरी समझा है।

निवेशक के रूप में अगर अंधेरे में तीर चला रहे हैं तो रुकिए...

'फ्लाइंग ब्लाइंड' अंग्रेजी में एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर वास्तव में उड़ने की बात करें तो हवाई जहाज में कई सारे उपकरण होते हैं जो उड़ान में पायलट की मदद करते हैं, भले ही बाहर से कुछ भी न दिख रहा हो। निवेशक के पास ऐसे उपकरण नहीं होते हैं। या शायद होते हैं। लेकिन ज्यादातर निवेशकों के पास ऐसे उपकरण नहीं होते हैं जो निवेश में उनकी मदद और बारीकियों से अवगत कराएं। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरी बात ऐसे निवेशकों से होती रहती है जिनको बचत और निवेश की थोड़ी समझ होती है। ऐसे ही कुछ निवेशकों से बात करते हुए मुझ अक्सर चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। कई बार मुझे झटका भी लगता है।

हाल में एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए। वे 50 की उम्र पार कर चुके हैं। तमाम लोगों की तरह उनका कैरियर भी पटरी से उतर रहा है और अब वे पहले से कम कमा रहे हैं। वे अब जल्द ही रिटायर होना चाहते हैं। उन्होंने टैक्स बचाने वाले विकल्पों में निवेश करते हुए कुछ रकम बचाई है। ज्यादातर रकम पीपीएफ में है। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया है। यह निवेश उन्होंने एजेंटों की सलाह पर किया है। हाल में उन्होंने एनपीएस में भी निवेश शुरू किया है। कुल मिलाकर पीपीएफ और एनपीएस के अलावा उन्होंने लगभग 70 फंडों में निवेश किया है। निवेश करने के लिहाज से 70 म्यूचुअल फंड्स बहुत अधिक हैं। यह जानकर किसी को भी झटका लग सकता है। लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है। अक्सर जो लोग एजेंट या सेल्सपर्सन की सलाह पर निवेश करते हैं वे बहुत सारे फंड खरीद लेते हैं। शुरुआती वर्षों में एजेंटों को फंड बेचने पर बड़ी रकम कमीशन के तौर पर मिलती है। हालांकि बाद में यह रकम कम होती जाती है। ऐसे में एजेंट अक्सर निवेशकों को नए नए फंड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ऐसा वे डायवर्सिफिकेशन या फंड्स के विविधीकरण के नाम पर करते थे।

धीरेंद्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

अगर कोई अंधेरे में भी लगातार तीर चलाता रहे, तो कोई न कोई तीर सही निशाने पर लग जाने की संभावना रहती ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंधेरे में तीर चलाना सही रणनीति है। निवेश के साथ ज्यादातर मामलों में यही हो रहा है। निवेशक अक्सर निवेश सलाहकारों के कहने पर ज्यादा से ज्यादा फंड्स में निवेश करते रहते हैं। दिलचस्प यह है कि ऐसा उनसे फंड डायवर्सिफिकेशन के नाम पर कराया जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि निवेश का तीर अपने निशाने पर लग रहा है या नहीं।

निवेशक सोचता है कि डायवर्सिफिकेशन हासिल करने का एक ही तरीका है - ज्यादा से ज्यादा फंडों में निवेश। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा फंडों में निवेश करने से आपको एक सीमा के आगे कोई अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन नही मिलता है।

म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई निवेश नहीं है। यह शेयर में निवेश करने का एक जरिया है। जैसे इक्विटी में फंड के जरिये आप शेयरों में निवेश करते हैं। एक सीमा से अधिक डायवर्सिफिकेशन इसलिए खराब है क्योंकि एक तरह के फंड अक्सर एक ही तरह के शेयरों में निवेश करते हैं। पांच या छह से अधिक फंडों में निवेश करने पर आप ऐसे शेयरों में निवेश कर रहे होते हैं, जो काफी हद तक उन्हीं शेयरों की तरह होते हैं जो आपके पास पहले से हैं।

मेरे दोस्त के पास 70 फंडों पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं था। उनको इन फंडों के रिटर्न के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे कहने पर उन्होंने अपना सारा निवेश 'माय इन्वेस्टमेंट्स ट्रैकिंग' सिस्टम में डाला। इसी तरह से एनपीए और पीपीएफ के निवेश से हासिल रिटर्न को समझना भी आसान था। अब वे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। अब कुल मिलाकर उनका निवेश लगभग 75 लाख रुपये का है। इसमें से लगभग आधा पीपीएफ में और तीन लाख रुपये एनपीएस में था। बाकी निवेश 75 फंडों में था। हालांकि ऐसा करने में वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के टूलसेट ने भी उनकी काफी मदद की। इससे उनको न सिर्फ यह जानकारी मिली कि कौन सा फंड बेचना चाहिए बल्कि यह भी पता चला कि फंड बेचने पर कितना टैक्स लगेगा। वैल्यू रिसर्च के टूल से उनको यह भी पता चला कि एफडी, इक्विटी या दूसरे विकल्पों में निवेश करने पर उनको कितना अच्छा या खराब रिटर्न मिल सकता था।

किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आजकल 75 लाख रुपये की रिटायरमेंट संपत्ति काफी नहीं है। मेरे दोस्त का काम इससे चल जाएगा क्योंकि उनको विरासत में कुछ प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन अगर उन्होंने एक दशक पहले निवेश के मामले में अंधेरे में तीर चलाना बंद कर दिया होता तो आज वे बहुत बेहतर स्थिति में होते। ज्यादातर निवेशक इसी तरह की गलतफहमी में रहते हैं। आजकल निवेश के मामलों में गाइड करने वाले बहुत से टूल ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में अब यह बहाना भी नहीं चलेगा कि मुझे तो निवेश के बारे में जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी।

25 अगस्त 2017 को भयंकर रूप ले लिया था लंबे समय से चले आ रहे रोहिंग्या संकट ने, जब म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी। इसे उसने रखाइन प्रांत में सफाया अभियान का नाम दिया था।

बम धमाके से दहला सोमालिया, 90 लोगों की मौत

मोगादिशू, एजेंसियां : सोमालिया की राजधानी मोगादिशू शनिवार को भीषण बम धमाके से दहल गई। एक व्यस्त सुरक्षा जांच चौकी के पास विस्फोटकों से लदी कार से किए गए धमाके में तुर्की के दो नागरिकों समेत 90 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। उनकी बस भी धमाके की चपेट में आ गई थी। हमले की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

सोमालियाई सरकार के प्रवक्ता इस्माइल मुख्तार ने बताया कि यह मोगादिशू में हुए भीषण बम धमाकों में एक है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हमले में 90 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी दी। सोमालिया के एक सांसद ने भी ट्वीट में बताया कि 17 पुलिस अधिकारियों समेत 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जबकि कैप्टन मुहम्मद हुसैन ने कहा कि सुबह के व्यस्त समय के दौरान एक टैक्स संग्रह सेंटर को निशाना बनाया गया। धमाके के दौरान घटनास्थल के समीप मौजूद रहे सकारिया अब्दुल कादिर ने बताया, 'विस्फोट के चलते मेरी कार के शीशे टूट गए। मैंने चारों ओर जमीन पर लोगों को खून से लथपथ पड़े देखा।'

- राजधानी मोगादिशू में जांच चौकी के पास विस्फोटकों से लदी कार से किया गया धमाका
- मृतकों में ज्यादातर यूनिवर्सिटी के छात्र, तुर्की के दो नागरिकों की भी मौत

मोगादिशू में अक्सर होते हैं बम धमाके

मोगादिशू में आए दिन कार बम धमाके और आतंकी हमले होते रहते हैं। अलकायदा से जुड़ा आतंकी संगठन अल-शबाब इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहता है। 2011 में इस आतंकी संगठन को मोगादिशू से खदेड़ दिया गया था। इस आतंकी संगठन का मध्य और दक्षिणी सोमालिया पर अब भी नियंत्रण है। इस अफ्रीकी देश में अल-शबाब के आतंकियों की संख्या नौ हजार के करीब होने का अनुमान है।

सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में शनिवार को कार बम विस्फोट के बाद राहत-बचाव कार्य में जुटे आपातकालीन सेवा कर्मी। रायटर

होटल को भी बनाया था निशाना

अल-शबाब के आतंकियों ने दो हफ्ते पहले मोगादिशू के एक होटल को भी निशाना बनाया था। इसमें पांच लोग मारे गए थे। यह होटल नेताओं, सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों में खासा लोकप्रिय बताया जाता है।

2017 में हुआ था सबसे भीषण हमला

अक्टूबर 2107 में मोगादिशू में सोमालिया के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। विस्फोटकों से भरे ट्रक से किए गए धमाके में 512 लोगों की मौत हुई थी और 295 घायल हुए थे।

शांति समझौते के करीब अमेरिका और तालिबान

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में गत 18 वर्षों से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में अमेरिका और तालिबान शांति समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख का जल्द एलान हो सकता है। यह करार होने के बाद अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत होगी।

टोलो न्यूज ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि दोनों पक्ष अगले दौर की बातचीत में समझौते पर हस्ताक्षर और अंतर अफगान वार्ता के लिए समय सीमा तय करेंगे। इसके पहले यह खबर आई थी कि तालिबान के ज्यादातर आतंकियों ने अफगानिस्तान में अस्थायी संघर्ष विराम करने के पक्ष में सहमति दी है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला तालिबान के सरगना मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा को लेना है।

इस बीच तालिबान के पूर्व कमांडर सैयद अकबर आगा ने कहा, 'संघर्ष विराम का दो हिस्सा होगा। संघर्ष विराम के पहले हिस्से का एलान अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर से पहले किया जाएगा। जबकि अफगान और विदेशियों के साथ करार होने के बाद दूसरे भाग की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि संघर्ष विराम के पहले भाग को लेकर तालिबान सहमत नहीं है।' जबकि काबुल में पाकिस्तान के राजदूत जाहिद नसरुल्ला खान ने कहा, 'मेरे मुल्क को उम्मीद है कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होने से संघर्ष विराम और अंतर अफगान वार्ता की राह प्रशस्त होगी।'

- करार पर हस्ताक्षर की तारीख का जल्द हो सकता है एलान

अहम पड़ाव की ओर वार्ता

अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने गत 19 दिसंबर को बताया था, 'तालिबान के साथ शांति वार्ता अहम पड़ाव पर पहुंच रही है।' कतर में तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता में खलीलजाद अमेरिकी पक्ष की अगुआई कर रहे हैं।

ट्रंप ने बहाल की थी बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत सितंबर में तालिबान के साथ शांति वार्ता रद कर दी थी। दोनों पक्ष तब समझौते के करीब थे। अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले साल दिसंबर से दोहा में शांति वार्ता चल रही थी। लेकिन तालिबान की ओर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के एक-एक नागरिकों की रिहाई के बाद गत नवंबर में शांति वार्ता दोबारा पटरी पर आई। ट्रंप ने दोबारा बातचीत होने की जानकारी दी थी।

न्यूज गैलरी

दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सवार छह लोगों के शव मिले

होनोलूलू : अमेरिकी प्रांत हवाई के काउई द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सवार छह लोगों के शव मिल गए हैं। हादसे में किसी के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर में मौजूद एक व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चल सका है। मौसम ठीक होने पर उसकी तलाश फिर से की जाएगी। तटरक्षक बल की ओर से बताया गया कि हेलीकॉप्टर में दो परिवारों के छह लोग और पायलट था। हेलीकॉप्टर को गुरुवार शाम काउई द्वीप से लौट आना था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर इसकी खोजबीन शुरू हुई। तटरक्षक बल के अधिकारियों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर कंपनी (सफारी हेलीकॉप्टर्स) ने उनसे गुरुवार शाम छह बजे संपर्क किया। कम दृश्यता और बारिश के चलते खोजबीन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। (एपी)

चीन ने भारत-पाक से तनाव कम करने का किया आग्रह

बीजिंग : चीन ने भारत व पाकिस्तान से तनाव कम करने और आपसी बातचीत के जरिये विवादों को खत्म करने का आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया से कहा, 'पड़ोसी होने के नाते हमने भारत व पाकिस्तान से तनाव कम करने और ऐसी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता हो। हमने दोनों देशों से क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व के लिए आपसी बातचीत के जरिये विवादों को सुलझाने की भी अपील की है।' उल्लेखनीय है कि इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाक में स्थित जैश ए मुहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया था। (एएनआइ)

इराक के सैन्य अड्डे पर हमले में अमेरिकी ठेकेदार की मौत

वाशिंगटन: उत्तरी इराक के किरकुक शहर स्थित इराकी सैन्य अड्डे पर किए गए रॉकेट हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई। हमले में अमेरिका के कई कर्मचारी और इराकी सैन्य कर्मी भी घायल हुए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही गठबंधन सेना ने एक बयान में कहा कि इस पूरे मामले की जांच इराकी सुरक्षा बल करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हमले में अमेरिकी कर्मचारियों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस हमले के पीछे ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठन हिजबुल्ला का हाथ मान रहा है। (रायटर)

पाकिस्तानी सेना लड़ेगी मुशर्रफ का केस

देशद्रोह मामला ▶ मौत की सजा के खिलाफ इमरान सरकार का करेगी इस्तेमाल

थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा

एम्सटर्डम, एएनआइ : पाकिस्तान में सेना का दबदबा जगजाहिर है। एक थिंक टैंक का तो यहा तक दावा है कि देशद्रोह मामले में विशेष अदालत से मौत की सजा पाए पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का केस एक तरह से अब पाकिस्तानी सेना लड़ेगी। इसके लिए वह अपनी कठपुतली इमरान सरकार का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाई थी।

नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम स्थित यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (ईएफएसएएस) नामक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार, सेना के दबदबे वाले पाकिस्तान में कोर्ट के फैसले से सत्ता के संतुलन को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि मौजूदा हालात में तख्तापलट की आशंका नहीं है। क्योंकि सत्ता में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सेना की कठपुतली सरकार है। यह सरकार कह रही है कि वह सेना की कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ने की इच्छुक है। सेना को खुद कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के सियासी गलियारे में भी चर्चा है कि इमरान सरकार के जरिये मुशर्रफ का मामला यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।

अस्पताल में भर्ती पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ। फाइल

सेना मुख्यालय में हुई थी बैठक : विशेष अदालत के फैसले के बाद उसी दिन रावलपिंडी स्थित सेना के मुख्यालय में शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई थी। सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि विशेष अदालत के फैसले से काफी पीड़ा हुई।

जज को पद से हटाने की मांग : विशेष अदालत के बाद कानून मंत्री फरोग नसीम ने बताया था कि सरकार सर्वोच्च न्यायिक परिषद से जस्टिस वकार अहमद को हटाने की मांग करेगी। फैसला सुनाने वाली तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख वकार ने फैसले में लिखा कि अगर सजा दिए जाने से पहले ही मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिन तक फंदे से लटकाकर रखा जाए।

इस मामले में मिली सजा : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत ने मुशर्रफ को 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने, संविधान को निलंबित करने और जजों को हिरासत में रखने के आरोपों में सजा सुनाई थी। वह मृत्युदंड पाने वाले पाकिस्तान के पहले पूर्व सैन्य शासक हैं। वह 2016 से दुबई में रह रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश को आपातकाल में झोंकने के लिए 17 दिसंबर को मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था।

लाहौर हाई कोर्ट ने अर्जी लौटाई

समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, लाहौर हाई कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के चलते पूर्ण पीठ नहीं होने का हवाला देकर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की अर्जी लौटा दी है। मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में शुक्रवार को अर्जी दी थी। वकील अजहर सिद्दीकी ने मुशर्रफ की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें संघीय सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया था।

तालिबान के हमले में दस अफगान सैनिकों की मौत

बीते दिनों तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की भी मौत हो गई थी। फाइल/एपी

कंधार, एएफपी : अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सेना के एक ठिकाने पर तालिबान आतंकियों के हमले में दस सैनिकों की मौत हो गई। आतंकियों ने सैन्य अड्डे तक सुरंग खोदकर इस हमले को अंजाम दिया गया।

सेना के प्रवक्ता नवाब जादरान ने शनिवार को बताया कि प्रांत के अशांत सांगिन जिले में सेना के बेस तक सुरंग खोदी गई थी, लेकिन सैनिकों की कार्रवाई से पहले ही इसे उड़ा दिया दिया। हमले के समय बेस में 18 सैनिक तैनात थे। दस की मौत हो गई और चार घायल हो गए। बाकी चार सैनिकों ने बहादुरी के साथ तालिबान आतंकियों के हमले का सामना किया। तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिद ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। तालिबान आतंकियों ने गत मंगलवार को बल्ख प्रांत में सेना के एक बेस को निशाना बनाया था। इसमें सात सैनिकों की जान गई थी। ये हमले ऐसे समय किए गए, जब अमेरिका और तालिबान के बीच अहम शांति वार्ता निर्णायक दौर में है।

साइबर अपराध से जंग को रूस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित

संयुक्त राष्ट्र, एपी: साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने के रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। आपराधिक उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का बेजा इस्तेमाल रोकने को लेकर रूस द्वारा पेश इस प्रस्ताव के पक्ष में 79 जबकि विरोध में 60 वोट पड़े। इस दौरान 33 देश अनुपस्थिति रहे। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरे देशों की आपत्ति के बावजूद मंजूर इस प्रस्ताव के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दुनियाभर के साइबर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। अपने कामकाज की रूपरेखा तैयार करने के लिए अगस्त 2020 में इस समिति की बैठक होगी।

महासभा में वोटिंग से पहले अमेरिका की उप राजदूत चेरिथ नार्मन शैले ने कहा कि यह प्रस्ताव साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करेगा। इतना ही नहीं, यह साइबर अपराध से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को विफल करने का भी काम करेगा।

- अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के विरोध के बावजूद प्रस्ताव को मिली मंजूरी

प्रतीकात्मक

वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से फिनलैंड की प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह पहले से ही साइबर अपराध जैसे विषयों से निपट रहा है तो ऐसे में नई संधि की क्या जरूरत है? उधर, रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि नई समिति को साइबर अपराध पर अगले साल आने वाली विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को भी ध्यान में रखना होगा। रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि 2021 में नई संधि पर काम शुरू होगा।

हांगकांग में चीनी कारोबारियों के वापस जाने का नारा

हांगकांग, एपी : हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने अब चीनी कारोबारियों से चीन जाने के लिए कहा है। आंदोलनकारी आजादी की मांग भी कर रहे हैं, आंदोलन के दौरान चीनी बैंकों और प्रतिष्ठानों पर हमले भी कर रहे हैं।

शनिवार को शॉपिंग मॉल की ओर मार्च करते आंदोलनकारियों ने चीनी कारोबारियों वापस जाओ...के नारे लगाए। माना जा रहा है कि चीनी कारोबारियों के स्वामित्व वाले शॉपिंग सेंटर आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। इस तरह का बड़ा प्रदर्शन हांगकांग की सीमा के निकट शेउंग शुई में हुआ। इस दौरान आंदोलनकारियों और सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस के बीच भिड़ंत भी हुई। इस दौरान कितने लोग घायल हुए और गिरफ्तार किए गए, यह सूचना अभी सामने नहीं आई है। चीन के साथ प्रत्यर्पण समझौते के प्रस्ताव के विरोध के साथ जून में शुरू हुआ आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इसमें नए-नए मुद्दे शामिल होते जा रहे हैं।

छह महीने से ज्यादा के इस आंदोलन में लोकतंत्र की मांग के बाद अब आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। इसी के तहत चीनी प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं और अब चीनी कारोबारियों से वापस चीन जाने के लिए कहा जा रहा है। आंदोलनकारियों की पहली मांग मानते हुए हांगकांग की सरकार प्रत्यर्पण कानून बनाने का प्रस्ताव वापस ले चुकी है।

1997 में ब्रिटेन से चीन के कब्जे में आए हांगकांग को कुछ मामलों में स्वायत्तता हासिल है। यहां पर स्थानीय निकायों को जनता मतदान के जरिये चुनती है, जो जनसमस्याओं के निस्तारण का काम करती हैं।

- अलगाव की भावना से हो रहे चीनी बैंकों और प्रतिष्ठानों पर हमले
- पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत, कई लोग गिरफ्तार
- छह महीने से ज्यादा के इस आंदोलन में अब आजादी की मांग पकड़ रही है जोर

हांगकांग में शनिवार को एक शॉपिंग मॉल में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों (बैटन के साथ सादे कपड़े में) के बीच झड़प हुई। एएफपी

चिंताजनक

दुनिया की ऑस्ट्रेलिया सरकार से प्यारे जीव को बचाने की गुहार, न्यू साउथवेल्स इलाके के नजदीक तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है कोआला

जंगल की आग से हजारों कोआला के मरने की आशंका

पर्थ, एपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित जंगलों में लगी आग से हजारों कोआला के मारे जाने की आशंका है। कोआला पेड़ों पर रहने वाला नन्हे भालू सरीखा भूरे रंग का प्यारा सा स्तनधारी होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही पाया जाता है। दुनिया भर से कोआला को बचाने के लिए आवाजें उठ रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथवेल्स इलाके के नजदीक तटवर्ती क्षेत्र में करीब 28 हजार कोआला थे। लेकिन हाल के महीनों में वहां के जंगलों में लगी आग से उनकी संख्या काफी कम हो जाने की आशंका है। कोआला ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले जीवों में शुमार है लेकिन हाल के वर्षों में जंगलों के कटान और प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनकी संख्या में कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री सूसन ले के अनुसार हाल के दशकों में कोआला के रहने वाले जंगलों के क्षेत्रफल में 30 प्रतिशत तक की कमी हुई है।

जंगलों में लगी आग को बुझाने के इंतजाम किए गए हैं, जैसे ही इस कार्य में सफलता मिलेगी-वैसे ही कोआला की गिनती कराई जाएगी, उनके पुनर्वास के इंतजाम किए जाएंगे। हाल के दिनों में आग से बचाए गए कोआला के पानी पीते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ले ने बताया कि पूरी दुनिया को कोआला की चिंता है और उनके पास उनको सुरक्षित रखने के लिए बड़ी संख्या मेल और अन्य माध्यमों से संदेश आए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग से कोआला को बचाने के बाद उसे पानी पिलाता दमकल कर्मी। एपी

कम हो गई है पर्यटकों की संख्या: ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग ने सबसे अधिक प्रभाव यहां के वायुमंडल पर पड़ा है। पिछले कुछ दशकों तक दुनिया के पर्यटक इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करते थे, पर धुएं की वजह से पर्यटकों का यहां आना लगभग बंद-सा हो गया है। आग ने यहां काफी बड़े पैमाने को राख कर दिया है।

बेहतर कार्य के लिए 35 एनआरआइ को सम्मानित करेंगी ब्रिटेन की महारानी

लंदन, प्रेट्र : अपने कार्यों से ब्रिटेन की बेहतरी में योगदान देने वाले 35 अप्रवासी भारतीयों (एनआरआइ) को भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राजमहल में आयोजित समारोह में सम्मानित करेंगी। इन भारतीयों में कोरियोग्राफर शोभना जयसिंह, शिक्षाविद अदिति लाहिड़ी और अर्थव्यवस्था के लिए काम करने वाले उद्योगपति पॉल पवनदीप थांडी शामिल हैं।

जिन भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा उनमें तीन को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एंपायर (सीबीई), छह को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एंपायर (ओबीई), 16 को मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एंपायर (एमबीई) और 10 को ब्रिटिश एंपायर मेडल्स (बीईएम) दिया जाएगा। सीबीई से शोभना जयसिंह, अदिति लाहिड़ी और पॉल पवनदीप थांडी को सम्मानित किया गया है। जबकि बच्चों और परिवारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली रेणुका प्रियदर्शिनी डेंट, अल्पसंख्यकों के लिए सेवा के लिए अरुणदीप सिंह कांग को सम्मानित किया गया है।

पाक का चीन के सहयोग से बना लड़ाकू विमान उड़ने को तैयार

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान जेएफ-17 को शुक्रवार को सार्वजनिक किया। चीन के सहयोग से बना यह विमान दो सीटों वाला है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, इस विमान को रिकॉर्ड पांच महीने में तैयार किया गया है। यह जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होकर उसका मुख्य लड़ाकू विमान बनेगा।

पहली खेप में आठ दो सीटों वाले जेएफ-17 लड़ाकू विमान बनाए गए हैं। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (पीएसी) और चाइना नेशनल एयरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (सीएटीआइसी) मिलकर इस विमान का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले बने विमानों को सार्वजनिक करने के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद के निकट कामरा स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भव्य समारोह आयोजित किया गया।

- जेएफ-17 को रिकॉर्ड पांच महीने में तैयार किया : एयर चीफ मार्शल खान

इस समारोह में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल खान, चीनी राजदूत याओ जिंग और चीन के विमानन उद्योग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हाओ झाओपिंग शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने रिकॉर्ड समय में विमान का निर्माण पूरा करने के लिए दोनों देशों की निर्माण इकाइयों को बधाई दी। कहा, जेएफ-17 विमानों का निर्माण पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती का साक्षात प्रमाण है। चीनी राजदूत याओ ने कहा, जेएफ-17 विमान दोनों देशों की दोस्ती और आपसी सहयोग का उदाहरण है। वायुसेना के बयान में बताया गया है कि पीएसी और सीएटीआइसी ने व्यावसायिक विमान बनाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

मैं रेलवे के खिलाफ मुंबई की टीम की हार से बेहद निराश हूं। मुंबई टीम की चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
— विनोद कांबली, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

क्लाइव लॉयड को मिलेगी सर की उपाधि

लंदन, आइएएनएस : वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान क्लाइव लॉयड को इस खेल में उनके योगदान को देखते हुए नाइटहुड देने का फैसला किया गया है। इसके बाद अब वह सर क्लाइव लॉयड कहलाएंगे। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 75 साल के लॉयड को नाइटहुड दिए जाने की पुष्टि की। बोर्ड ने लिखा है कि वेस्टइंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड को बधाई।

गुवाहाटी को देश की खेल राजधानी बनने में जुटे सोनोवाल

अभिषेक त्रिपाठी, गुवाहाटी

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में असम की राज्य सरकार न सिर्फ इसका सफलतापूर्वक आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि इसे राज्य में एक खेल संस्कृति तैयार करने के रूप में भी देखा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य गुवाहाटी को देश की खेल राजधानी बनाने का है और इस लक्ष्य को पाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल पूरी तरह से जुट गए हैं।

मुख्यमंत्री सोनोवाल के साथ एक मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने असम के सभी पंचायतों के लिए विलेज ओलंपिक टैलेंट हंट नामक मुहिम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मुलाकात के दौरान सोनोवाल ने कहा, 'असम राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण के लिए 104 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह प्रतियोगिता युवा पीढ़ी को सशक्त बनाएगी और उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।'

लक्ष्य

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सफल बनाने में जुटे असम के मुख्यमंत्री
- गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेंगे एक लाख रुपये

राज्य सरकार ने असम में 500 खेल मैदान स्थापित करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को मंजूरी दी है। असम के एथलीटों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को एक लाख रुपये, रजत जीतने वालों को 75,000 रुपये और कांस्य जीतने वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। असम राज्य सरकार ने पहली बार राज्य में प्रतिभाओं की खोज के लिए खेल नीति पेश की है। यदि कोई एथलीट ओलंपिक में स्वर्ण जीतता है, तो उस खिलाड़ी को नकद पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे जबकि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले एथलीटों को 50 लाख रुपये मिलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए एक भागीदार के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण के पास कई जिम्मेदारियां हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से असम खेल चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने फैसला किया है कि 1000 एथलीटों को अपने खेल करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल। ट्विटर

सफल इतिहास : गुवाहाटी ने 2007 में राष्ट्रीय खेलों, 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों और 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। अधिकारियों को भरोसा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को गुवाहाटी में काफी सफलता मिलेगी।

बोनस अंक से चूकी दिल्ली

रणजी ट्रॉफी

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली ने हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच में जीत के लिए 84 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट गंवा दिए और बोनस अंक लेने से चूक गई। दिल्ली के अब तीन मैचों में सात अंक हैं और वह ग्रुप ए और बी की 18 टीमों में 12वें स्थान पर है। हैदराबाद तीन पराजयों के बाद 17वें स्थान पर है।

दिल्ली की दिक्कतें पंजाब के खिलाफ अगले मैच में बढ़ने वाली हैं क्योंकि शिखर धवन, नवदीप सैनी और इशांत शर्मा उसमें नहीं खेलेंगे। पंजाब दो जीत के बाद 17 अंक लेकर शीर्ष पर है। धवन और सैनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के कारण अगले मैच में नहीं होंगे जबकि इशांत कार्यभार प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। तेज गेंदबाज पवन सुयाल चोट के कारण बाहर होंगे। दिल्ली ने सुबह बिना किसी नुकसान के 24 रन से आगे खेलते हुए धवन (21), कुणाल चंदेला (छह) और नीतिश राणा (06) के विकेट गंवा दिए।

बंगाल ने आंध्र प्रदेश के साथ खेला ड्रॉ

कोलकाता, प्रेट्र : कोलकाता में बंगाल को ड्रॉ मैच में आंध्र प्रदेश पर पहली पारी के आधार पर तीन अंक से संतोष करना पड़ा। भोजनकाल के बाद सत्र में दोनों टीमों ने ड्रॉ पर सहमति जताई जब बंगाल ने 21 ओवर में बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए थे। मेजबान टीम को इस मैच में सीधे जीत दर्ज करने का मलाल रहेगा क्योंकि मैच के दौरान पहले तीन दिन बारिश और खराब रोशनी से कई व्यवधान पड़े। आंध्र के लिए सलामी बल्लेबाज सीआर ज्ञानेश्वर तारणहार रहे जिन्होंने तीसरे से चौथे दिन तक बल्लेबाजी की और नाबाद 74 रन बनाए। आंध्र प्रदेश की पहली पारी 181 रन पर ही सिमट गई। ज्ञानेश्वर की 239 रन की संयमित पारी से आंध्र की टीम फॉलोऑन खेलने से भी बच गई। बंगाल के लिए ईशान पोरेल ने 50 रन देकर चार विकेट और आकाशदीप ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए। बंगाल ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक रमन के इस सत्र में लगातार दूसरे शतक (112) की बदौलत पहली पारी में 289 रन बनाए थे।

यूपी ने सौराष्ट्र को हराया, पुजारा फ्लॉप

राजकोट, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश ने शनिवार को यहां ग्रुप बी मैच में सौराष्ट्र को पारी और 72 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा दूसरी पारी में बल्ले से विफल रहे। उत्तर प्रदेश ने सौराष्ट्र को पहली पारी में 331 रन पर समेट दिया और फिर मध्य क्रम बल्लेबाज मुहम्मद सैफ के 165 रन के बूते 523 रन का विशाल स्कोर बनाया। इससे उत्तर प्रदेश ने पहली पारी के आधार पर 192 रन की बढ़त हासिल कर ली। चौथे और अंतिम दिन जब खेल शुरू हुआ तो सौराष्ट्र को मैच बचाने और हार से बचने के लिए पिच पर रुककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी लेकिन उत्तर प्रदेश के कप्तान सौरभ कुमार ने अपने फिरकी के जादू से प्रतिद्वंद्वी टीम के छह बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे सौराष्ट्र की टीम 120 रन पर सिमट गई और उत्तर प्रदेश ने बोनस अंक भी हासिल किया। सौराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज हार्विक देसाई (50) और स्नेहल पटेल (19) ने पहले विकेट के लिए 38 रन की भागीदारी निभाई। जीशान अंसारी (03 विकेट) ने पटेल को आउट किया। पुजारा कई मौकों पर टीम को मुश्किल से निकालते रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ 10 गेंद ही खेल सके और सौरभ की गेंद पर आउट हुए।

उत्तराखंड को मिली शिकस्त

कटक, प्रेट्र : बसंत मोहंती और सूर्यकांत प्रधान की शानदार तेज गेंदबाजी के दम पर ओडिशा ने उत्तराखंड को ग्रुप सी के मैच में 10 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। यह ओडिशा की लगातार तीसरी जीत थी जिसमें उसने बोनस अंक हासिल किया। अब वह ग्रुप सी में 21 अंक लेकर शीर्ष पर है जबकि झारखंड उससे पांच अंक पीछे दूसरे स्थान पर है। मैन ऑफ द मैच शांतनु मिश्रा के 110 रन की मदद से ओडिशा ने पहली पारी में 117 रन की बढ़त हासिल की। चार विकेट पर 54 रन से आगे खेलते हुए उत्तराखंड की टीम 195 रन पर आउट हो गई। ओडिशा ने 63 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

रणजी ट्रॉफी के दौरान हैदराबाद के खिलाफ शॉट खेलने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज ध्रुव शौरी। प्रेट्र

एक नजर में

भारत में समस्या बताते हैं, समाधान नहीं : इशांत

नई दिल्ली : तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को भारतीय गेंदबाजी ईकाई का ध्वजवाहक बनने में 12 साल लग गए, लेकिन 96 टेस्ट मैच खेलने वाला यह खिलाड़ी बिना किसी शक के उस गेंदबाजी आक्रमण के नेतृत्वकर्ता का तमगा पाने का हकदार है, जिसने बीते कुछ वर्षों में भारत को खेल के लंबे प्रारूप में सफलता दिलाई है। इशांत इस समय रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद को मात देने में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद इशांत ने अपनी गेंदबाजी, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर बात की और साथ ही यह बताया कि ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी के साथ बिताए गए वक्त ने उन्हें किस तरह से मदद की। उन्होंने कहा, 'मेरे सफर में कई उतार-चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा हूं। मैं जहीर खान, कपिल देव से अपनी तुलना नहीं करता हूं। उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है।' (प्रेट्र)

अगली धौनी जल्दी नहीं मिलेगा : गांगुली

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को कहा कि महेंद्र सिंह धौनी ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं से जरूर बात की होगी। धौनी वनडे विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। गांगुली ने कहा, 'उन्होंने (धौनी) कप्तान से बात की है और मुझे यकीन है कि चयनकर्ताओं से भी बात की होगी। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करने के लिए यह कोई मंच है।' उन्होंने कहा कि धौनी जैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। 'यह धौनी का फैसला होगा कि वह क्या करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात नहीं की है, लेकिन वह भारतीय क्रिकेट के चैंपियन हैं।' (प्रेट्र)

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिलेगा खास सम्मान

लंदन : न्यूजीलैंड में जन्में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के साथ आइसीसी विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सदस्यों को ब्रिटेन के 'न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट' में जगह दी गई है। स्टोक्स ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की पारी खेल टीम को पहली बार विश्व विजेता बनाया था। इसके छह सप्ताह बाद उन्होंने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में नाबाद 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। स्टोक्स को 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एंपायर' के सम्मान के लिए चुना गया है। (एपी)

बॉक्सिंग डे टेस्ट 1 ▶ पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने मेहमानों को 148 रन पर किया ढेर

हार की कगार पर न्यूजीलैंड की टीम

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में हासिल की 456 रनों की बड़ी बढ़त

मेलबर्न, एएफपी : पैट कमिंस की अगुआई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग टेस्ट (दूसरा टेस्ट) मैच के तीसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी को 148 रन पर समेट कर 319 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 137 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 456 रन की कर ली। पहली पारी में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड 12 और मैथ्यू वेड 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी 467 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 44 रन से की। कमिंस ने पांच विकेट, जेम्स पैटिनसन ने तीन और मिशेल स्टार्क ने दो विकेट विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बड़ी बढ़त दिलाई। न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ टॉम लाथम ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना कर सके। उन्होंने 144 गेंद की पारी में 50 रन बनाए। वह अपना 16वां अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद कमिंस की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच थमा बैठे। विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज कमिंस ने 17 ओवर में 28 रन दिए। पहली पारी में 319 रन की बढ़त कायम करने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन ने न्यूजीलैंड को फॉलोऑन देने की जगह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहतर समझा। डेविड वार्नर (38) और रॉरी बर्न्स (35) ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। इस साझेदारी को नील वैगनर ने वार्नर को आउट कर तोड़ा। इसके बाद फॉर्म में चाल रहे मार्नस लाबुशाने 19 रन बनाकर रन आउट हो गए जबकि मिशेन सेंटनर ने बर्न्स को विकेट के पीछे कैच कराकर पवेलियन भेजा। वैगनर ने पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (07) को आउट कर टेस्ट क्रिकेट पर अपने 200 विकेट पूरे किए।

इससे पहले दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड ने कप्तान केन विलियमसन और टॉम ब्लंडेल का विकेट गंवाकर 44 रन बनाए थे। तीसरे दिन का खेल शुरू होते समय टॉम लाथम नौ और रॉस टेलर दो रन पर खेल रहे थे। भोजनकाल तक हालांकि टीम ने छह विकेट गंवा दिए जबकि स्कोर 102 रन था। कमिंस की तेज गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेबस नजर आए। टेलर (04) को उन्होंने स्लीप में कैच कराने के बाद अगली गेंद पर हेनरी निकोल्स को खाता खोलने से पहले ही एलबीडब्ल्यू कराया। विकेटकीपर बीजे वाटलिंग ने हालांकि उन्हें हैट्रिक पूरी नहीं करने दी। पैटिनसन ने इसके बाद वाटलिंग को बर्न्स के हाथों कैच कराकर न्यूजीलैंड के स्कोर को पांच विकेट पर 58 रन कर दिया।

बॉक्सिंग-डे टेस्ट के दौरान एमसीजी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोलस (बायें) को आउट करने के बाद जश्न मानते ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस। एपी

350 से ज्यादा के लक्ष्य का सफल पीछा अभी तक एमसीजी के मैदान पर किसी भी टीम ने नहीं किया है। इस मैदान पर सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा इंग्लैंड (332) ने जनवरी 1929 में किया था

05 विकेट ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लिए। उनके लिए यह वर्ष शानदार रहा है। उन्होंने इस वर्ष 99 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए और आइपीएल में बड़ा करार मिला

लाथम ने हालांकि लंबे समय तक एक छोर संभाले रखा और जब वह आउट हुए तो टीम को स्कोर सात विकेट पर 112 रन था। न्यूजीलैंड की टीम पर्थ में पहला मैच 296 रन से हार गई थी।

ट्रेंट बोल्ट के हाथ में फ्रैक्चर, तीसरे टेस्ट से बाहर : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के हाथ में शनिवार को फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। यह न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इस हाथ से वह गेंदबाजी नहीं करते। इस अनुभवी खिलाड़ी ने हाल में चोट से वापसी की थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मेहमान टीम की पहली पारी के अंत में पेसर मिशेल स्टार्क की बाउंसर गेंद उनके दस्ताने पर लगी।

द. अफ्रीका ने बनाई इंग्लैंड पर बढ़त

बॉक्सिंग-डे टेस्ट-2

- दुसेन का अर्धशतक, नोर्त्जे के साथ मिलकर इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसाया
- भोजनकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए सात विकेट पर 197 रन

सेंचुरियन, एएफपी : रेसे वान डेर डुसेन और एनरिक नोर्त्जे ने मैच की सबसे बड़ी साझेदारी करके यहां इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को तीसरे दिन भोजनकाल तक 300 के पार पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने सात विकेट पर 197 रन बना लिए हैं।

एक समय दक्षिण अफ्रीका की टीम 62 रनों पर चार विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद डुसेन ने 51 और नोर्त्जे ने 40 रन बनाकर पांचवें विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी कर डाली और इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसा दिया।

मेहमान टीम का इंतजार पहली पारी के शीर्ष स्कोरर क्विंटन डिकॉक ने भी बढ़ाया, जिन्होंने 17 गेंद में 30 रन बना लिए। हालांकि इससे पहले मेहमान टीम के गेंदबाजों ने तीन विकेट निकालकर थोड़ी राहत की सांस ली, जिसमें दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज डुसेन, नोर्त्जे के विकेट और ड्वेन प्रिटोरियस का विकेट शामिल था। दो विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिए।

वहीं, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 40 मिनट तक बीमारी की वजह से मैदान से बाहर रहे। इसके बाद वह लौटे, लेकिन भोजनकाल से पहले फिर पवेलियन लौट गए। इससे पहले, नोर्त्जे सैम कुर्रन की गेंद पर आठ रन पर कैच आउट हो गए थे, लेकिन रिव्यू में आया कि गेंद उनके कंधे से लगकर जॉनी बेयरस्टो के पास पहुंची। नोर्त्जे ने कई छोटी गेंद का शानदार ढंग से सामना किया। ब्रॉड की एक गेंद उनकी कलाई से भी लगी, इसके बाद उन्होंने मैदान पर ही अपना इलाज कराया। दूसरी ओर डुसेन ने साहसिक पारी खेली। आर्चर की गेंद पर आउट होने से पहले वह लगातार दो बार रन आउट होने से बचे। उन्होंने 67 गेंद में पांच चौके लगाए। इसके अलावा नोर्त्जे भी आर्चर के अगले ओवर में चलते बने। उन्होंने 89 गेंद का सामना करते हुए 127 मिनट तक क्रीज पर बिताया।

मार्करैम फ्रैक्चर के कारण सीरीज से बाहर

सेंचुरियन : दक्षिण अफ्रीका के सलामी बलेबाज एडेन मार्करैम इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर खेले जा रहे पहले टेस्ट में बायें हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर हुआ है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने कहा कि यह चोट उन्हें पहले मैच के दूसरे दिन लगी, जिसे ठीक होने के लिए सर्जरी की जरूरत होगी। इसी कारण वह छह सप्ताह तक खेल से दूर रहेंगे। सीएसए के चीफ मेडिकल ऑफिसर शुएब मांजरा ने कहा कि एडेन को बायें हाथ की अनामिका अंगुली में चोट लगी जिससे उनकी अंगुली फ्रैक्चर हो गई।

सरकार और पीसीबी से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला : कनेरिया

विवाद

- पूर्व क्रिकेटर ने कहा, मुझ पर प्रतिबंध लगने के बाद दोनों ने कोई मदद नहीं की

कराची, आइएएनएस : स्पॉट फिक्सिंग के कारण आजीवन प्रतिबंध झेल रहे लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और देश की सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध लगने के बाद इन दोनों ने उनकी कोई मदद नहीं की।

कनेरिया ने ट्विटर पर लिखा, 'यह सच है कि मेरे कबूलनामे के बाद मुझे पाकिस्तान सरकार या बोर्ड से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला जबकि मेरी ही जैसी स्थिति से निकले अन्य खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो भी पीसीबी के समर्थन के साथ। उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने हालांकि मेरे साथ कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं पाकिस्तान के लिए पूरी ईमानदारी से खेल सका। अब यह मेरे देश की सरकार, इमरान खान, पीसीबी का मसला है, मेरा भविष्य उनके हाथ में है।' इससे पहले कनेरिया ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ खिलाड़ी पीठ पीछे उनको लेकर टिप्पणियां करते थे। करियर में 61 टेस्ट खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने स्पष्ट किया था कि पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने हमेशा उनका समर्थन किया।

इंजमाम बोले, पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा है कि जब कनेरिया उनकी कप्तानी में खेले थे तो इस तरह की बातें उनके सामने नहीं आई थीं। अख्तर ने अपने बयानों में कहा था कि पाकिस्तानी टीम में कनेरिया के साथ इसलिए सौतेला व्यवहार किया जाता था क्योंकि वह हिंदू थे इसलिए कई लोग उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे।

पूर्व कप्तान ने कहा, 'कनेरिया ने जिस कप्तान के अंडर में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला वो मैं हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि हमारी टीम में इस तरह का मुद्दा है कि कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से इसलिए भेदभाव करता है क्योंकि वह गैरमुस्लिम है। मुझे हमारी टीम में इस तरह का एक भी उदाहरण याद नहीं है। 'मैं कनेरिया की बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि हमारा दिल इतना छोटा नहीं है कि हम इस तरह की चीजें करेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है और हम हर किसी को अपना सहयोग देते हैं।

फुटबॉल डायरी

ईपीएल में वोल्वरहैंप्टन ने 3-2 से हराया, दो गोल की बढ़त लेने के बावजूद हारी गॉर्डियोला की टीम

सिटी की खिताबी जीत की उम्मीदों को फिर लगा झटका

वोल्वरहैंप्टन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शुक्रवार को देर रात हुए एक बेहद नाटकीय मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को वोल्वरहैंप्टन के खिलाफ 2-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी जहां सिटी के गोलकीपर एंडरसन को विरोधी टीम के खिलाड़ी की राह में आने की वजह से रेड कार्ड दिखाकर बाहर किया गया। इस हार के साथ ही सिटी की खिताबी की रक्षा करने की उम्मीदों को झटका लगा।

दो गोल की बढ़त लेने के बावजूद मिली इस हार के बाद सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला ने भी स्वीकार किया कि उनकी टीम की खिताबी जीत की उम्मीदें बिखरी गई हैं। खेल के 12वें मिनट में ही सिटी के गोलकीपर एंडरसन को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया। तब गॉर्डियोला ने सर्जियो अग्यूरो को बाहर बुलाकर स्थानापन्न गोलकीपर क्लाउडियो ब्रावो को मैदान में उतारा। 10 खिलाड़ियों तक सिमटने के बावजूद रहीम स्टर्लिंग (25वें व 50वें मिनट) ने दोनों हाफ में गोल करके सिटी को 2-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ में उन्हें दो बार पेनाल्टी किक पर गोल करने का मौका मिला। पहले वोल्वरहैंप्टन के गोलकीपर ने उनकी कोशिश को बेकार कर दिया लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी की मदद से दोबारा सिटी को पेनाल्टी मिली। दूसरी बार भी स्टर्लिंग की किक को रोक लिया लेकिन गेंद छिटककर स्टर्लिंग के आगे आई जिसे उन्होंने गोल में तब्दील किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत में चिप किक के जरिये सिटी को दोहरी बढ़त दिलाई।

ईपीएल में मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर एंडरसन को रेड कार्ड दिखाते मैच रेफरी। एपी

हालांकि दूसरे हाफ में सिटी की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। खेल के 55वें मिनट में एडामा ट्राओरे के गोल ने वोल्वरहैंप्टन को वापसी दिलाई। इसके बाद राउल जिमेनेज ने निर्धारित समय से आठ मिनट पहले गोल करके वोल्वरहैंप्टन को बराबरी दिलाई जबकि 89वें मिनट में मैट डोहार्टी ने गोल करके अपने घरेलू दर्शकों में उर्जा का संचार भर दिया। इंजुरी टाइम में स्टर्लिंग की फ्री किक गोल पोस्ट के ऊपरी हिस्से से लगकर पीछे चली गई और सिटी को शिकस्त झेलनी पड़ी।

गॉर्डियोला ने कहा कि हमेशा गोल को बचाया जा सकता है लेकिन कभी-कभी यह थका देता है। 10 खिलाड़ियों के साथ बचने के लिए बहुत ये सारे मिनट थे। इन्होंने 80 मिनट तक हार टालने के लिए सब कुछ किया लेकिन यह मुश्किल था। इस हार के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार सिटी अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज लिवरपूल से 14 अंक पिछड़ गया। मौजूदा सत्र में सिटी के खराब प्रदर्शन का सबसे ज्यादा फायदा वोल्वरहैंप्टन ने उठाया है। अक्टूबर में उसने सिटी को एतिहाद स्टेडियम में 2-0 से हराया था। 1960/61 के बाद पहली बार उसने सिटी के खिलाफ एक सत्र में दो जीत दर्ज की है।

एसी मिलान में लौटे इब्राहिमोविच

मिलान, एएफपी : स्टार स्ट्राइकर ज्लाटन इब्राहिमोविच इटालियन क्लब एसी मिलान में लौट आए हैं। 38 वर्षीय इब्राहिमोविच अपने करियर के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा अपनी ख्याति को एक बार फिर चरितार्थ करने की है। खराब दौर से गुजर रही एसी मिलान के साथ इब्राहिमोविच ने शुक्रवार को छह महीने का करार किया। इब्राहिमोविच के मुताबिक वह क्लब को बुरे दौर से निकालने आए हैं। स्वीडन के दिग्गज खिलाड़ी इब्राहिमोविच 2004 में जुवेंटस से जुड़े थे लेकिन 2006 में मैच फिक्सिंग प्रकरण के बाद वह इंटर मिलान से जुड़े। इसके बाद वह 2010 में एसी मिलान से पहले लोन पर जुड़े और फिर वहां के नियमित खिलाड़ी बन गए। दोबारा एसी मिलान से जुड़ने से पहले इब्राहिमोविच अमेरिकी क्लब ला गैलेक्सी के लिए खेल रहे थे। अब तक वह एसी मिलान के लिए 85 मुकाबलों में 56 गोल किए हैं।

20 प्रजाति के तीन हजार से अधिक प्रवासी परिंदे आ चुके हैं उत्तराखंड स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की विभिन्न रेंज में। अभी इनकी संख्या और बढ़ेगी। यह मार्च तक यहां प्रवास करते हैं और इस दौरान अपना परिवार भी बढ़ाते हैं।

'कैप्स्यूल गिल' के कारनामे को फिर सलाम

रविवार विशेष ▶ 1989 की घटना पर बनने जा रही बॉलीवुड फिल्म, अजय देवगन निभाएंगे किरदार

12-13 नवंबर 1989 की बात है। प. बंगाल के रानीगंज में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कोयला खदान- महावीर कोलियरी में 220 मजदूर 350 फीट नीचे काम कर रहे थे। अचानक ही खदान में पानी भरना शुरू हो गया। तब आइआइटी आइएसएम के छात्र जेएस गिल संकटमोचक बनकर आए। उन्होंने कैप्स्यूलनुमा लिफ्ट के जरिये खुद नीचे उतर 65 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। हादसे में केवल छह जानें गई। अब इस हैरतअंगेज कारनामे पर बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है। अभिनेता अजय देवगन कैप्स्यूल गिल के किरदार में आएंगे नजर। धनबाद से जागरण संवाददाता **आशीष सिंह** और **संजीव सिन्हा** की खास रिपोर्ट।

जेएस गिल (बाएं) और अजय देवगन। फाइल (सौ.-फेसबुक)

हादसे में खदान से बचकर निकले मुरली प्रसाद और उनकी पत्नी व बेटा। जागरण

13 नवंबर 1989 की तस्वीर, हादसे के बाद खदान में कैप्स्यूल से उतरने की तैयारी करते गिल। फाइल (सौ. ईसीएल)

याद है 'काला पत्थर'...

यश चोपड़ा द्वारा निर्मित 'काला पत्थर' फिल्म साल 1979 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर अभिनीत यह फिल्म भी असली घटना पर आधारित थी। यह घटना 27 दिसंबर 1975 को धनबाद की चासनाला स्थित कोयला खदान में घटी थी। हादसे में 375 मजदूरों की जल समाधि बन गई थी। इस हादसे को दुनिया की सबसे बड़े खदान हादसों में से एक माना जाता है।

आइआइटी आइएसएम (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस) के पूर्व छात्र जसवंत सिंह गिल का 26 नवंबर को गृहनगर अमृतसर में निधन हुआ है। आइएसएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर गिल की तस्वीर के साथ लिखा-1965 बैच के माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र जेएस गिल की बहादुरी पर हमें गर्व है...। गिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनपर बनने जा रही बॉलीवुड फिल्म- 'कैप्स्यूल गिल' को लेकर भी चर्चा है।

नवंबर 1989 को घटे उस हादसे के दौरान गिल ईसीएल में एजीएम के पद पर कार्यरत थे। ईसीएल परिसर में वह कैप्स्यूल स्मारक के रूप में मौजूद है, जिसके जरिए उन्होंने मौत के जबड़े में फंसे मजदूरों को खदान से सकुशल निकाला था। 1991 में गिल को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देकर सम्मानित किया था। गिल जब जीवित थे, तभी फिल्म निर्माताओं ने उनसे फिल्म बनाने को लेकर संपर्क कर लिया था और अब अजय देवगन इसे बनाने जा रहे हैं।

वे लोग जिन्हें गिल ने जीवनदान दिया, आज भी उनके प्रति आभार प्रकट करते थकते नहीं। उस समय कोलियरी के हॉलेज ऑपरेटर रहे मुरली प्रसाद ने बताया कि 12 नवंबर की रात की पाली में 220 कामगार महावीर कोलियरी में 350 फीट नीचे काम करने उतरे। कोयला उत्पादन के लिए जब विस्फोट किया गया तभी दीवार टूट गई। दूसरी ओर जल भंडार था। खदान में तेजी से पानी भरने लगा। लोग भागने लगे। डोली के निकट जो थे, वे ऊपर चले गए। तब तक खदान में पानी भर गया था। 71 श्रमिक फंस गए। इनमें छह की मौत आंखों के सामने हो गई। हम 65 लोग बचे थे। आज भी घटना की याद कलेजा कंपकपा देती है। करीब 84 घंटे हम मौत की सुरंग में पड़े रहे। गिल साहब ने हमें बचा लिया...।

मुरली ने बताया, कोलियरी में एक माह पहले आए मैनेजर घोष ने खदान में कई जगह फोन लगवाए थे। उनके तार सुरक्षित थे। फोन से ऊपर संपर्क किया तो दो किमी दूर ऊंचाई की ओर 42 नंबर सेक्शन पहुंचने को कहा गया। तब गिल साहब देवदूत बनकर कैप्स्यूल से नीचे उतरे। उन्हें देख पहले ऊपर जाने के लिए श्रमिक आपस में ही उलझने लगे।

आखिर जान किसको प्यारी नहीं होती। तब सरदार जी ने कहा कैप्स्यूल में एक बार में केवल एक आदमी जाएगा। जो बीमार है वह पहले। अंत में सरदार जी बाहर आए...। उन 65 लोगों में से एक नूर मोहम्मद और जोगिंदर पासवान ने बताया, खदान से पानी मोटर पंप से निकालकर बोर होल किया गया। हम सब जहां थे वहां बोर होल से 2.5 मीटर का लोहे के कैप्स्यूल में गिल खदान में उतरे। गिल सबके मना करने के बाद भी नीचे उतरे और सभी को छह घंटे में बाहर निकाला।

> खदान में जिस तेजी से पानी घुसा, लगा जलजला आ गया। हम समझ गए कि मौत निश्चित है। फिर भी ऊंचाई की ओर भागते गए। सभी ने तय किया कि पहले अपने कैप लैंप कमर में बांध लें। मर भी गए तो नंबर से पहचान हो जाएगी। लेकिन गिल साहब कैप्स्यूल सहित नीचे उतरे और 65 लोगों को बचाकर खुद अंत में निकले...।
>
> -मुरली, हादसे में जीवित बचे श्रमिक

'काला पत्थर' फिल्म का एक पोस्टर। सौ. यशराज फिल्म्स

कमाल के गिल...

बंगाल की कोयला खदान में अचानक भर गया था पानी, 350 फीट नीचे फंसे थे 220 मजदूर, आइआइटी आइएसएम के छात्र जेएस गिल की सूझबूझ से बची 65 की जान

26 नवंबर को अमृतसर में हुआ निधन, ट्विटर हैंडल पर आइएसएम ने दी श्रद्धांजलि

ईसीएल कार्यालय में रखा कैप्स्यूल। जागरण

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

'दादा' की अंगुली पकड़ धमाल मचाएगा क्रिकेट का 'वंडर किड'

विराट कोहली से लेकर केविन पीटरसन तक, बड़े-बड़े क्रिकेटर तीन साल के जिस उस्ताद क्रिकेटर शेख शाहिद की बल्लेबाजी के मुरीद हैं, अब दादा सौरभ गांगुली की क्रिकेट अकादमी उसे विधिवत प्रशिक्षण देकर निखारेगी। कोलकाता से जागरण संवाददाता **विशाल श्रेष्ठ**, कोलकाता की रिपोर्ट।

संडे बॉक्स
जरा हटके...

- विराट कोहली से लेकर केविन पीटरसन तक, तीन साल के शेख शाहिद की बल्लेबाजी के बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं मुरीद
- अब दादा सौरभ गांगुली की क्रिकेट अकादमी विधिवत प्रशिक्षण देकर निखारेगी 'वंडर किड' का हुनर

किसी ने सच कहा है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं। तीन साल के शेख शाहिद को ही ले लीजिए। इस बच्चे ने दो साल की उम्र में ही सचिन-विराट की तरह करारे शॉट लगाने शुरू कर दिए थे। उसकी बल्लेबाजी देख टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उसे 'अद्भुत' करार दिया, तो इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कोहली से उसे भारतीय टीम में शामिल करने की सिफारिश कर डाली। क्रिकेट का यह 'वंडर किड' इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देश-दुनिया में उसकी बल्लेबाजी की तारीफ हो रही है।

दक्षिण कोलकाता के बेहला अंचल के शकुंतला पार्क, मूचीपाड़ा में रहने वाले शाहिद के पिता शेख शमशेर ने बताया- एक दिन मैं घर में टीवी पर भारत-आस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देख रहा था। शाहिद उस वक्त दो साल का था। उसने अचानक मुझसे कहा कि उसे भी क्रिकेट खेलना है। मैंने उसे प्लास्टिक का बल्ला और गेंद लाकर दी। उसने जब शॉट लगाया तो मैं दंग रह गया। वह बिल्कुल पेशेवर क्रिकेटरों की शैली में बल्लेबाजी कर रहा था। पूछने पर कहता है कि टीवी में जैसा देखा वैसा ही किया। अगले छह महीने तक मैंने उसे घर में प्रैक्टिस कराई। ढाई साल का हुआ तो क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करने का फैसला किया।

शमशेर ने बताया, उसे लेकर गरियाहाट के पास स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल ऑफ क्रिकेट पहुंचा तो वहां इतने छोटे बच्चे को भर्ती लेने से इन्कार कर दिया गया। काफी जोर देने पर कोच ने पहले बच्चे का टेस्ट लेने की बात कही। शाहिद ने पहली ही गेंद पर इतना शानदार शॉट लगाया कि कोच दंग रह गए और तुरंत उसे भर्ती ले लिया। तब से वहीं उसका प्रशिक्षण चल रहा है।

न्यू अलीपुर इलाके के एक सैलून में काम करने वाले शमशेर ने कहा- मेरे बेटे में अद्भुत प्रतिभा है पर क्रिकेट महंगा खेल है। सैलून में पूरा दिन काम करके महीने में जो छह-आठ हजार रुपये कमाता हूं, वो परिवार चलाने में खर्च हो जाता है। कोई मदद करे तो मेरे बेटे का भविष्य संवर जाएगा। इस बीच, शाहिद को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की क्रिकेट एकेडमी से प्रशिक्षण का आश्वासन मिला है।

कोच अमित चक्रवर्ती ने बताया- हमारे यहां न्यूनतम पांच साल के बच्चे का ही दाखिला लिया जाता है। उसके पिता के काफी जोर देने पर कहा कि एक बॉल डालकर देखता हूं। शाहिद ने पहली ही गेंद पर इतना शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि मैं अवाक रह गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके 62 वर्षीय इस अनुभवी कोच ने कहा- शाहिद में विलक्षण प्रतिभा है। कोच फिलहाल शाहिद को प्लास्टिक की हार्ड गेंद और टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। शाहिद के कद के मुताबिक लकड़ी का बल्ला तक बाजार में उपलब्ध नहीं है।

विराट कोहली और शेख शाहिद की समान अंदाज में बल्लेबाजी की तस्वीर। जागरण

सौरव ने लंदन से ली शाहिद की सुध

सौरव गांगुली ने गत 15 दिसंबर को लंदन से साल्टलेक के करुणामयी इलाके में स्थित अपनी क्रिकेट एकेडमी 'वीडियोकॉन 22 यार्ड्स' के निदेशक संजय दास को फोन कर शेख शाहिद के बारे में जानकारी ली। इसके बाद संजय ने शाहिद के कोच अमित चक्रवर्ती को फोन करके कहा कि दादा नहीं चाहते कि शाहिद जैसी प्रतिभा आर्थिक तंगी के कारण खो जाए। जल्द ही उसकी स्पांसरशिप का इंतजाम उनकी क्रिकेट एकेडमी की ओर से किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर लाखों दीवाने...

तीन साल के शाहिद की बल्लेबाजी के सोशल मीडिया पर लाखों दीवाने हैं। शाहिद जब दो साल आठ महीने का था, उस वक्त पिता ने उसकी बल्लेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वह तेजी से वायरल हुआ और 91 लाख लाइक्स मिले। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर शाहिद की जमकर तारीफ की। हमवतन केविन पीटरसन ने उस वीडियो को विराट कोहली को टैग करते हुए कहा कि इस बच्चे को अपनी टीम में ले लो। इसपर विराट ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूछा कि यह बच्चा कहां से है? ये तो अद्भुत है।

घर के आंगन में बैठा शेख शाहिद। जागरण

पिता शेख शमशेर और मां सोफिया बीबी के साथ शेख शाहिद। बिमल कर्मकार

हाथ न थे, हौसले से लिख दी सफलता की कहानी

जीना इसी का नाम है

आशीष कुमार सिंह, लखनऊ

- उप्र के बाल एवं पुष्टाहार विभाग में पदस्थ कामिनी का जीवट देता है दूसरों को प्रेरणा

कोई इंसान शरीर से नहीं, बल्कि मन से दिव्यांग होता है। उप्र के बाल एवं पुष्टाहार विभाग में पदस्थ विकास अधिकारी कामिनी की कहानी इसे साबित कर रही है। चार साल की उम्र में दोनों हाथ और एक पांव की अंगुलियां गंवाने के बाद भी अटूट हौसले और जीवट के दम पर वह इस मुकाम पर हैं।

छोटी-मोटी दिक्कतों से हारकर जिंदगी को खत्म मान लेने वालों को यह कहानी जीने का नया नजरिया देती है। लखनऊ में तैनात यह अफसर स्थानीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से के अलावा कई बड़े सम्मानों से भी अलंकृत हो चुकी हैं। 1997 में आजमगढ़ निवासी स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव के साथ वैवाहिक बंधन में बंधी कामिनी कहती हैं कि सफलता के इस सफर में पति के साथ सास लीलावती, देवर राघवेंद्र कुमार और देवरानी मुग्धा का पूरा सहयोग मिला।

मूल रूप से फैजाबाद की रहने वाली कामिनी श्रीवास्तव 1962 में जन्मीं। पिता धर्मवीर श्रीवास्तव रेलवे में ड्राइवर थे। चार वर्ष की उम्र में कामिनी श्रीवास्तव रामनवमी के दिन पिता के साथ सफर के दौरान रेल इंजन की चपेट में आ गईं। दुर्घटना में दोनों हाथ और एक पैर की अंगुलियां गंवाने के बाद दो वर्ष तक इलाज चला। छह वर्ष की अवस्था में माता-पिता ने उन्हें पैरों से कलम थाम लिखना सिखाया। स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद यह नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ अर्थशास्त्र से एमए किया। वर्ष 2000 में इंदिरा महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत अध्ययन दल के साथ इंडोनेशिया भेजा गया। 1994 में उन्हें बेहतर कार्यप्रदर्शन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से पुरस्कार मिला। 2016 को मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई वीरता सम्मान दिया। इसी साल उनकी किताब- खिलते फूल महकता आंगन प्रकाशित हुई, जिसके लिए हिंदी साहित्य संस्थान उप्र से रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार मिला।

> बेहद विपरीत परिस्थिति में भी हौसला बनाए रखना चाहिए। हम हौसले से काम लें तो वह सब पा सकते हैं, जो हम चाहते हैं।
>
> -कामिनी श्रीवास्तव

पैर से लिखते हुए कामिनी।

> मैंने यह काम नि :शुल्क रखा है क्योंकि अपंग पशु की देखभाल में लोग रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे पशुओं को मदद दिलाने के लिए कृष्णा लिंब के मोबाइल नंबर 9414262637 पर संपर्क किया जा सकता है।
>
> -डॉ. तपेश माथुर, कृष्णा लिंब लैब, जयपुर

अपंग गायों को निशुल्क कृत्रिम पैर लगा रहे डॉ. माथुर

गाय को कृत्रिम पैर लगाते डॉ. माथुर। जागरण

नरेंद्र शर्मा, जयपुर : जयपुर के पशु चिकित्सक डॉ. तपेश माथुर ने देश के 12 राज्यों में अब तक 100 से अधिक अपंग गायों को पैरों पर खड़ा किया है। इसके साथ ही कई जानवरों में अंगों का प्रत्यारोपण किया है। बड़ी बात यह कि प्रत्येक गाय पर पर पैर लगाने के लिए खर्च होने वाली 15 हजार रुपये की राशि वह खुद अपने वेतन से वहन करते हैं। अपंग और असहाय पशुओं की पीड़ा से व्यथित हो डॉ. माथुर ने गायों के लिए कृत्रिम पैर खुद ही तैयार किया। इसके लिए एक लैब उन्होंने अपने में बनाई, नाम रखा कृष्णा लिंब। अब यह लैब राजस्थान ही नहीं देशभर में सराही जा रही है। अब उन्हें कुछ सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग भी देना शुरू किया है, लेकिन फिर अब भी वह वेतन से एक हिस्सा खर्च करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने को गठित केंद्रीय समिति में डॉ. तपेश माथुर को भी सदस्य बनाया गया है। उन्हें 2014 में इंडियन सोसाइटी फॉर वेटेरिनरी सर्जरी की ओर से गोल्ड मेडल और 2015 में बेस्ट फील्ड वेटेरीनेरियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

उत्तराखंड के अंतिम गांव गंगी में बह रही संपन्नता की 'प्रेरक' गंगा

मधुसूदन बहुगुणा, नई टिहरी

165 परिवारों वाले टिहरी के गांव ने कृषि व पशुपालन के जरिये पेश की मिसाल

- आलू, राजमा बेचकर कर रहे प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का कारोबार

टिहरी, उत्तराखंड स्थित सीमांत गांव गंगी के परिवार उन परिवारों में शामिल नहीं, जो सुविधाओं के अभाव में अपना गांव छोड़ पलायन कर गए। उत्तराखंड के अनेक गांव सूने होते गए। ऐसे में गंगी एक प्रतिमान स्थापित करने में सफल रहा है। कृषि, पशुपालन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बूते इन्होंने संपन्नता की सुखद तस्वीर प्रस्तुत की है।

गंगी के लोगों ने अपने पिछड़ेपन को तो दूर किया ही, अपने स्तर पर अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई दी। यहां आलू और राजमा उत्पादन से ही किसान प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का कारोबार कर रहे हैं। जबकि, हर सीजन भेड़ों से करीब 50 क्विंटल ऊन निकालते हैं। ऊन अधीक्षक चंबा एसएस बोनाल बताते हैं कि इस ऊन को उत्तराखंड खादी बोर्ड के अलावा देश के अन्य राज्य भी खरीदते हैं।

जनसंख्या नियोजन

जिला मुख्यालय नई टिहरी से 90 किमी की दूरी तय कर घनसाली-घुत्तु होते हुए भिलंगना ब्लॉक के दूरस्थ गांव गंगी पहुंचते हैं। समुद्रतल से 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे गंगी की आबादी 700 है। गांव में हर परिवार के पास 500 से लेकर एक हजार तक भेड़-बकरियां हैं। एक बकरी की कीमत उसके वजन के हिसाब से तीन से लेकर सात हजार रुपये तक होती है। ग्रामीणों के पास सामान ढोने के लिए अपने घोड़ा-खच्चर भी हैं। इन्हें केदारनाथ यात्रा में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक घोड़े की कीमत करीबी 1.25 लाख और खच्चर की करीब 70 हजार रुपये है। जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. बीएस रावत बताते हैं कि गंगी के घोड़ा-खच्चर देशी नस्ल के हैं, जो न ज्यादा बड़े होते हैं, न छोटे ही। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में इन्हीं की डिमांड है।

गंगी तक सड़क तो पहुंच गई है, लेकिन अभी इस पर छोटे वाहन भी नहीं गुजर पा रहे। सो, ग्रामीणों को आठ से दस किमी की दूरी पैदल नापनी पड़ती है। दो साल पूर्व ही गांव सौर ऊर्जा से रोशन हुआ और सभी 165 परिवार इसका उपभोग कर रहे हैं। गंगी के अधिकांश युवा 12वीं तक ही पढ़े हैं। स्नातक सिर्फ बारह हैं, लेकिन इनमें लड़कियां शामिल नहीं हैं। दरअसल, इंटर की पढ़ाई के लिए नौनिहालों को दस किमी पैदल चलकर राजकीय इंटर कॉलेज घुत्तू पहुंचना पड़ता है। जबकि, स्नातक की पढ़ाई के लिए बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल की दूरी 40 किमी है। ऐसे में लड़कियां इंटर के बाद नहीं पढ़ पातीं। जिला पर्यटन अधिकारी एसएस यादव बताते हैं कि गंगी से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंवाली कांठा व खतलिंग ग्लेशियर आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग के लिए यह जगह काफी प्रसिद्ध है।

गंगी गांव में भेड़ से ऊन निकालते ग्रामीण। जागरण

नहीं रोया कमियों का रोना...

गंगी में भोटिया नस्ल के कुत्ते भी पाले जाते हैं। इन कुत्तों की उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी डिमांड है। भोटिया कुत्ते का एक पिल्ला पांच हजार रुपये तक में बिकता है। गंगी के लोगों ने इसे भी अपनी कमाई का माध्यम बनाने में चूक नहीं की। यानी कमियों का रोना न रोकर, जो भी है उसी से नई राह बनाने का काम गंगी ने कर दिखाया है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

मनाली में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आइस हॉकी स्टेडियम

जासं, मनाली : देश के खिलाड़ियों को आइस हॉकी का प्रशिक्षण लेने के लिए अब विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश सरकार अब मनाली में अंतरराष्ट्रीय आइस हॉकी स्टेडियम बनाएगी। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में जगह का चयन किया है। स्टेडियम निर्माण के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में नीदरलैंड की कंपनी से 17 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया है। कंपनी की टीम जनवरी में मनाली आएगी। अंतरराष्ट्रीय आइस हॉकी स्टेडियम बनाने के लिए जमीन का चयन हो गया है।

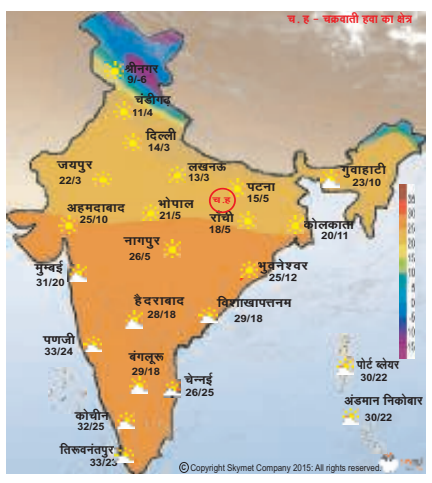

मौसम विशेष

पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। एक-दो स्थानों पर पाला जमने के आसार हैं। दिन ठंडा रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के साथ शीतलहर चलने के कारण कंपकंपाती ठंड जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/20/आंबा	अहमदाबाद	26/12/आंबा
कोलकाता	20/11/आंबा	बड़ोदा	27/12/सा
चेन्नई	30/23/आंबा	नागपुर	26/06/आंबा
हैदराबाद	28/18/आंबा	इन्दौर	24/11/आंबा
बंगलूरू	29/18/आंबा	रांची	20/11/व
त्रिवेन्द्रम	34/24/व	पटना	20/10/आंबा
गुवाहाटी	23/15/सा	जमशेदपुर	23/16/व
गंगटोक	05/-3/ आंबा	पुणे	29/19/सा

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 29 दिसंबर, 2019 से शनिवार 4 जनवरी, 2020 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, धनागम में प्रयास, कार्य में एकाग्रता, पूंजी निवेश में सावधनी, साझेदारी में तनाव, भावना की अधिकता, वाहन भवन योग, संतान से चिंतित, खानपान पर ध्यान रखें, शिक्षा में एकाग्रता, क्रोध पर नियंत्रण, शुभ अंक 9।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
व्यापार , उद्योग, नौकरी के कार्य में सफलता, अर्थ साधन में सफलता, नए कार्य का योग, विदेश से समाचार, धन के आवागमन में सावधानी, चिंता योग, भूमि भवन के कार्य में प्रगति, संतान की प्रगति, मित्रों से सावधान, शत्रु पक्ष परास्त, नये साथी का मिलन, शुभ अंक 11।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, अर्थ साधन अच्छा, नए कार्य की योजना, प्रतिस्पर्धा में सफलता, विशेष व्यक्ति का सहयोग, स्वास्थ्य में सुधार, वाहन योग, संतान से चिंतित, चयन में देरी, शत्रु पक्ष प्रभावी, व्यर्थ के कार्य से बचें, दांपत्य में तनाव, शुभ अंक 11।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
व्यापार, उद्योग, नौकरी के कार्य में सहयोग से सफलता, धनागम अच्छा, धन निवेश में सावधानी, साझेदारी में सावधानी, विदेश से समाचार, चिंता समाधान, सजावट तथा भवन का योग, संतान की प्रगति, अध्ययन में अवरोध, ईर्ष्या से बचें, जीवन साथी का मिलन, शुभ अंक 1।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में सफलता, अर्थ साधन अच्छा, कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, मन में शिथिलता, भौतिक साधनों की वृद्धि, संतान को सहयोग, चयन में सफलता, शत्रु पक्ष से सावधान, नए साथी से मिलन, अवसर के अनुसार कार्य करें, वाहन में सावधानी, शुभ अंक 2।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, नये कार्य की योजना, साझेदारी कार्य में प्रगति, विदेश व्यापार में सफलता, पारिवारिक असंतोष, भौतिक साधनों की वृद्धि, चयन में सफलता, कूटनीति से कार्य करें, ससुराल से सहयोग, एकाएक कार्य संपन्न, शुभ अंक 3।

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रगति, धनागम में सफलता, दिनचर्या में व्यस्तता, पूंजी निवेश में सावधानी, अच्छे समाचार की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुधार, भवन भूमि योग, संतान के लिये योजना, अध्ययन में एकाग्रता, शत्रु पक्ष से सावधान, कुसंग से बचें, यात्रा में सावधानी, शुभ अंक 4।

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन में सुधार, दिनचर्या व्यस्ततम, भविष्य की योजना, चिंता का योग, स्वास्थ्य में सुधार, संतान से सहयोग, चयन में अवरोध, मित्रों का सहयोग, प्रणय में मधुरता, ससुराल से सहयोग, आय में सुधार, शुभ अंक 5।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, धनागम में प्रयास, कार्य करने वालों का ध्यान रखें, पारिवारिक सुख सहयोग, संतान की प्रगति, शिक्षा में सफलता, वाद विवाद से बचें, निर्णय में देरी न लगायें, प्रणय में मधुरता, अनुबंध की प्राप्ति, व्यय अधिक, शुभ अंक 6।

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन में प्रयास करें, कार्यशैली में सुधार, निर्णय सलाह से करें, प्रतिस्पर्धा में सफलता, विशेष व्यक्ति से मिलन सहयोग, चिंता का योग, भौतिक साधनों की पूर्ति, मित्रों से विरोध, प्रणय में तनाव, यात्रा में कठिनाई, शुभ अंक 6।

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, धनागम में प्रयास करें, निर्णय सलाह से करें, धन के आवागमन में सावधानी, मन में चिंता से स्वास्थ्य कमजोर, वाहन सजावट योग, व्यर्थ के कार्य से बचें, दाम्पत्य सुख, वाहन में सावधानी, राजनैतिक कार्य में प्रगति, शुभ अंक 8।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रगति, अर्थ साधन में प्रयास सफल, कार्यशैली में सुधार, विशेष व्यक्ति से लाभ, विदेश से समाचार, चिंता की समाप्ति, चयन में सफलता, मित्रों से सावधान, नये साथी का मिलन, वाहन में सावधानी, शासन के कार्य में प्रगति, शुभ अंक 9।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

रविवार 29 दिसंबर 2019

आजकल

16

www.jagran.com

विजयंत टैंक भारतीय सेना का अंग बना

आज ही के दिन 1965 में पहली बार विजयंत टैंक सेवा में आया। टैंक का प्रोटोटाइप 1963 में सामने आया था। पहली बार इसका निर्माण ब्रिटेन में किया गया। 1971 के युद्ध में विजयंत का अभूतपूर्व योगदान रहा। अब तक इसे कई बार अपडेट किया जा चुका है।

अल्लामा इकबाल ने पेश किया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत

मुहम्मद इकबाल ने आज ही के दिन 1930 में मुसलमानों के लिए देश के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक अलग स्वशासित इकाई बनाने की मांग की थी। इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने यह बात कही थी। जिसे बाद में द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहा गया।

आनंद के सफर का बेहतरीन अंदाज राजेश खन्ना

आज ही 1942 में बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर में हुआ था। 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कांटेस्ट जीता। बॉलीवुड में पहली फिल्म 1966 में आई आखिरी खत थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे। तीन बार फिल्मफेयर मिला। फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहब फाल्के गोल्डन एक्टर अवॉर्ड और पद्मभूषण से भी सम्मानित हुए। मुमताज के साथ आई उनकी सभी 8 फिल्में सुपरहिट रहीं। जीवन में उन्होंने 180 फिल्में की। वे दिल्ली से लोकसभा सांसद भी रहे। 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

एक झटके में खत्म हो गई परेशानी

न्यूयॉर्क, एजेंसी : मैरीलैंड की एक महिला की परेशानी एक झटके में खत्म हो गई जब उसकी 50 हजार डॉलर (करीब 35 लाख 71 हजार रुपये) की लॉटरी लग गई। महिला हर क्रिसमस पर अपने दोस्तों को उपहार में देने के लिए लॉटरी टिकट खरीदती थी। इस बार उसने अपने पति के लिए भी टिकट खरीदा। टैलबोट काउंटी की 51 वर्षीय महिला डियार्डे स्टोक्स ने कहा कि मैंने कई टिकट खरीदे थे लेकिन यह शानदार किस्मत थी कि सुपर कैश का टिकट मेरे पति के ही हाथ लगा। उनके पति 50,000 सुपर कैश स्क्रैच ऑफर के शीर्ष पुरस्कार 50,000 डॉलर के विजेता बने। उन्होंने कहा कि जब मेरे पति ने इसे स्क्रैच किया और कहा कि हम 50,000 डॉलर जीत चुके हैं तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हालांकि फिर उनकी बात सही साबित हुई। स्टोक्स ने कहा कि जैकपॉट उनके परिवार को आर्थिक परेशानी से उबरने में मदद करेगा।

शोध अनुसंधान

जीन थेरेपी की मदद से गंभीर बीमारी के इलाज की उम्मीद

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने जीन साइलेंसिंग थेरेपी की मदद से एएलएस जैसी गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। एएलएस यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है। इससे दिमाग की नर्व कोशिकाएं व मेरुदंड पर दुष्प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति की सीखने-समझने की क्षमता कम हो जाती है। पहले के अध्ययनों में सामने आया है कि करीब 200 जीन म्यूटेशन इससे जुड़े होते हैं। चूहे पर किए गए प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने एक वायरस की मदद से जीन साइलेंसिंग आरएनए को शरीर में पहुंचाया। इस आरएनए ने एएलएस से जुड़े विशेष जीन म्यूटेशन को निष्क्रिय कर दिया। अगर बीमारी के लक्षण सामने आने से पहले यह इलाज दिया जा सके तो न्यूरॉन्स को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। - एएनआइ

आंतों के कैंसर से जुड़े अहम प्रोटीन की पहचान हुई

वैज्ञानिकों ने आंतों से संबंधित कैंसर के प्रसार में मददगार बनने वाले प्रोटीन की पहचान की है। हालिया अध्ययन में सामने आया है कि इंपोर्टिन-11 नाम का प्रोटीन कैंसर का कारण बनने वाले कैटेनिन प्रोटीन को कोलन कैंसर की कोशिकाओं के केंद्र तक लेकर जाती है। अगर इस कड़ी को रोक दिया जाए, तो आंतों के कैंसर के प्रसार को रोकना संभव हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर के 80 फीसद मामले एपीसी जीन के म्यूटेशन से जुड़े होते हैं, जिसमें कैटेनिन प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। अगर इंपोर्टिन-11 को निशाना बनाकर कैटेनिन को कोशिकाओं के केंद्र तक पहुंचने से रोका जा सके, तो बीमारी का प्रसार भी रुक सकता है। - एएनआइ

हड्डियों के फ्रैक्चर का इलाज होगा आसान

जागरण संवाददाता, रुड़की

- आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया बायो रीएब्जॉर्बेबल ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट
- कम हो जाएगा बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा

अन्य तरीकों के मुकाबले किफायती भी है नई तकनीक। प्रतीकात्मक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के शोधकर्ताओं ने हड्डियों के फ्रैक्चर के इलाज के लिए कृत्रिम बायो रीएब्जार्बेबल और किफायती ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट विकसित किया है। इसकी मदद से फ्रैक्चर होने पर संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सकेगा।

आइआइटी रुड़की के बायो टेक्नोलॉजी विभाग के शोधकर्ता सारीम खान ने बताया कि वर्तमान में हड्डियों के इलाज में ग्राफ्ट वाले हिस्से में बैक्टीरिया का संक्रमण एक आम समस्या रहती है। इससे हड्डियों के अलग-अलग हिस्सों के जुड़ने में दिक्कत आती है और शुरुआती ग्राफ्ट को निकालने या संक्रमण मुक्त करने के लिए दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। पर अब एक अधिक सक्षम बैक्टीरिया रोधी मेम्ब्रेन की मदद से बेहतर उपचार की संभावना बनी है। हड्डी दोबारा बनने की इस प्रक्रिया में मैकेनिकल पावर और ऑस्टियोकंडक्टिविटी भी बढ़ेगी।

उन्होंने बताया कि यह अधिक सक्षम बैक्टीरिया रोधी मेम्ब्रेन ऑपरेशन के बाद बैक्टीरिया के संक्रमण से खुद लड़ेगा। इसके लिए किसी उपचार या सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। इसलिए इलाज का खर्च और स्वस्थ होने में समय कम लगेगा। मेम्ब्रेन एक दीवार बन कर हड्डी को मूल आकार में कायम रखेगा। इससे संबंधित हड्डी एवं आसपास के कोमल टिश्यू के अनावश्यक चिपकने का खतरा नहीं रहेगा। शोधकर्ता ने बताया कि इस संबंध में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलीक्यूल्स और आरएससी एडवांसेज में दो अध्ययन प्रकाशित हुए हैं।

ऐसे तैयार किया मेम्ब्रेन : इस अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि चिटोसन मैट्रिक्स में उचित मात्रा में कुदरती क्ले मिनरल (हैलोसाइट) मिलाने से बायो रीएब्जॉर्बेबल मेम्ब्रेन बनता है। जो मनुष्य में टिश्यू के दोबारा बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। अध्ययन में बताया गया है कि यह मेम्ब्रेन हड्डी के दोबारा बनने के दृष्टिकोण से ऑस्टियोब्लास्ट (हड्डी के सेल) के लिए बहुत अनुकूल है। इस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया से लड़ने की ज्यादा शक्ति है। इसलिए ऑपरेशन के बाद संक्रमण का खतरा भी कम होगा। इन गुणों के अतिरिक्त इस मेम्ब्रेन में 67 एमपीए का ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ और अधिक लचीलापन भी है।

होगा किफायती उपचार : मेटल के प्रचलित स्टेंट और प्लेट के बदले ये मेम्ब्रेन लगाए जा सकते हैं। जो उनसे 300 गुना सस्ता भी है और स्टेंट एवं प्लेट की तरह इस मेम्ब्रेन को निकालने के लिए दूसरी बार सर्जरी की भी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मेम्ब्रेन बायो रीएब्जॉर्बेबल है। वहीं यह मेम्ब्रेन प्रचलित ग्राफ्ट की कई समस्याएं दूर करेगा।

अब 'काई पावर' से भी चलेंगी बाइक और कार

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ

स्पेक्ट्रम

- वीबीएयू के पर्यावरण विभाग के शोध छात्र का प्रयास रंग लाया
- शैवाल से बायोडीजल बनाने में मिली सफलता

तालाब और नालों के पानी पर जमी शैवाल (काई) तो आपने देखी ही होगी। जमीन पर जमी काई पर आप हो सकता है फिसले भी हों, लेकिन उसी काई के पावर से अब गाड़ियां दौड़ेंगी। काई से बनने वाला बायोडीजल बाइक और कार में ईंधन का काम करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के शोध छात्र रंजन सिंह ने काई से बायोडीजल बनाने में सफलता हासिल की है।

रंजन बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या बन चुका है। इस दिशा में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर सार्थक परिणाम आने का सभी को इंतजार है। इसी दिशा में उन्होंने प्रदूषित जल में पाए जाने वाले कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व पर काम किया, जिसमें यह बात सामने आई कि तालाब व नालों के किनारे पैदा होने वाली काई हानिकारक अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों को भोजन के रूप में अवशोषित करती है। इससे शैवाल का जैवभार बायोमास में बढ़ जाता है। इसमें लगभग दस से 15 दिन का समय लगता है। इस अवधि के बाद शैवाल को निकाल कर ट्रांस एस्टीरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारना होता है। प्रक्रिया के तहत कुछ केमिकल भी प्रयोग किए जाते हैं, जिसके बाद वह बायोडीजल में परिवर्तित हो जाता है। रंजन कहते हैं कि यह बायोडीजल पर्यावरण के अनुकूल है, जिसका इस्तेमाल कार, बाइक आदि मोटर व्हीकल में किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं है। रंजन का यह शोध बायो रिसोर्स टेक्नोलाजी जर्नल में हाल में ही प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा इसी शोध के बाद रंजन को साउथ चाइना एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए ऑफर मिला है।

अपनी लैब में शोध करते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के छात्र रंजन सिंह। जागरण

क्या है प्रक्रिया : इसके तहत शैवाल को गर्म करते हैं, फिर तेज गति से उसे ठंडा करते हैं, जिससे उस शैवाल से लिपिड (वसा) निकलता है। इस वसा को ट्रांस स्टीरीफिकेशन (ब्वॉयलर) प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है।

कितनी काई से कितना ईंधन : रंजन के मुताबिक, काई में अवशोषित अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों के आधार पर इसकी मात्रा तय होती है। साफ सुथरे तालाब की काई उतनी कारगर नहीं होगी। एक हजार मिली काई से 20 मिली बायोमास और उसी आधार पर ईंधन प्राप्त होगा।

मंगल पर जीवन तलाशेगा नासा का रोवर

अभियान ▶ अगले साल लाल ग्रह के सफर पर रवाना होगा 'मार्स 2020'

भावी मानव मिशन का मार्ग प्रशस्त करना भी है मकसद

पासाडेना, प्रेट्र : अगले साल मंगल की यात्रा पर जाने वाला नासा का मार्स 2020 रोवर लाल ग्रह पर न केवल जीवन की संभावना खोजेगा बल्कि भावी मानव मिशन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने रोवर का अनावरण करते हुए शुक्रवार को यह बात कही। इस रोवर को लॉस एंजिलिस के पास पासाडेना में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के विशाल कक्ष में तैयार किया गया है, जहां इसके चालक उपकरण का पिछले हफ्ते सफल परीक्षण किया गया।

यह रोवर जुलाई 2020 में फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से रवाना होगा और सात महीने बाद फरवरी 2021 में यह मंगल ग्रह पर उतरेगा। इसी के साथ यह लाल ग्रह पर उतरने वाला पांचवां अमेरिकी रोवर बन जाएगा। मिशन के उप प्रमुख मैट वैलेस ने कहा, 'इसे मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, इसलिए हम इसके साथ विभिन्न उपकरण भेज रहे हैं, जो मंगल की सतह पर भौगोलिक एवं रसायनिक संदर्भों को समझने में मदद प्रदान करेंगे।'

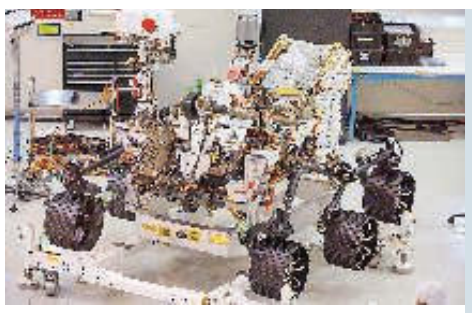

अमेरिका में लॉस एंजिलिस के पास पासाडेना में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के कक्ष में तैयार किया गया मार्स 2020 रोवर। एएफपी

लगाए गए उन्नत उपकरण : रोवर में जो उपकरण लगाए गए हैं, उनमें 23 कैमरे, मंगल ग्रह की हवाओं को सुनने के लिए दो श्रवण यंत्र और रसायनिक विश्लेषणों के लिए लेजर शामिल हैं। पूर्व में भेजे गए रोवर की तरह इस रोवर में भी छह पहिये लगे हैं, जिसके चलते चट्टानी इलाकों में चलने में इसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार के आकार वाले रोवर के लिए गति कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह के एक दिन में इसे मात्र 200 वर्ग गज की दूरी तय करनी है। बता दें कि मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। चलने के दौरान ईंधन की दिक्कतों का दूर करने के लिए इसमें एक सूक्ष्म परमाणु रिएक्टर लगाया गया है। रोवर में सात फुट लंबी भुजाएं (रोबोटिक आर्म) हैं, जो चट्टानों को खोदकर नमूने निकालने में सक्षम हैं।

लाल ग्रह और पृथ्वी में थी समानता : वैलेस ने बताया, 'हम प्राचीन जीवन की तलाश कर रहे हैं...यानी हम मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पूर्व की उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं,जब यह ग्रह पृथ्वी की तरह था।' उन्होंने बताया कि तब इस लाल ग्रह की सतह पर गर्म पानी, स्थूल वातावरण और इसके चारों ओर चुंबकीय बल था और यह काफी कुछ यहां पृथ्वी पर विकसित हुए साधारण कोशिकीय जीवन की तरह था।'

डेल्टा क्षेत्र में उतरेगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का रोवर

प्राचीन जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए मार्स 2020 लंबे सूखे डेल्टा क्षेत्र जेजेरो में उतरेगा, ताकि मिशन की सफलता की संभावना अधिक-से-अधिक हो। इस क्षेत्र का चयन वर्षों तक वैज्ञानिक चर्चाओं के बाद किया गया है। यह इलाका एक ऐसा क्रेटर है,जो कभी 500 यार्ड की गहरी झील थी। यह पहले उन नदियों के जाल से जुड़ी हुई थी, जो लगभग 3 .5 से 3 .9 अरब वर्ष पूर्व बहा करती थीं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि क्रेटर में प्राचीन जैविक अणु सुरक्षित हो सकते हैं। बता दें कि चीन ने भी अपने मंगल मिशन की दिशा बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक को लांच किया था। हालांकि, नासा का यह मिशन मंगल ग्रह के कम-से-कम एक वर्ष तक सक्रिय रहेगा, जो धरती पर लगभग दो वर्ष के बराबर है।

संक्रमण से बचाएगी नई हर्बल दवा

बरेली, आइएएनएस : भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) व राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआइ) लखनऊ ने पालतू जानवरों को संक्रमित करने वाले टिक्स और माइट्स (छोटे कीट) को नियंत्रित करने के लिए हर्बल एसारिसाइड विकसित किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह दवा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना के तहत तैयार की गई है। आइवीआरआइ के निदेशक आरके सिंह के अनुसार, कीटों का मारने के लिए यह कीटनाशक 85 फीसद प्रभावी पाया गया है। दुधारु पशु यदि इन छोटे कीटों से संक्रमित रहते हैं तो इसका प्रभाव उनके शरीर के साथ-साथ डेयरी उत्पादों पर भी पड़ता है।

यहां एक-दूसरे पर आटा और अंडा फेंककर लड़ते हैं युद्ध

आटे और अंडे से आप खाने के संदर्भ में ही परिचित होंगे। लेकिन स्पेन में यह लड़ाई में भी इस्तेमाल होता है। दरअसल, यहां के इबी कस्बे के निवासियों द्वारा प्रतिवर्ष 'एल्स एनफर्निट्स' नाम का उत्सव मनाया जाता है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग सैन्य परिधानों में एक-दूसरे पर आटे और अंडे से हमला करते हैं। पटाखे भी इसका हिस्सा होते हैं। यह करीब दो सौ साल पुराना पारंपरिक मनोरंजक उत्सव है, जो कि ईसाई त्योहार 'डे ऑफ इनोसेंट्स' के तहत प्रतिवर्ष 28 दिसंबर को मनाया जाता है। एएफपी

13 दिन में पार किया ड्रेक पैसेज

दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक ड्रेक पैसेज (जलमार्ग) को एक नाव के जरिये पार करते एथलीट कॉलिन ओ ब्राडी और उनकी टीम। ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीपों के बीच की जगह है। इसे पार करना बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन ब्राडी की टीम ने इसे 13 दिनों में पार कर रिकॉर्ड बनाया है। एपी

स्क्रीन शॉट

दक्षिण अफ्रीका में नए साल का जश्न मनाएंगे अक्षय कुमार

हिंदी सिनेमा के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं अक्षय कुमार। इस साल उनकी चार फिल्में 'केसरी', 'मिशन मंगल', 'हाउसफुल 4' और 'गुड न्यूज' रिलीज हुई हैं। आगे उनके खाते में छह फिल्में और हैं, जिनकी शूटिंग उन्हें पूरी करनी है। इतनी व्यस्तता के बावजूद वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए समय निकाल लेते हैं। कुछ समय पहले परिवार के साथ पुणे से छुट्टियां मनाकर लौटे अक्षय नए साल का जश्न मनाने पूरे परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'गुड न्यूज' को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग मिली है।

फिल्म ने पहले दिन करीब 17.56 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म की सफलता पर को लेकर अक्षय कहते हैं कि वह अपनी फिल्मों की सफलता का जश्न नहीं मनाते हैं। अक्षय के मुताबिक हर साल उनकी चार-पांच फिल्में रिलीज होती हैं। एक फिल्म रिलीज होने के दो महीने बाद ही दूसरी बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे में समझना मुश्किल होता है कि किस फिल्म के लिए जश्न मनाया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि 'गुड न्यूज' रिलीज होने के कुछ महीनों बाद ही 'सूर्यवंशी' रिलीज होगी। अक्षय ने यह भी बताया कि फिल्मों की असफलता का उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। किसी फिल्म के असफल होने पर वह सप्ताह के सिर्फ तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक उसके प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं, उसके बाद वह अगली फिल्म की तैयारी में जुट जाते हैं। अक्षय की आगामी फिल्म 'सूर्यवंशी' है, जो अगले साल 27 अप्रैल को रिलीज होगी।

फैन का दिया पेन संभालकर रखा है पुलकित सम्राट ने

अभिनेता पुलकित सम्राट आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पुलकित की इस साल 'पागलपंती' फिल्म रिलीज हुई थी। बात की जाए उनके बर्थडे पार्टी की तो पुलकित जन्मदिन पर कोई बड़ी पार्टी नहीं करने वाले हैं। अपनी बर्थडे पार्टी को वह बेहद निजी रखेंगे। मुंबई में वह अपने परिवार और कुछ खास दोस्तों के साथ ही जन्मदिन मनाएंगे। पुलकित का कहना है कि यह साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहा है। काम ने उन्हें पूरे साल व्यस्त रखा। इस साल उन्हें दुनिया घूमने का भी मौका मिला। जन्मदिन को लेकर पुलकित कहते है कि हर साल वह अपने जन्मदिन पर केवल आराम करना पसंद करते हैं। इस साल भी बेहद साधारण तरीके से वह अपना जन्मदिन मनाएंगे। अब तक के सबसे प्यारे तोहफे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी एक फैन ने उन्हें एक पेन गिफ्ट किया था, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था। वह पहला ऐसा गिफ्ट था, जो उन्हें किसी फैन की तरफ से मिला था। वह पेन पुलकित ने आज तक संभालकर रखा है। पुलकित सम्राट की आने वाली फिल्म 'तैश' होगी। इस फिल्म का निर्देशन बिजॉय नाम्बियार ने किया है।

बचपन में शाह रुख खान बनती थीं रुखसार

विक्की कौशल के भाई सनी कौशल अभिनीत फिल्म 'भांगड़ा पा ले' अगले वर्ष रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। इस फिल्म से साउथ की एक्ट्रेस रुखसार ढिल्लन हिंदी सिनेमा में कदम रखेंगी। फिल्म का शीर्षक 'भांगड़ा पा ले' सलमान खान और शाह रुख खान की फिल्म 'करण अर्जुन' के गाने की याद दिलाता है। रुखसार बताती हैं कि वह शाह रुख खान की बहुत बड़ी फैन हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं। रुखसार ने बताया कि जब वह छोटी थीं, टॉम ब्वॉय जैसी थीं। उनके पापा हर वीकेंड पर उनका और उनकी बहन का एक डांस वीडियो शूट करते थे। डांस की तैयारी रुखसार और उनकी बहन पूरे हफ्ते करती थीं। वह बताती हैं कि 'कुछ कुछ होता है' फिल्म का उन पर काफी प्रभाव रहा है। इस फिल्म के गाने 'ये लड़का है दीवाना...' पर वह और उनकी बहन डांस किया करते थे। गाने में वह हमेशा शाह रुख खान बनती थीं, जबकि उनकी बहन काजोल बनती थीं। फिल्म में भांगड़ा डांस को लेकर रुखसार कहती हैं, 'मैं भी पंजाबी हूं। जहां तक भांगड़ा डांस करने की बात है, तो शादियों और घर के फंक्शन्स में तो हमने बहुत डांस किया है, लेकिन फिल्म में चूंकि शुद्ध भांगड़ा दिखाया गया है, इसलिए कैंची चलाना और दूसरे डांस स्टेप्स मुझे सीखने पड़े। लगभग तीन महीने की डांस की ट्रेनिंग के बाद ही हमने भांगड़ा किया है।'

स्विट्जरलैंड की वादियों में फन टाइम

वर्ष 2019 को अलविदा कहने का वक्त करीब है। अक्सर साल के अंत में सितारे छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाते हैं। सैफ अली खान भी परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में वक्त बिता रहे हैं। करीना कपूर खान और तैमूर के साथ करीना की बहन करिश्मा भी हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली करिश्मा ने स्विट्जरलैंड से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। पूरा परिवार वहां पड़ रही बर्फ का लुत्फ उठा रहा है। तस्वीर में सैफ और तैमूर बीच में खड़े हैं और उनके एक तरफ करीना और दूसरी तरफ करिश्मा हैं। करिश्मा ने इस तस्वीर के साथ लिखा, 'सब गुड न्यूज है।'

अध्ययन

द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित शोध में किया गया दावा, मोटापा और मधुमेह से जुड़े जोखिम को भी करता है कम

फिटनेस के लिए फायदेमंद है इंटरमिटेंट फास्टिंग

वाशिंगटन, प्रेट्र : उपवास करने के कई फायदे होते हैं। इससे कई रोगों का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंटरमिटेंट फास्टिंग (एक निश्चित अवधि में स्वैच्छिक उपवास और गैर-उपवास के बीच का चक्र) के वैज्ञानिक और क्लीनिकल (नैदानिक) फायदों का पता लगाया है, जो चिकित्सकों को रोगियों की फिटनेस बनाए रखने के लिए नई तरीकों पर काम करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि इस तरह का उपवास स्वस्थ जीवनशैली का संकेत देता है। 25 वर्षों तक के अध्ययन बाद न्यूरोसाइंटिस्ट मार्क मैट्सन ने अपने शोध पत्र में बताया कि खाने के बीच का अंतराल और उपवास कोशिकीय स्वास्थ्य में सहयोग करता है। ऐसा भोजन की कमी की स्थितियों में खुद को ढालने के कारण भी हो सकता है, जिसे हम मेटाबोलिक (चयापचय) स्विचिंग कहते हैं। इस तरह की स्विचिंग तब होती है, जब कोशिकाएं तेजी से शुगर आधारित ऊर्जा के भंडारण को खत्म कर देती हैं और फिर वसा को धीमी चयापचय प्रक्रिया की ऊर्जा में बदल देती है। अध्ययनों ने साबित किया है कि इस तरह के बदलाव तनाव के प्रतिरोध को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के विनियमन में सुधार लाते हैं और जलन को कम करते हैं।

प्रतीकात्मक

मैट्सन ने अपने लेख में बताया है, जानवरों और इंसानों पर किए गए चार अध्ययनों में पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) और ब्लड लिपिड लेवल कम करता है। साथ ही इससे हृदय की गति को भी आराम मिलता है।

मैट्सन ने कहा, 'इसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मोटापा और मधुमेह से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है।' मैट्सन के अनुसार, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। शरीर को इंटरमिटेंट फास्टिंग को समायोजित करने और शुरुआती भूख के कष्ट तथा चिड़चिड़ेपन से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है। उन्होंने बताया, 'मरीजों को सलाह दी जाती है कि शुरुआत में भूख लगना और चिड़चिड़ापन आम बात है और इससे निजात पाने में दो सप्ताह से एक महीने का समय लगता है। उसके बाद मस्तिष्क इस नई आदत का अभ्यस्त हो जाता है।'

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग : इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लोकप्रिय स्वास्थ्य और फिटनेस प्रवृत्ति है। इसमें खाने के पैटर्न और खाने की अवधि के बीच का चक्र शामिल होता है। यह आपको यह नहीं बताता है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन यह जरूर बताता है कि आपको कब और कैसे खाना है। इसमें आप पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी यूं ही नहीं खा सकते हैं।